Page No 1

राजस्थान विधान सभा

सोलहवीं बैठक, मंगलवार, दिनांक २० मार्च, सन् १६५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ११ बजकर ६ मिनट पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्षः प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १६१

इन्सपेक्टर ऑफ स्कूलस किशनगढ़ के आधीन अध्ययापकों के फिक्सेशन के विचाधारीन मामले

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) इन्सपेक्टर ऑफ स्कूलस किशनगढ़ के मातहत कुल कितने अध्यापकों के फिक्सेशन के मामले पेडिंग है ?

(ख) उक्त कार्यालय में अध्यापकों के फिक्सेशन के १ जनवरी १६५५ को कितने मामले पोडिंग थे और उनमें से कितने फैसले किये जा चुके हैं ?

(ग) १ फरवरी १६५६ को किन किन अध्यापकों के फिक्सेशन के मामले पोडिंग थे तथा उनके अभी तक पेडिंग रखे जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप शिक्षा मंत्राणी)—(क) ८२ के।

(ख) ८२ के।

Page No 2

[श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल]

(ग) एक भी नहीं ।

(घ) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ङ०) फिक्सेशन के मामलों को तय करने के लिये एक कमेटी नियुक्त की गयी थी । इस कमेटी ने जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है । उसकी रिपोर्ट पर अध्यापकों को फिक्सेशन में कुछ कन्सेशस देने के लिए सरकार के आदेश जारी किये हैं जो कि निरीक्षणों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये भेज दिये गये हैं । आशा है कि अब फिक्सेशन कार्य माह अप्रेल के आखिर तक पूरा हो जायगा ।

कृपया परिशिष्ट १ देखिये

(प्रश्न में (घ) व (ङ) भाग नहीं हैं फिर भी उत्तर पढ़ा गया)

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष । मेरी पहली शिकायत यह है कि सूची मेज पर रख दी गई है । इस संबंध में कई बार आदेश हो चुका है, कि नोटिस ऑफिस से प्राप्त कर ली जावे । मैंने आज भी यहां आने से पहले नोटिस रूम में पता लगाया तो कोई सूची नहीं मिली । इसलिये आपसे निवेदन है कि इसका निश्चय रूप से कोई न कोई इलाज हो जावे, ताकि इसकी कोई शिकायत न रहे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया(मुख्य मंत्री)— मैं समझता हूं कि सारी सूची पढ़ दी जाय जो आपको नहीं पहुँची है ।

श्री अध्यक्ष—अब दे दीजिये ।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैं पढ़ कर सुना देती हूं, मगर यह काफी लंबी है ।

श्री चांदमल मेहता—अब दे दीजिये ।

अब तक दो तीन बार आश्वासन देने पर भी इस प्रकार की ढिलाई क्यों की गई ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—ढिलाई नहीं की गई । इसके लिये बराबर कोशिश की जा रही है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार के यह भी ध्यान में है कि इस सेशन के पहले सेशन में यह आश्वासन दिया गया था कि अगले सेशन में इनको तय कर दिया जावेगा ।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इरादा था कि पूरा हो जायगा ।

Page No 3

श्री चांदमल मेहता—जिस तरह का इरादा किया उसमें देरी होने का क्या कारण है।

श्रीमती कमलाकुमारी-बेनीवालकारण तो यह है कि सब रिपोर्ट इकट्ठी करने में देर हो सकती है और इससे यह कोई नहीं कह सकता कि लापरवाही की गई हो या काम में ढ़िलाई है ?
ऐसी बात नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सच है कि अध्यापकों के फिक्सेशन के बारे में ढ़िलाई हो रही है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही हैं कि इससे नये अध्यापकों को ऊंचे ग्रेड मिल गये और पुराने उसी ग्रेड में हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी वेनीवाल—ऐसी बात नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कि ऐसी बात इस वर्ष भी हुई है ?

श्रीमतीकमला कुमारी बेनीवाल—फिक्सेशन की ढिलाई के कारण कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ के अध्यापकों ने अपर ग्रेड की मांग की कि दूसरे अपर ग्रेड में रख लिए गये हैं, उनको भी रखा जावे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया —आप का मतलब है कि नये अध्यापकों को हायर ग्रेड में लिया जाता है, यह हो सकता है। इसका कारण यह कि इनको टेम्परेरी तौर पर तो लगाया जाता है, उन लोगों की जगह जो लोग ट्रेनिंग के लिये कहीं चले जाते हैं। जहां तक प्रोमोशन का मतलब है वो तो यह है कि नीचे तो टेम्परेरी अपोइन्टमेंन्ट करने होंगे। इस ख्याल से कि टेम्परेरी पोस्ट खाली होती हैं, उस जगह नये लोगों को लगाया जाता है। परमानेन्ट प्रोमोशन का सवाल तो सीनियोरिटी के आधार पर तय होता है।

श्री चांदमल मेहता—परमानेन्ट पोस्टिंग है उसके लिये जो नयी नियुक्तियां होती हैं वे हायर ग्रेड में होती है। पचासों ऐसे अध्यापक रह जाते हैं जिनको सर्विस करते काफी अर्सा हो गया, किंतु हायर ग्रेड नहीं मिल रहा है।

श्रीमोहनलाल सुखाड़िया—इससे उनको सीनियरोटी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, जब कोइ किसी जगह फिक्स नहीं। अभी तक रूल्स बनाये जा रहे हैं उसके अनुसार फिक्सेशन होने के बाद ही प्रोमोशन का सवाल आता है उसके बाद इस प्रकार के केजेस हो सकते हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि भूतपूर्व राजस्थान में अध्यापकों के संबंध में पिछले वर्ष में गवर्नमेंन्ट ने एक कमेटी नियुक्त की थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे याद नहीं ?

प्रश्न संख्या १६२

राजस्थान में राष्ट्रीयकरण की गई पुस्तकों का प्रकाशन

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न के उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में राष्ट्रीयकरण की गई कौन कौन सी पुस्तकें कब कब से प्रचलित है ?

(ख) उक्त पुस्तकों में किस किस में कितने कितने पेज हैं ?

(ग) किस किस पुस्तक का कितना कितना लागत मूल्य है ?

(घ) किस किस पुस्तक का क्या क्या मूल्य रखा गया है ?

(ङ) उक्त पुस्तकों के क्रय विक्रय से पिछले २ वर्षों में सरकार को कितनी कितनी आमदनी हुई है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप-शिक्षा-मंत्राणी)—(क) जुलाई १९५४ से प्रचलित है। इसकी सूची सदस्य महोदय की जानकारी के लिये सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) ख, ग एवं घप्रश्न भाग में पूछी गयी सूचना सदन की मेज पर रखी गयी तालिका में दे दी गयी है।

(ङ) सन् १९५४,५५ व १९५५,५६ में कुल बिक्री १,१४,२१९ रु० १ की हुई इसमें कुल फायदा जो सरकार को हुआ, वह सही नहीं बताया जा सकता क्योंकि अभी तक लेखकों की रायल्टी और प्रेस के नये एडीशन के बिल आदि चुकाने बाकी हैं।

श्री चांदमल मेहता—पहली तो मेरी शिकायत अध्यक्ष महोदय, यही है कि मुझे सूची नहीं मिली है।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—आपकी जानकारी के लिये सूची पढ़ देती हूं।

नाम पुस्तक	कक्षा	पृष्ठ संख्या	लागत मूल्य आ०	पा०	मूल्य
सरल विज्ञान	६	१२४	७	७	८ आना
सरल विज्ञान	७	११२	७	५	,, ,,
सरल विज्ञान	८	१०४	६	८	,, ,,
आधुनिक सामान्य विज्ञान	६	१०८	७	५	,, ,,
आधुनिक सामान्य विज्ञान	७	१२०	७	७	,, ,,
,, ,,	८	१२२	७		,, ,,
सामाजिक विज्ञान	७	१७२	१०	६	१५ आ. ६ पा.
आदर्श ललित कला	६	३४	११		१३ आ. ३ पा.
,, ,,	७	३६	११	५	१४ आ.
,, ,,	८	३८	१२	७	१४ आ. ६ पा.
राजस्थान रीडर	६	६७	६	६	६ आ. ३ पा.
संगीत चन्द्रिका	६	५४	४	३	५ आ. ६ पा.
,, ,,	७	५८	४	६	८ आ. ३ पा.
,, ,,	८	६६	५		६ आ. ६ पा.

श्री चांदमल मेहता—पुस्तकों की लागत से कितना अधिक प्रोफिट रखा जा सकता है, इस संबन्ध में सरकार ने कोई नियम बना रखे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—प्रोफिट के लिये कोई नियम नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इस संबन्ध में नियम बनाने का विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह जो किताबों के लिये नेशनेलाइजेशन का बोर्ड कायम हुआ है यह उसकी सिफारिश पर निर्भर है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह भी सही है कि कुछ पुस्तकों पर ४० से ५० प्रतिशत तक प्रोफिट लिया जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—अभी जो सूची पढ़ कर सुनायी गयी है उससे क्या माननीय मुख्य मंत्री के जानकारी में नहीं आया कि ४० से ५० प्रतिशत तक प्रोफिट है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—मेरे ख्याल से जितनी भी टैक्स्ट बुक्स प्रेसक्राइब की गई हैं उन पर नेट सेविंग कितनी होगी, यह तो सही तभी बताया जा सकता है जब कि उसका पूरा हिसाब किताब हो जाय, पूरे खर्चे को वर्क आउट कर लें तभी निश्चित कुछ कहा जा सकता है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इस प्रकार की मुनाफा वृत्ति को बन्द करने का विचार करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुनाफा वृत्ति है ही नहीं तो बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री चांदमल मेहता—जब सरकार मुनाफा वृत्ति को बन्द नहीं करना चाहती तो क्या प्रोफिट के आधार पुस्तकों का क्रय विक्रय करने का विचार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने निवेदन किया इसमें कोई खास मनोवृत्ति काम करती नजर नहीं आती है क्योंकि किसी पुस्तक की कीमत कितनी रखी जाय और कितनी है यह तभी मालूम हो सकता है जब कि सारी चीजों का टोटल लगाकर नेट प्रोफिट और नेट लोस मालूम हो तभी सही कीमत का पता लग सकता है ।

श्री चांदमल मेहता—राष्ट्रीयकरण की हुई पुस्तकों को तबदील करने का अधिकार, सरकार को, स्वयं को है, फिर पड़े रहने का सवाल ही नहीं उठता ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सवाल ही नहीं होता यह बात नहीं, बाद में जाकर जब कभी चेन्ज हो, चेन्जेज में कितनी किताबें खराब जायगीं उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेज कितने हुए, बुक सेलर्स के जरिये बिकवाने में कितना कमिशन आदि दिया गया, इन सब चीजों को वर्क आउट करने के बाद ही नेट प्रोफिट और नेट लोस देखा जा सकता है ।

श्री चांदमल मेहता—इन पुस्तकों के बेचे जाने के संबंध में सरकार ने क्या व्यवस्था कर रखी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ यह अलग से प्रश्न है । आमतौर पर बुकसेलरों के जरिये बेची जाती है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि चन्द पुस्तक विक्रेताओं के सिवाय किसी को भी पुस्तकें बेचने के लिये नहीं दी जातीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया —जिनको गवर्नमेंट एप्रुव करे ।

प्रश्न संख्या १६३

दो सौ रुपये से कम की खालसा की गई जागीरें

श्री केसरीसिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) जो जागीरें सरकार ने अब तक खालसा की है, उनमें कितनी जागीरें २०० रुपये से कम की हैं ?

(ख) वे कौन कौन सी और किस किस जिले में हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) कोई जागीर राजस्थान सरकार ने नहीं की ।

(ख) कोई नहीं । अगर कोई ऐसी जागीर वापिस करनी होगी तो जो खर्चा हुआ है वसूल किया जाकर कर दी जायगी ।

श्री केसरीसिंह—क्या कोटा डिवीजन में कोई २०० रुपये से कम की जागीर खालसा नहीं हुई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने जैसा कि निवेदन किया सारे राजस्थान में कोई नहीं तो कोटा भी उसमें आ जाता है ।

श्री केसरीसिंह—अगर कोई खालसा हुई हो तो ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— अगर आप ऐसा कोई स्थान बता दें जो २०० रुपये से कम की जागीर है और वह खालसा होगई है तो अलग से देखा जा सकता है ।

प्रश्न संख्या १६४

पालड़ी (त. डेगाना) में अनुभवी अध्यापक का प्रबन्ध

श्री भोपाल सिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सच है कि पालड़ी, तहसील डेगाना में ६ माह से कोई मास्टर नहीं है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार जल्दी ही वहां पर एक अनुभवी मास्टर भेजने का प्रबन्ध करेगी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—(उप-शिक्षा-मंत्राणी) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता क्योंकि यहां शिक्षक कार्य कर रहा है।

श्री भोपालसिंह—जब वहां पर छः महीने से अध्यापक नहीं था तभी तो मैंने प्रश्न किया था।

मैं वहां का बाशिन्दा हूं और जानता हूँ कि वहां पर शिक्षक नहीं था आज जबाब दिया जा रहा है कि शिक्षक वहां पर काम कर रहा है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—आपने प्रश्न पूछा उसके पहले वहां अध्यायक है।

श्री भोपालसिंह—कितने दिन पहले से ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—काफी दिन पहले से।

श्री मानसिंह—अध्यापक कौनसी तारीख को वहां गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जोइनिंग रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं आपसे निवेदन करूं आपका सप्लीमेन्टरी वाजिब है हम इस विषय में इनफोरमेशन सीक करना चाहते थे किन्तु नागौर डिवीजन का टेलीफोन से सम्बन्ध कट गया था टेलीफोन डिस्टर्बेंस होने की वजह से इनफोरमेशन प्राप्त नहीं कर सके।

Page No 9

प्रश्न संख्या १६५.

म. किशनगढ़ मिल्स को पुनः चालू करने की शासकीय योजना

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) महाराजा किशनगढ़ मिल्स को चालू करने की क्या कोई योजना सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है ?

(२) यदि हां, तो वह योजना क्या है और उसके अन्तर्गत मिल्स कब तक चालू कर दी जायेगी ?

(३) उक्त मिल्स को अबतक चालू नहीं करने के क्या कारण हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(उद्योग मंत्री) (१) हां।

(२) मिल मैनेजमेन्ट को मिल को वापिस चालू करने की शर्त पर सरकार द्वारा मजदूरों को चुकाने के लिये (उनके चढ़े हुए वेतन के) ७५, ००० रु. कर्ज रूप दिये गये हैं। मैनेजमेंट ने आश्वासन दिया है कि मिल शीघ्र ही चालू कर दी जावेगी।

(३) मिल मैनेजमेंट के पास रुपये की कमी थी।

श्री चांदमल मेहता—सरकार ने अबतक उस मिलको बन्द रहने को हालत में चालू करने के लिये क्या प्रयास किया ?

श्री भोगीलाल पड्या—मैं समय समय पर बताता रहा हूं। कई व्यापारियों से बातचीत की गई जो उस मिल को चालू करने की इच्छा रखते थे। ऐसा नहीं हुआ तो कर्जा दिलाने की बात भी सोची, वह भी नहीं हो सका। तो इसके बाद तीसरी बात यह आई कि ७५ हजार रुपया सरकार दे ताकि वह रकम मजदूरों को चुकाई जावे और जो उनका प्रोवीडेन्ट फन्ड आदि हैं उसके पेटे सवा लाख रुपया और दिया जाय तो इस तरह से सरकार ने २ लाख रुपया देने की बात की है। ७५ हजार दे भी दिया गया है सवा लाख रुपया और देना है। अब मिल मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से एक आदमी रक्खा है जो मिल चलाने का काम शुरू कर रहा है।

श्री चांदमल मेहता—आज से छः महीने पहले सरकार ने आश्वासन दिया था कि

[श्री चांदमल मेहता]

इसे दो महीने में चालू करवा दिया जावेगा । वह आश्वासन किस आधार पर दिया गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—प्रयास कर रही थी सरकार उस वक्त भी और ऐसी उम्मीद थी कि दो महीने में चालू हो जावेगी और इसी प्रकार का आश्वासन मैनेजमेंट ने सरकार को दिया था। अब इस चीज में कोई आकस्मिक कठिनाई आ जाती है तो सरकार भी क्या कर सकती है।

श्री चांदमल मेहता—इन तरीकों के अलावा और कोई तरीका सरकार के पास नहीं है कि जिससे यह मिल चालू किया जा सके ?

श्री भोगीलाल पंड्या—काफी जांच की गई है पर वे तरीके कारगर नहीं प्रतीत हुए।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि किन्हीं परिस्थितियों में सरकार को मिल को टेक ओवर करने का भी अधिकार है।

श्री भोगीलाल पंड्या—मालूम है। पर साथ ही और भी बातें देखनी पड़ती हैं । सरकार ने देखा कि मिल की मशीनरी काफी पुरानी है, इस पर कर्जा भी है । तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ने अपने नफे नुकसान को काफी सोच विचार के बाद ही यह तरीका ठीक समझा है। मान लीजिये सरकार ले लेती है। मशीनरी काफी खराब है उसको बदलने करने में काफी रुपया फसाना पड़ता अगर किसी लेनदार ने दावा कर दिया तो उसके साथ लिटीगेशन में जाना पड़ता। तो कई तरह से इसको एग्जमिन कराया गया। पर सही तरीका यही मालूम हुआ और वैसे ही किया गया।

श्री चांदमल मेहता—यह सही तरीका कब दिमाग में आया ?

श्री अध्यक्ष—(घंटी) Another Supplementory.

श्री कु. **जसवन्तसिंह**—मैं सवाल पूछना चाहूंगा माननीय मन्त्री से कि किशनगढ के बारे में भिन्न भिन्न प्रश्न आते हैं और काफी पूछताछ भी होती है तो इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री ही क्यों न कायम कर दी जाय। किशनगढ अफेयर्स के लिये एक अलग मिनिस्ट्री अपोइन्ट कर दें जो इसका सवाल जवाब देती रहा करे। (हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर मैं समझता हूं कि आवश्यक नहीं समझा जायगा।

श्री चांदमल मेहता—यह मिल अब कब तक चालू देखने की उम्मीद की जा सकती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वहां तो उनके चलाने वाले आदमी भी चले गये हैं। सफा का काम शुरू हो गया है।

श्री तेजमल बापना—आगे फिर कब तक चलू रहेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हिन्दुस्तान में अनेकों फैक्टरियां हैं, बन्द होती रहती हैं और खुलती रहती हैं, सरकार किन किन के बारे में गारन्टी लेती रहेगी। जब तक चलेगी फिर जो स्थिति आवेगी देखा जावेगा।

श्री अध्यक्ष—No definite date can be given

प्रश्न संख्या १६६

राजस्थान के विभिन्न जिलों में औसत जनसंख्या के पीछे माध्यमिक व उच्च पाठशालाएं
(प्रश्नकर्ता श्री तनसिंह की ओर से श्री जवानसिंह ने प्रश्न पूछा)

श्री जवानसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे;-राजस्थान के प्रत्येक जिले में कितनी औसत आबादी के पीछे एक प्राइमरी मिडिल स्कूल व हाई स्कूल है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—(उपमन्त्राणी, शिक्षा विभाग)

	प्राइमरी	मिडल	हाई
बीकानेर	२३६२	१२७०५	३३०३२
गंगानगर	१६६७	१०७१०	५७२८४
चुरु	२६२३	१४६१७	४३६०५
जोधपुर	२२६७	२५६२१	३६४०६

(आगे के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री जवानसिंह—यह लिस्ट मुझे प्राप्त हो गई है। यह असमानता जो इसमें दिखाई गई है इसको मिटाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

Page No 12

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(मुख्य एवं शिक्षामन्त्री) हम इस साल प्रयत्न कर रहे हैं और ये प्रयत्न हमारे क्या हैं इसकी विस्तृत जानकारी जब डिमाण्ड पर बहस आप करेंगे तो मैं निवेदन कर दूंगा।

श्री जवानसिंह—क्या मैं आशा करूं कि जालोर और बाड़मेर के लिये विशेष कर के ध्यान रक्खा जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जरूर रक्खा जावेगा आप अगर प्रयत्न करते रहेंगे तो।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—लोकल बोडीज की भी स्कूलें इसमें शामिल हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरा खयाल है लोकल बोडीज की स्कूलें इसमें शामिल नहीं है।

प्रश्न संख्या १६७

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधीन राजस्थान में खुलने वाले बड़े बड़े उद्योग

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान में कहां कहां क्या क्या बड़े उद्योग खोलने की सरकार की योजना है ?

(२) व्यक्तिगत कारखानों के चलाने के लिये सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं देना निश्चित किया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(उद्योग व व्यापार मंत्री) (१) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्योगों के खोले जाने की योजना है ;

(१) एक सीमेन्ट फैक्टरी, चित्तौड़गढ़, सिरोही, या रामगंज के पास।

(२) दो टैक्सटाइल मिल्स उदयपुर, जयपुर या भवानीमंडी में।

(३) तीन शक्कर की मिलें, अन्ता, हिन्डौन, कोटा, हनुमानगढ़ में या गंगा नगर क्षेत्र में या दक्षिणी राजस्थान में।

(४) दो स्टील रिरोलिंग मिलें, बिजली से चालित. जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर या सवाई माधोपुर में।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(५) एक ऑयल हाइड्रोजिनेशन प्लान्ट, गंगानगर या कोटा में।

(६) हल्के बिजली के सामान की फैक्टरी चम्बल और भाखरा क्षेत्र में।

(७) रेयन फैक्टरी कोटा में।

(८) दो वुड सीज़निंग फैक्टरी, कोटा और उदयपुर में।

(९) पांच रिरोलिंग मिल्स नोन फेरस मेटल के लिये प्रत्येक डिविजन में।

(१०) फेल्ट फेक्टरी।

(११) वूलन वर्स्टेड स्पीनिंग मिल।

(१२) रिवाइवल काच फेक्टरी।

(१३) पेपर और कार्ड बोर्ड फेक्टरी।

(१४) सिरेमिक्स इन्डस्ट्री।

(१५) प्रोसेसिंग ऑफ मारबल।

(१६) पावर एलकोहल एण्ड सिनेटर्ड स्पिरिट।

(१७) साइकिल पार्ट्स।

(१८) गोट हेयर एण्ड ब्रिस्टल्स बालोतरा में।

(१९) बोल्ट्स और नट्स।

(२०) पेन्ट और वारनिश।

(२१) ब्रास इम्प्लीमेन्ट्स का टावर ब्लाट्स, दरवाजे के फेस्टनर्स आदि का उत्पादन।

(२२) कास्टिक सोडा, हाईड्रोक्लोरिक एसिड फेक्ट्री बीकानेर में।

(२३) प्लास्टर ऑफ पेरिस।

(२४) जिप्सम, सीमेन्ट, शक्कर।

(ख) सरकार द्वारा निम्न कारखाने खोले जावेंगे :

(१) ड्राइहाउस।

(२) सेन्ट्रल वर्कशोप।

(३) सरंजाम कार्यालय।

(४) अल्ट्रामेराइन ब्ल्यू।

(५) वूल कारबोनाइजेशन प्लान्ट।

(६) सोडियम सल्फेट के लिये पाइलाट प्लान्ट।

(७) गलीचा और चटाई उत्पादन केन्द्र।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ग) व्यक्तिगत कारखानों के चलाने के लिये सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता निम्न प्रकार है :

[१] सड़क की सुविधायें, दुरुस्ती विद्युत-शक्ति के उपलब्ध होने तक बिजली की मदद । ३. पानी रियायती दर पर । ४. स्थान के लिए भूमि रियायती दर पर । ५. आर्थिक सहायता, ६. सरकारी खरीद के समय स्थानीय उद्योगों को दर में पांच प्रतिशत प्राथमिकता । ७. मुख्य मुख्य कच्चे पदार्थों पर बिक्री कर से मुक्ति ।

श्री चांदमल मेहता—जो कारखाने सरकार की ओर से खोले जाने की तजवीज है उनमें अब तक क्या प्रगति हो चुकी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—काफी प्रगति हो चुकी है । वैसे दो स्पिनिंग मिल्स की बातचीत करीब करीब पक्की हो गई है । सैन्ट्रल रिरोलिंग मिल की बात भी हो चुकी है । रेयन फैक्टरी के लिए भी बहुत प्रगति हो चुकी हैं, सामान भी बहुत सा आ चुका है, मशीनरी की भी आने की तैयारी ही है । प्लास्टर ऑफ पैरिस के लिये भी काफी बातचीत हो चुकी हैं । और ऐसे ही बहुत से उद्योगों के लिए बातचीत हो चुकी है और ऐसी आशा की जाती है कि कुछ अगले वर्ष शुरू हो जावेंगी ।

श्री सरदार सिंह—माननीय मन्त्री महोदय ने कहीं टोंक का नाम नहीं लिया । तो क्या वहां कोई उद्योग की गुंजाइश नहीं है ?

श्री भोगीलालपंडया—जांच कर रहे हैं । मालपुरा में तो एक इन्डस्ट्री सैट कर दी गई है ।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—सीमेन्ट की फैक्टरी मेवाड़ में खोलने की व्यवस्था किस आधार पर की गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वहां पर पत्थर काफी मात्रा में मिल रहा है इस आधार पर और पानी की सुविधा भी वहां पर है और सस्ती बिजली भी मिल सकेगी ।

श्री हिम्मतसिंह—कोटा की रेयन फैक्टरी के लिए किसका प्रार्थना-पत्र आया है ।

श्री भोगीलाल पंड्या—जुग्गीलाल पदमपत सिंहानिया का प्रार्थनापत्र; उनसे बात भी पक्की हो गई है, बहुत काम आगे बढ़ गया है । मशीनरी के लिए ऑर्डर भी दे चुके हैं, रवाना भी हो गई है । हो सकता है कि जल्दी ही वह खुल जावेगी ।

श्री हिम्मतसिंह—कितना रुपया वे इन्वेस्ट करने को तैयार हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तीन चार करोड़ रुपया लगायेंगे।

श्री गुरुदयाल सिंह—गंगानगर जिले में दूसरी शुगर फैक्टरी किस जगह लगाई जावेगी।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने स्थान बतलाया न।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—मेरा मतलब गंग कैनाल एरिया से है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिए भी अर्जी आई है।

श्री चांदमल महता—प्राइवेट व्यक्तियों को क्या क्या सुविधाएं दी जावेंगी ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में अपनी ओर से सरकार ने कोई अधिकृत घोषणा नहीं की है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने जो बातें थीं बताई हैं, सामान्य तौर पर सरकार ये मदद देगी। फिर कम ज्यादा इन्डस्ट्री की हालत पर निर्भर है, वे क्या मांग कर सकते हैं और हम क्या दे सकते हैं। मामूली जनरल सुविधा जो दे सकते है वह मैंने बता दी। विशेष सुविधा अगर कोई मांगेगा तो स्थिति को देखकर केबिनेट लेवल पर उसे तय किया जावेगा।

श्री चान्दमल मेहता—अब तक कौन कौन से कारखानों की किस किस के नाम से सेन्टर से मन्जूरी ली जा चुकी है ?

श्री भोगलाल पंड्या—यह अलग से पूछ लीजियेगा। मैं सब बता दूंगा।

श्री चांदमल मेहता—जो एक दो चार याद हों वही बता दीजियेगा।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने बताया, जे. के. सिंघानियां, एक राशिवाला है, इसी तरह से गोलेछा ब्रदर्स हैं उनका सीमेन्ट फेक्ट्री का हो चुका है। एक आबू रोड पर ए. सी. सी. को सीमेन्ट फेक्ट्री की मन्जूरी हो चुकी है।

श्री चंदमल मेहता—क्या यह सही है कि बड़े उद्योगों को खोलने के संबंध में सरकार अपनी तरफ से निश्चित नीति नहीं अपना कर व्यक्ति को देख कर अपनी नीति बनाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह इन्डस्ट्री को देख कर ही नीति अपनाई जाती है। फिर इसकी विस्तृत जानकारी के लिए क्या क्या इन्डस्ट्री कहां कहां खोली जा रही हैं, क्या किया जा रहा

[श्री भोगीलाल पंड्या]

है इस पर एक विस्तृत जानकारी देते हुये एक पुस्तिका सरकार की तरफ से शाया हुई है, जिसको देखने से आपको मालूम होगा।

श्री चांदमल मेहता—जो दो चार नाम एवेलेबल हैं वे ही बता दें।

श्री भोगीलाल पंड्या—जुग्गीलाल कमलापत रेयन फेक्ट्री के लिए, रानी वाले को टेक्स्टाइल मिल के लिए हो चुका है, गोलेछा ब्रदर्स हैं उनके बारे में सीमेन्ट फेक्ट्री का तय हो चुका है, आबू रोड पर ए०सी०सी० द्वारा सीमेन्ट फेक्ट्री खोलने का फैसला हो चुका है। अभी जो सवाई माधोपुर में सीमेन्ट फेक्ट्री है उसकी केपेसिटी १ लाख टन की है उसको ५ लाख टन तक की केपेसिटी बढ़ाने की मन्जूरी हो गई है और वहां काम भी शुरू हो गया है। इस तरह से बहुत सी मन्जूरियां हो चुकी हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बड़े २ उद्योगों को चलाने के सम्बन्ध में सरकार अपनी कोई निश्चित नीति नहीं अपना कर व्यक्ति या कारखाने को देख कर नीति अपनाती है।

श्री भोगीलाल पंड्या—इन्डस्ट्री को देख कर ही हमें अपनी नीति अपनानी पड़ती है। थोड़ी बहुत सुविधायें नहीं देने से वह इन्डस्ट्रीज नहीं चल सकती है। जनरल जो बातें हैं वह आपको बता दी हैं कि लगभग यह सुविधाएं सब को देते हैं।

श्री चांदमल मेहता— सरकार इन्डस्ट्री के आधार पर, किस किस इन्डस्ट्री को क्या क्या सुविधाएं देना चाहती है, उस सम्बन्ध में अपनी नीति तय करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वैसे मैंने आपको बताया है कि इन्डस्ट्रियल पालिसी पर सरकार सोच रही है। दूसरी रियासतों में क्या क्या सुविधाएं हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिये एक विशेष व्यक्ति को भेजा था। वे सब जानकारी लाये हैं, उसके आधार पर इन्डस्ट्रियल पोलिसी बनाने का सोच रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—इसका कब तक फैसला कर दिया जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जितना समय लगना चाहिये उसके बाद ही वह हो सकता है।

श्री चांदमल मेहता—किस किस जगह क्या क्या कारखाने खोले जा रहे हैं, इसके सम्बन्ध में क्या सरकार ने अपनी ओर से कोई समिति बनाई थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार अपनी ओर से उसकी जानकारी देती है जो पार्टी आती हैं लगाने के लिए, उसको अपनी ओर से बताती है। इसके अलावा अभी हमारे माइनिंग डिपार्टमेन्ट ने एक अच्छी पुस्तक लिखी है जिसमें बताया गया है कि कहां कहां कौन कौन से मिनरल्स निकलते हैं और वह किस किस उद्योग में काम में आते हैं। उसी तरह से उद्योग के लिए एक ऐसी ही पुस्तक तैयार हो रही है, और मेरा ऐसा ख्याल है कि वह एक सप्ताह में छप कर आ जायगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या कोई एक्सपर्ट उद्योग विभाग की ओर से बुलाया गया जिसने इस तरह की जांच करके रिपोर्ट लिखी है कि फलां फलां उद्योग फलां फलां जगह पनप सकते हैं? क्या कोई ऐसी कार्यवाही हुई है?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब आवश्यकता होती है तो वह एक्सपर्ट भी बुला लेती है लेकिन यह सब जानते हैं कि जहां कपास खूब पैदा होता है वहां टेक्सटायल मिल हो सकती है। जहां ऊन होता है वहां ऊन की मिल बन सकती है, जहां साल्ट्स निकलते हैं वहां सोडियम वगैरह हो सकते हैं, जहां सीमेन्ट का पत्थर निकल सकता है वहां सीमेन्ट फेक्ट्री लग सकती है। उसके बाद भी यदि आवश्यकता होती है तो एक्सपर्ट को बुलाया जाता है जैसे कि डा० टोडब्रोले को हमने बुलाया था।

श्री चांदमल मेहता—दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कारखाने खोले जा सकते हैं, इसको तय करने के पूर्व क्या सर्वे कराई है, कि किस किस जगह क्या क्या हो सकता है?

श्री भोगीलाल पंड्या—५, ६ दिन में वह किताब छप जायगी और पूरी सर्वे की रिपोर्ट आपको मिल जायगी।

श्री श्रीदास गोयल—ग्लास फेक्ट्री खुलने की क्या राजस्थान में सम्भावना है?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, ग्लास फेक्ट्रीज़ हमारे यहां ६, ७ खुली थीं जिनमें से केवल धौलपुर की चल रही है। बाकी में कुछ लिक्वीडेशन में चली गई; कुछ आपस के झगड़े में चली गई, ऐसा हुआ है इसलिए बन्द पड़ी हैं। लेकिन उसकी सम्भावना है, क्योंकि मिट्टी अच्छी निकलती है।

श्री कंवरलाल जेलिया—रामगंज मण्डी में जो सीमेन्ट फेक्ट्री का आपने बताया है उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री भोगीलाल पंड्या—वहां पत्थर अच्छा मिलता है सीमेन्ट का पत्थर अच्छा चूने वाला है इसलिये सम्भावित स्थानों में उसका नाम रखा गया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री केसरीसिंह।

प्रश्न संख्या १६८

राजस्थान में जल बोर्ड तथा उसके सदस्य मनोनीत करने के आधार

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में इस समय कितने जल बोर्ड कार्य कर रहे हैं ?

(ख) इन बोर्डों के सदस्यों को सरकार ने किस आधार पर मनोनीत किया है ?

(ग) क्या इसके सचिव भी मनोनीत किये गये हैं ? उनके नाम क्या हैं, जिलेवार बतावें।

(घ) जिला बूंदी में अलग अलग तहसीलों में कितना २ रुपया इसके लिये दिया गया है।

(ङ) इस बोर्ड में कितने आदमी वेतन पर रक्खे गये हैं और इनके क्या क्या नाम हैं ?

(च) क्या ये आदमी बोर्ड की स्वीकृति लेकर रखे गये हैं या सचिव ने अपनी इच्छा से इनको रख लिया है ?

(छ) इन लोगों को कितना रुपया वेतन के रूप में मिलता है और कितना अलाउन्स के रूप में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासनमन्त्री)—(क) केवल एक। राजस्थान प्रान्त के प्रत्येक जिले में वाटर बोर्ड की एक शाखा कार्य करती है जो जिला कमेटी के नाम से सम्बोधित की जाती है।

(ख) इस राजस्थान जल बोर्ड के सदस्य रचनात्मक कार्यकर्ताओं में से, राजस्थान विधान सभा तथा अन्य व्यक्तियों को जो इस कार्य में रुचि रखते हैं सरकार द्वारा मनोनीत किये गये हैं।

(ग) जल बोर्ड द्वारा जिला कमेटियों के मन्त्री मनोनीत किये जाते हैं। सरकार से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। उनकी सूची इस प्रकार है :

१. श्री धर्मदत्त जी जयपुर

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

२. श्री महेन्द्रकुमार जैन	टोंक
३. श्री रामसिंह यादव	सवाई माधोपुर
४. श्री भवानीसिंह सैनी	अलवर
५. श्री राधाकृष्ण पुरोहित	भरतपुर
६. श्री सॉवलमल भोर	सीकर
७. श्री भागीरथ स्वामी	झुन्झुनू
८. श्री मीठालाल त्रिवेदी काका	जोधपुर
६. श्री देवदत्त तिवाड़ी	बाड़मेर
१०. श्री लीलाधर व्यास	जैसलमेर
११. श्री शंकरलाल एडवोकेट	पाली
१२. श्री देवीचन्द जैन	जालोर
१३. श्री रिखबचन्द शाह	सिरोही
१४. श्री बृजमोहन धूत	नागौर
१५. श्री मालचन्द खड़गावत	बीकानेर
१६. श्री हंसराज आर्य, एम. एल. ए.	श्री गंगानगर
१७. श्री कन्हैयालाल सेठिया	चूरू
१८. श्री रतनलाल सोढानी	कोटा
१६. श्री भंवरलाल शर्मा लाखेरीवाला	बूंदी
२०. श्री प्रभूलाल पेंटर	झालावाड़
२१. श्री किशनलाल शर्मा	उदयपुर
२२. श्री भंवरलाल मदादा	भीलवाड़ा
२३. श्री धूलजी भाई, एम. एल. ए.	बांसवाड़ा
२४. श्री गोरीशंकर उपाध्याय	डूंगरपुर
२५. श्री इन्द्रदेव विद्याभूषण	चित्तोड़गढ़

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(घ) जिला बूंदी में अलग अलग तहसीलों को दिये गये द्रव्य का विवरण इस प्रकार है—

	स्वीकृत द्रव्य	बांटा हुआ द्रव्य
१. पाटन	९०,१०२ रुपये	५६,१२६ रुपये
२. बूंदी	१०,३०० ,,	५,७३६ ,,
३. तालेड़ा	७,२६० ,,	५,९७७ ,,
४. हिन्डोली	१०,००७ ,,	७,१५२ ,,
५. नेनवा	२०.७८४ ,,	१३,१२३ ,,
कुल	१,३८,४५३ रुपये	८८,११४ रुपये

(ङ) सरकार की ओर से कोई व्यक्ति वेतन पर इस बोर्ड में नहीं रखा गया है। सारी व्यवस्था जल बोर्ड की है। जिला बूंदी कमेटी बूंदी में इस समय निम्न ४ कार्यकर्त्ता काम कर रहे हैं :

१. श्री हीरालाल
२. श्री मूलचन्द
३. श्री कृष्णगोपाल
४. श्री सूरजमल

(च) इससे सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(छ) जल बोर्ड की ओर से उक्त कार्यकर्ताओं को निम्न प्रकार वेतन मिलता है—

	वेतन	सवारी भत्ता	योग
१. श्री हीरालाल	६० रुपये	१५ रुपये	७५ रुपये
२. श्री मूलचन्द	६० ,,	१५ ,,	७५ ,,
३. श्री कृष्ण गोपाल	६० ,,	१५ ,,	७५ ,,
४. श्री सूरजमल	३० ,,	१० ,,	४० ,,

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—इसमें से एम. एल. एज़. कितने हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एम. एल. एज. दो हैं। एक श्री हंसराज आर्य और दूसरे श्री भूलजी भाई।

Page No 21

श्री भैरूसिंह (वि. सं. १६)—क्या विधान सभा के सदस्यों को भी एलाउन्स के रूप में कुछ मिलता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एम. एल. एज़ को कुछ नहीं मिलता है। वे लेते नहीं हैं।

श्री रामदयाल उपाध्याय—बाकी जो सूची में हैं उनको क्या पे मिलती है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मिलती जरूर है, लेकिन अलग २ जगह अलग २ मिलती है। वह मेरे पास नहीं है।

श्री द्वारकादास पुरोहित—पाली, जोधपुर, बाड़मेर में जो रचनात्मक कार्यकर्ताओं के सेक्रेटरीज़ के रूप में नाम बताये गये हैं वे इस जल बोर्ड में शामिल होने से पहले क्या थे? वे क्या रचनात्मक कार्य करते थे और किस प्रकार से वे जल के कार्य में रुचि लेते थे? इसकी आपके पास रिपोर्ट है क्या कि यह यह काम उन्होंने किये थे जिसकी वजह से उनको एप्वाइन्ट किया गया है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रचनात्मक कार्यकर्ताओं की सूची मेरे पास नहीं है कि कौन २ कहां कहां कार्य करता था या कर रहा है।

श्री द्वारकादास पुरोहित—मैंने सेक्रेटरीज के बारे में पूछा है कि जल बोर्ड में जो सेक्रेटरीज़ लिये गये हैं उन्होंने क्या क्या रचनात्मक कार्य किये हैं? जब कि आपने उनको एप्वाइन्ट किया है तो जल के मामलों में उन्होंने क्या २ रुचि बताई थी और क्या २ काम किये थे उन्होंने रचनात्मक कि जिसकी वजह से उनको एप्वाइन्ट करना आपने मुनासिब समझा है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह जानकारी इस तरह की मुझे प्राप्त नहीं है। फिर प्राप्त करके बता सकता हूं।

श्री भैरूंसिंह—रचनात्मक कार्यकर्ताओं के आधार का क्या मापदण्ड सरकार ने तय कर रखा है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—किसका?

श्री अध्यक्ष—रचनात्मक कार्यकर्ताओं के आधार का क्या मापदण्ड तय कर रखा है सरकार ने?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—राजस्थान में कौन कौन कार्य करने वाले हैं वह हरेक को मालूम है।

श्री भैरूं सिंह—सरकार ने कौनसा मापदण्ड निश्चित कर रखा है ? सरकार की कोई ऐसी नीति होगी कि कोई इतना रचनात्मक काम करेगा उसको जलबोर्ड में लिया जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—राजस्थान में सबको मालूम है कि कौन कौन क्या काम करने वाले हैं ।

श्री द्वारकादास पुरोहित—सबको तो मालूम है लेकिन सरकार को क्या मालूम है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह जल बोर्ड को मालूम है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने कोई क्राइटेरिया मुकर्रर नहीं किया है, ऐसी स्थिति है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—क्राइटेरिया मुकर्रर करने का सवाल नहीं आता है । वे अर्से से काम करने वाले हैं । जो लोग अच्छे काम करने वाले हैं उनको रखा गया है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार ने यह निर्णय किया है या नहीं कि अमुक पब्लिक वर्कर कहलाने के काबिल है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जो आदमी रेस्ट्रिक्टेड काम नहीं करता है वह अच्छा कार्यकर्ता कहलाता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार किस बिना पर इस निर्णय पर पहुँची है........

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जो लोग जनता की सेवा करते हैं और रेस्ट्रिक्टेड काम नहीं करते हैं उनको कहते हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इनके कार्यों की सूची सरकार ने तैयार कर रखी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जनता को मालूम है, यह साफ बात है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जनता को मालूम होने का प्रश्न नहीं है । गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है । गवर्नमेंट ने क्या निर्णय किया है ? गवर्नमेन्ट को क्या मालूम है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह वाटर बोर्ड का डिसीजन है । तनख्वाह वाटर बोर्ड से दी जाती है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—गवर्नमेन्ट की वाटर बोर्ड के सिलसिले में जो रेस्पोन्सिबिलिटी है उसको देखते हुए गवर्नमेन्ट को क्या कोई क्राइटेरिया मुकर्रर करना पड़ेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पोजिशन बिल्कुल स्पष्ट है। सेन्ट्रल वाटर बोर्ड की रेस्पोन्सिबिलिटी है। फाइनेन्शियल या किसी तरह का खर्चा हो तो उसके लिए रूल्स बने हुए हैं। वहां काम करने वाले सेक्रेटरी कौन हैं, आदि के लिए मैं निवेदन करूंगा कि वाटर बोर्ड ही नियुक्त करता है और जो खर्चा होता है वह वाटर बोर्ड का खर्चा होता है। गवर्नमेन्ट की मनी से पे नहीं किया जाता है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—माननीय मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि नौकरों की तनख्वाहों में कितना खर्चा हो रहा है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह सवाल पैदा ही नहीं होता है। वाटर बोर्ड ही उनको पे करता है। अगर असेम्बली द्वारा दिये हुए खर्चे में से कोई खर्चा होता है तो पूछ सकते हैं, लेकिन वाटर बोर्ड वाले ही खर्च करते है, गवर्नमेन्ट खर्च नहीं करती। गवर्नमेन्ट का कोई पैसा खर्च नहीं होता है।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि इन मन्त्रियों में से कोई भी व्यक्ति नोन कांग्रेसी नहीं है?

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि वाटर बोर्ड से जितना खर्चा हुआ है, वह गवर्नमेंट की ओर से न होकर चन्दे से इकट्ठी की गई रकम में से खर्चा हो रहा है?

श्री भैरूंसिंह—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है?

श्री घासीराम—भवानीसिंहजी जो हैं, क्या हैडमास्टर मिडिल स्कूल हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस समय नहीं हैं।

श्री भैरूंसिंह—क्या इन मंत्रियों में से कोई ऐसा मंत्री है जो नोन कांग्रेसी है?

श्री अध्यक्ष—कौन से मंत्री?

(हंसी)

श्री भैरूंसिंह—वाटर बोर्ड के?

श्री भवानी सहाय शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ पूछ लूं। अलवर में जो इस वक्त भवानीसिंह जी हैं, लगे हुए हैं, ये लगने से पहले कितना रचनात्मक कार्य कर रहे थे?

Page No 24

[श्री भवानी सहाय शर्मा]

(किसी माननीय सदस्य के कुछ संकेत करने से) मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मिनिस्टर साहब से पूछ रहा हूं।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री घासीराम—अलवर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की शिकायत थी........

(घंटी)

श्री भवानी सहाय शर्मा—अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण सवाल है और पूछना जरूरी है। सवाल यह है कि जो भवानीसिंह जी लगे हुए हैं........

श्री अध्यक्ष—कोई होंगे बाबा।

श्री भवानी सहाय शर्मा—उनके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आया।

श्री केसरीसिंह—इन सचिवों में कितने सचिव ऐसे हैं ?........

श्री अध्यक्ष—Not clear.

श्री केसरीसिंह—इन सचिवों में से कितने ऐसे हैं जो कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं ? (विराम) जो सेक्रेटरीज़ काम कर रहे हैं उनमें से कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं वे कितने ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। नाम तो बहुत हैं लेकिन उनको मैं जानता तो नहीं, हरएक को जानूं ही, यह तो मुश्किल है। जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूँ। मीठालाल काका.... ये रचनात्मक कार्यकर्ता हैं।

श्री केसरीसिंह—क्या यह सत्य है कि जनता का काम केवल कांग्रेस ही कर सकती और नहीं ?

(विरोधी पक्ष द्वारा "हियर हियर" एवं घंटी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसमें बहुत से ऐसे रखे गये है जो रचनात्मक कार्यकर्ता नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, १६६।

प्रश्न संख्या १६६

(श्री तनसिंह की अनुपस्थिति में लिया गया)

राजस्थान में शासकीय व्यय से चलने वाली प्राथमिक पाठशालायें

क्या शिक्षा मन्त्री जी निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कुल कितनी प्राइमरी स्कूलें सरकारी खर्चे पर चलती हैं ?

(ख) उनमें कुल कितने अध्यापक हैं ?

(ग) प्रति अध्यापक की औसत माहवारी तनख्वाह क्या है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उप शिक्षा मंत्राणी)—(क) ६८३६ स्कूलें ।

(ख) ११,४०८ अध्यापक हैं ।

(ग) ६२) रु० ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या १७०

किशनगढ़ सब डिवीजन के पटवारी तथा इस सब-डिवीजन के निवासी पटवारियों का बाहर स्थानान्तर

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ सब डिविजन में पटवारियों की कितनी संख्या है ?

(ख) उक्त पटवारियों में किशनगढ़ सब डिवीजन के बाहर के कितने हैं ?

(ग) किशनगढ़ सब डिवीजन के निवासी कितने पटवारी हैं जो अन्य सब डिविजनों में भेजे गये ?

[श्री चांदमल मेहता]

(घ) ऐसे कौन कौन पटवारी हैं जिन्होंने अपने सब डिविजन में ट्रांसफर होने के लिए इन्सपेक्टर से पटवारी होना स्वीकार किया है ?

(ङ) ऐसे पटवारियों में किन किन का ट्रान्सफर किशनगढ़ सब डिवीजन से बाहर किया गया है ?

श्री संपतराम (उप राजस्व मन्त्री)--(क) किशनगढ़ सब डिविजन में पटवारियों की संख्या ७१ है।

(ख) उक्त पटवारियों में किशनगढ़ सब डिवीजन से बाहर के ४ पटवारी हैं।

(ग) किशनगढ़ सब डिवीजन के निवासी ऐसे ७ पटवारी हैं जो अन्य सब डिवीजनों में पटवारी पद पर कार्य कर रहे हैं।

(घ) कोई नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रश्न यहां पर आवें, मैं समझता हूं कि उन पर थोड़ा विचार किया जाय तो ठीक होगा। कौन-कौन से पटवारी हैं, कहां कहां काम करते हैं........

श्री अध्यक्ष—This is the interest which the Hon' ble member envisage in the administration,

श्री चांदमल मेहता--सब डिवीजन के बाहर पटवारियों के ट्रान्सफर्स करने के क्या कारण हैं ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूसिंह।

प्रश्न संख्या १७१

सन् १९५३-५४ के हरिजन ग्रहों के सहायतार्थ खरीदी गई चद्दरें

श्री भैरूसिंह (१९)—क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[श्री भैरूसिंह]

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने सन् १९५३-५४ में लगभग ३५,०००)-रु० की टीन की चद्दरें हरिजनों के मकानों के लिये सहायतार्थ देने हेतु खरीदी थीं ?

(ख) यदि हां, तो क्या ये चद्दरें वितरित कर दी गई थीं ? यदि हां, तो किस किस को कितनी कितनी और कब कब ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) क्या कुछ चद्दरें अब भी पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

श्री भोगीलाल पंडया (समाज कल्याण मन्त्री)—(क) हां। सन १९५३-५४ में ३४,३७३ रु० ११ आना ६ पाई की टीन की चद्दरें मकान के लिये खरीदी गई थीं।

(ख) नहीं। अभी कुछ चद्दरें वितरित नहीं हो सकी हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (सूची उपलब्ध नहीं हुई)

(ग) इसका उत्तर 'ख' में दे दिया गया है। ८८२ चद्दरें बाकी थीं, उनमें से भी बांट दी गई हैं।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि चद्दरें डिस्ट्रिक्ट वाइज़ अलाट नहीं की गईं ?

श्री भोगीलाल पंडया—जहां जहां डिस्ट्रिक्ट में जरूरत थी वहां वहां पहुंचा दी गई, कुछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं पहुच पायीं। खास तौर पर उन लोगों का सरकार ने ध्यान रखा है कि या तो उनके मकान जल गये हों या बाढ़ से बह गये हों।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ में इन तीनों जिलों में, क्या एक भी चद्दर वहां वितरित की गई है ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—श्री भवानी सहाय।

प्रश्न संख्या १७२

राज गढ़ (अलवर) में वर्तमान डॉक्टर की नियुक्ति एवं उनके आचरण के के विरुद्ध शिकायतें

श्री भवानी सहाय—क्या स्वास्थ्य मन्त्री महोदय कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि—

[श्री भवानी सहाय]

(क) राजगढ़ (अलवर) में वर्तमान डाक्टर कब से नियुक्त है ?

(ख) क्या इनका परिवर्तन कोटा किया गया था ? यदि हां, तो वे कितने दिनों बाद वापिस आगये और उनके स्थान पर जो डाक्टर आया वह कितने दिनों बाद वापिस आ गये और उनके स्थान पर जो डाक्टर आया वह कितने दिन राजगढ़ रहा ?

(ग) क्या इनके विरुद्ध जनता की शिकायत होने के कारण ही इनका स्थानान्तरण किया गया था ?

(घ) ऐसे स्थानान्तरण कितने बार हुए और फिर रद्द किये गये ? कृपया कारण बताइये ।

(ङ) क्या इन डाक्टर के आचरण तथा व्यवहार की जांच की गई थी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

(च) क्या वर्तमान डाक्टर के कार्यकाल में मरीजों की संख्या घटी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) मई १९५४ से ।

(ख) जी हां, परन्तु ३७ दिन बाद ही ये वापस राजगढ़ आगये । जो डाक्टर इनके बाद आये वे भी ३७ दिन राजगढ़ रहे ।

(ग) कुछ लोगों की शिकायतें जरूर थीं । परन्तु स्थानान्तर का उससे कोई सम्बन्ध नहीं था ।

(घ) दो बार । शासनिक कारणों से ।

(ङ) जी हां । शिकायतें ठीक नहीं पायी गई ।

(च) जी नहीं ।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

श्री भवानी सहाय—यह.......

श्री अध्यक्ष—तुरन्त पूछ लीजिये, otherwise very little time is left and other questions will be left.

श्री भवानी सहाय—उनका जो ट्रान्सफर हुआ वह क्यों हुआ तो उसका कारण प्रशासनिक बताया ! बहुत सी अर्जियां आपके पास और चीफ मिनिस्टर के पास भेजी गई उनका क्या हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद—शिकायतों की जांच कराई गई। मैं फाइल ,पूरी अपने साथ लाया हूँ। पी. एम. ओ. की रिपोर्ट मौजूद है। शिकायतें गलत थीं। मैं भी मौके पर गया था, पता चला कि शिकायतें गलत थीं।

श्री भवानी सहाय—प्रश्न पूछने से पहले या बाद में ट्रान्सफर किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद—पहले कर दिया गया।

श्री भवानी सहाय—क्या यह सही है कि २२ जून, १९५५ को डाइरेक्टर मेडिकल ने एक भवानी सहाय शर्मा, एम. एल. ए. को कोई पत्र लिखा ?

श्री अध्यक्ष—लिखा होगा, आपके पास होगा।

(हंसी)

प्रश्न संख्या १७१

परबतसर तहसील में नियन्त्रण में लिये जागीरी ग्राम एवं उन ग्राम वासियों पर लागें

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे;

(क) परबतसर तहसील में कितने जागीर के ग्राम सरकार के नियन्त्रण में लिये गये हैं ?

(ख) उक्त ग्रामों को नियन्त्रण में लेने के बाद क्या क्या नई लागें किसानों पर लगाई गई हैं ?

(ग) उक्त लागें किस कानून के अन्तर्गत लागू की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)— (क) परबतसर तहसील के १४४ जागीर के ग्राम सरकार के नियन्त्रण में लिये गये।

(ख) कोई नई लाग बाग नहीं लगाई गई।

Page No 30

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या कोई नई लाग लगाने के बाद कोई शिकायत आयी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां। माननीय सदस्य खुद आये थे। मैंने हुक्म लिख दिया था कि कोई लाग वसूल नहीं की जायगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या उस हुक्म के जारी करने के बाद भी परबतसर तहसील में लाग वसूल की जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उसके बाद मेरे पास कोई शिकायत नहीं आयी है। माननीय सदस्य बता रहे हैं तो मैं जांच करूंगा।

प्रश्न संख्या १७४

कम मूल्य भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत बनने वाले भवन तथा उस हेतु ऋण

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) Low cost housing scheme के अन्तर्गत कितने भवन जयपुर शहर में कहां कहां किस किस बस्ती में बन रहे हैं ?

(ख) अब तक कितना रुपया कर्ज के बतौर दिया गया ?

(ग) भारत सरकार द्वारा कितना रुपया इस कार्य के लिये मिला था ? उसमें से कितना रुपया खर्च किया जा सका और कितना रुपया लैप्स हो रहा है ?

(घ) लैप्स होने के क्या कारण हैं ?

(ङ) जयपुर शहर में इस स्कीम के अन्तर्गत जो भवन बन रहे हैं उनका समय समय पर निरीक्षण करने हेतु किस किस अधिकारी को भेजा गया और सरकार की ओर से उक्त अधिकारियों के लिये क्या क्या यातायात की व अन्य सुविधायें दी गई ?

(च) यदि नहीं तो क्या उन्हें सवारी का अलाउन्स दिया गया है, यदि नहीं, तो क्यों ?

Page No 31

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री)— (क) तारीख १४. ३. ५६ तक ३६७ भवन निम्न लिखित बस्तियों में बन रहे हैं :

सी स्कीम	४८
गांधी नगर	१५६
लेबर कोलोनी	५३
आदर्शनगर	६८
बनीपार्क	२७
शहर	२६
अन्य	१३
	३६७

(ख) तारीख १४. ३. ५६ तक ११, ६४, ००० रु० ऋण के बतौर दिये जा चुके हैं।

(ग) लो इनकम ग्रुप हाउसिंह स्कीम के लिये भारत सरकार से राजस्थान के लिए १६५५-५६ पर्यन्त १ करोड़ की निधि निर्धारित की गई थी। इसमें से ३७३१७८८ रुपये व्यय हो चुके हैं क्योंकि खर्चा वित्तीय वर्ष तक होता रहेगा। यह अभी नहीं बताया जासकता कि कितना रुपया खर्च नहीं हो सकेगा।

(घ) रुपये लैप्स होने के कारण निम्न लिखित हैं :

१. लोगों को पर्याप्त संख्या में प्लॉट ही समय पर नहीं मिल सकना।

२. प्लॉटों का कई स्थानों में समय पर कब्जा नहीं दिया जा सकना।

३. प्लाटों के डिमार्केशन करने में देरी।

४. वाटर लाइन डालने में देरी हुई क्योंकि पर्याप्त संख्या में पाइप उपलब्ध नहीं थे।

(५) बहुत से लोगों ने भी प्लाटों के अलाट करवाने व ऋण ग्रहण करने में आशातीत उत्साह नहीं दिखाया।

(ङ) इस किस्म के भवनों के निरीक्षणार्थ भवन निर्माण अधिकारी समय समय पर जाते रहे हैं। ओवर सियर की तीन पोस्टें थीं पर योग्य व्यक्तियों के न मिलने से वे पोस्टें रिक्त रहीं।

(च) सुविधा नहीं दी गई क्योंकि यह आवश्यक नहीं समझा गया।

(छ) सरकार की ओर से हर प्रकार की सुविधा दी गई किन्तु कई कारणों से जैसे कि

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

पाइपों का अभाव व भूमि को समतल करने के लिए समय लग जाना, प्लॉटों का अलाटमेन्ट देरी से होना इत्यादि के कारण पूरी रकम खर्च नहीं हो सकी।

(प्रश्न में भाग (छ) नहीं है किन्तु सदन में उत्तर पढ़ा गया)

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या यह सही नहीं है कि उक्त अधिकारी यातायात की सुविधा नहीं होने के कारण वह सब जगह सुपरविजन नहीं कर सकता और जनता को इससे काफी तकलीफ उठानी पड़ती है ?

श्री अध्यक्ष—सारे रीज़न्स उत्तर में बता दिये गये हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—सरकार की ओर से सवारी की सुविधा नहीं मिली इसलिए वह सब जगह नहीं जा सकता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपका मतलब क्या है ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—जनता को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्या उनको सवारी नहीं मिलने से नुकसान उठाना पड़ रहा है ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—सवारी नहीं मिलने के कारण वे सब मकानों को नहीं देख सकते जब कि देखना जरूरी होता है। समय पर नहीं देख सके। इस लिए जनता को काफी नुकसान हुआ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—दूसरे कारण थे वे सब निवेदन किये गये, जितना खर्चा किया जा सकता था वह सब किया गया।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—भविष्य में सरकार क्या करने की सोच रही है, अन्डर कंस्ट्रक्शन मकानों के सुपरविजन के लिये ?

श्री अध्यक्ष—अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों के सुपरविजन के लिये क्या इन्तजाम है, यह बता दीजिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उसके लिए इन्तजाम है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या इन्तजाम किया गया है सरकार की तरफ से ? सरकार की तरफ से जमीन और कर्जा दिया गया है तो सुपरविजन के लिए कन्वेयेन्स भी देना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कन्वेयेन्स का इन्तजाम तांगा या साइकल द्वारा स्वयं कर सकते हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—जयपुर शहर में ३५७ मकान बन रहे हैं। बगैर कन्वेयेंस के उनका सुपर्विजन कैसे किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—Why do you plead the cause of that Officer ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)— अध्यक्ष महोदय, प्रश्न की मंशा स्पष्ट मालूम पड़ती है।

प्रश्न संख्या १७५

ठिकाणा दूनी में ठिकाने के पटवारी के साथ सरकारी पटवारी की नियुक्ति एवं उसको वेतन ठिकाने से देने सम्बन्धी

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि ठिकाना दूनी, तहसील दूनी में ठिकाने के पटवारी होते हुए भी सरकारी पटवारी काम कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह ठिकाने से दिलाई जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो वे पटवारी कब से और क्यों रखे गये हैं ?

श्री सम्पतराम (उप मन्त्री)—(क) और (ख) का सम्मिलित उत्तर इस प्रकार है:

जब से ठिकाने दूनी के गांवों में लैंड रिकार्ड का काम शुरू हुआ तब से सरकारी पटवारी मुकर्रिर हुए हैं। सरकारी पटवारियों की तनख्वाह ठिकाने से नहीं दिलाई जाती है। ठिकाने ने अपने कुछ प्राइवेट पटवारी रक्खे बताये हैं और उनसे अपनी वसूली कराते हैं। ठिकाना अभी खालसा नहीं हुआ है।

श्री रावराजा सरदारसिंह—क्या अभी ठिकाना रिज्यूम नहीं हुआ है ?

श्री सम्पतराम—अभी तक रिज्यूम नहीं हुआ है।

प्रश्न संख्या १७६

माध्यमिक पाठशालाओं के उर्दू व फारसी के मौलवियों के ग्रेड की घोषणा न करने संबंधी

श्री जसवन्त सिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या १ अप्रैल, सन् १९५० से समस्त अध्यापकों के वेतन के ग्रेड में वृद्धि हुई है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि मिडिल कक्षाओं को पढ़ाने वाले उर्दू व फारसी के मौलवियों के वेतन का ग्रेड अभी तक घोषित नहीं किया गया है ?

(ग) सन् १९५६ में होने वाली वेतन वृद्धि में उपरोक्त मौलवियों के वेतन व ग्रेड में वृद्धि हुई है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (शिक्षामंत्री): (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

श्री जसवन्तसिंह—इनका ग्रेड व वेतन में वृद्धि नहीं करने का क्या कारण है ? मौलवियों में और दूसरे अध्यापकों में भेद भाव का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपका प्रश्न आने के बाद मेरा भी ध्यान इस ओर गया है।

प्रश्न संख्या १७७

त० सलूम्बर में काकड़ू काश्त के खाते एवं काकड़ू काश्त के काश्तकारों से लगान

श्री सोहन लाल—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सलूम्बर तहसील में काकड़ू काश्त के कितने खाते हैं ?

(ख) काकड़ू काश्त करने वाले किसानों से पैमाइश में स्वीकृत लगान ही लिया जाता है या उससे अधिक ?

[श्री सोहनलाल भटनागर]

(ग) यदि अधिक लिया जाता है तो क्यों ?

(घ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद पहले से काकड़ू काश्त करते आ रहे किसान जिस श्रेणी के काश्तकार हो जाते हैं उन्हें उस श्रेणी के काश्तकार करार देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) प्रतिवर्ष भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न जमीनों पर काकड़ू काश्त करते हैं। ऐसी हालत में किसी का मुश्तकिल खाता तहसील सलूम्बर में नहीं है। अतः ऐसी दशा में तादाद सही नहीं बताई जा सकती है।

(ख) काकड़ू काश्त करने वाले किसानों से जो दरख्वास्त देकर काश्त करते हैं एक रुपया प्रति बीघा के हिसाब से लगान लिया जाता है और जो बगैर दरख्वास्त दिये (स्वीकृति लिये) काश्त करते हैं उनसे दो रुपया प्रति बीघा लगान लिया जाता है। सैटलमैन्ट की लगान की शरह से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होता।

(ग) जो लगान लिया जाता है वह उदयपुर के कानून व रिवाज के मुवाफिक लिया जाता है।

(घ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद भी जिन किसानों को जो अधिकार पूर्व से ही प्राप्त हैं वे वैसे ही रहेंगे। सरकार की तरफ से इसमें कोई भी कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—काकड़ू काश्त कैसी होती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आरजू काश्त से मतलब है।

प्रश्न संख्या १७८

समाज कल्याण विभाग की सहायता एवं संरक्षण से पिछली जाति के चलाये जाने वाले छात्रावास

श्री भैरोंसिंह—क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में समाज कल्याण विभाग की सहायता से और इस विभाग के संरक्षण में पिछड़ी जातियों के कितने छात्रावास कहां कहां चलाये जाते हैं ?

[श्री भैरूसिंह]

(ख) प्रत्येक छात्रावास को कितनी कितनी सहायता मिलती है और उनमें छात्रों की संख्या प्रत्येक में कितनी कितनी है ?

(ग) गत दो वर्ष में इस विभाग के किस किस अधिकारी ने कब कब इन छात्रावासों का निरीक्षण किया ?

(घ) क्या यह सही है कि कोटा व जयपुर डिविजन के छात्रावास का गत दो वर्ष में किस अधिकारी ने निरीक्षण नहीं किया ?

(ड) क्या यह सही है कि रीजनल कमिश्नर बडोदा ने नवम्बर के महिने में जयपुर छात्रावास का निरीक्षण किया था और अधिकारियों ने निरीक्षण का विवरण दर्ज कराने के लिये उनके सामने नयी इन्सपेक्शन नोट बुक रखी और उसमें ही इन्सपेक्शन नोट लिखवाया।

(च) यदि हां, तो क्या पुरानी इन्सपेक्शन नोट बुक खतम हो गई थी या गायब हो गई थी ?

श्री भोगीलाल पंडया (समाज कल्याण मंत्री)--(क) इस विभाग के अंतरगत ४१ छात्रावास चल रहे हैं जिनमें से १४ छात्रावास सरकार की ओर से, जिनमें सभी प्रकार की निःशुल्क व्यवस्था है : खाना, कपडा, पुस्तकें, बिस्तर, स्कूल फीस आदि राज्य की ओर से होती है। बाकी २७ छात्रावास स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा इस विभाग की सहायता से चल रहे हैं : जिन्हें प्रति छात्र १५ रू० मासिक के हिसाब से स्टीपेंड दिया जाता है। विस्तृत जानकारी संलग्न तालिका देगी।

(ख) सूची संलग्न है।

(ग) संलग्न तालिका विस्तृत जानकारी देगी।

(घ) नहीं।

(ड) नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया..............परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरूसिंह—यह तालिका मेरे पास नहीं पहुँची।

श्री भोगीलाल पंडया—पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष—No time to read.

श्री भोगीलाल पंडया—आपके पास भिजवा दूंगा ।

प्रश्न संख्या १७६

त० सराड़ा की नठारापाल में निकली धातु की खान का विकास

श्री सोहनलाल—क्या उद्योग एवं व्यवसाय मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) सराडा तहसील की नठारापाल में किस धातु की खान निकली है ।

(ख) उसके विकास के लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री भोगीलाल पंडया (उद्योग मंत्री)—(क) नठारा की पाल में घिया भाटा (सोप स्टोन) एवं लोहे की खानें निकली हैं ।

(ख) लोहा धातु के विकास के लिये विभागीय- प्रोसपेक्टिंग किया गया था और उसके उपरान्त क्षेत्र को मुक्त घोषित करके माइनिंग लीज देने की व्यवस्था की गई है ।

प्रश्न संख्या १८०

जागीर बन्दोबस्त इत्यादि कार्यों हेतु कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति के आधार

श्री भैरुसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि इस वर्ष सरकार द्वारा जागीर बन्दोबस्त व जागीर सम्बन्धी अन्य कार्यों में सलाह देने के लिये कुछ कानूनी सलाहकार नियुक्त किये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों को किस किस तारीख से कितने रुपये माहवार पर इस पद पर नियुक्त किया गया है ?

(ग) किन योग्यताओं के आधार पर इनकी नियुक्तिआं की गई ?

[श्री भैरूसिंह]

(घ) इन सलाहकारों के क्या काम हैं और अब तक इनमें से प्रत्येक से क्या २ काम लिया गया है ?

श्री दामोदरलाल (राजस्व मंत्री)—(क) जी हां, जागीरों के सम्बन्ध में कानूनी पैरोकार मुकर्रिर किये गये।

[ख] व [ग] जिन जिन को नियुक्त किया गया है उनके सम्बन्ध में वांछित सूचना निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	नाम	दिनांक जब से नियुक्ति हुई	वेतन	योग्यता
१.	श्री इस्माइलअली ऐडवोकेट	२३, ६, ५५	४०० रु०	१० वर्ष अफ्रीका में और १२ वर्ष से उदयपुर में प्रेक्टिस कर रहे हैं।
२.	श्री हरिश्चन्द्र एडवोकेट	२३, ६, ५५	,, ,,	१६४० से यानी १६ वर्ष से प्रेक्टिस कर रहे हैं।
३.	श्री शतानन्द शर्मा एडवोकेट	२३,६, ५५	,, ,,	१६२८ से यानी २८ वर्ष से प्रेक्टिस कर रहे हैं।
४.	श्री नाथूलाल जैन ऐडवोकेट	२, ६, १६५५	,, ,,	१० वर्ष से प्रेक्टिस कर रहे हैं।
५.	श्री पूरनचन्द्र ऐडवोकेट	१३, १२, ५५	,, ,,	७॥ वर्ष से।

(घ) जितने भी मुआवजे के दावे सरकार को प्रस्तुत किये जाते हैं उनकी जांच जिलाधीश के कार्यालय में तथा जागीर कमिश्नर के कार्यालय में आवश्यकतानुसार जागीर एडवाइजर्स से कराई जाती है। मुआवजा सम्बन्धी कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें सरकार के हकों की रक्षा करने के लिये कानून के अच्छे जानकार अनुभवी वकील की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक डिविजन के कानून व रिवाज से परिचित वकील ही ठीक करा सकता है क्योंकि

[श्री दामोदरलाल व्यास]

जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट के अनुसार जागीर कमिश्नर को एक अदालत की हैसियत से निर्णय देते हैं। जागीर कमिश्नर के फैसले की अपील भी सरकार या जागीरदार की तरफ से रेवेन्यू बोर्ड में हो सकती है, वहां भी सरकार के पक्ष का समर्थन करने के लिये वकील की आवश्यकता है।

डिविजन वार मुआवजे के दावे इस प्रकार प्रस्तुत हुये हैं।

जयपुर ७१७

उदयपुर १८५८ [२०० रु० से ऊपर आय वाले ठिकाने जब्त हुये इसलिये संख्या ज्यादा है।]

जोधपुर ४०५

बीकानेर ४३५

कोटा ५४६

योग ३९६४

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि अब तक इन वकीलों से अदालतों में किसी प्रकार का कार्य नहीं लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं। जितने क्लेम्स पेश हुये हैं उनकी स्क्रुटनी करके लाखों रुपयों के ऐतराज पेश किये गये हैं।

श्री भैरूसिंह—क्या सरकार ने उनकी नियुक्ति के समय खास बात यह देखी है कि वे सब वकील हों ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं। उनकी पिछली योग्यता, रेवेन्यू के काम की जानकारी देखी गई है।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि सरकार ने उनकी योग्यता का आधार कई वर्षों की प्रेक्टिस माना है।

श्री दामोदरलाल व्यास—रेवेन्यू कोर्ट्स में प्रेक्टिस को खास ध्यान रखा गया है। रेवेन्यू के मामलों में अनुभव और जानकारी का खास ध्यान रखा है।

श्री भैरूसिंह—अनुभव और जानकारी का क्या क्राइटेरिया रखा गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उनके अनुभव और जानकारी का पता लगाया गया।

श्री भैरूसिंह—क्या यह सही है कि जो लोग रेवेन्यू कोर्टस में प्रेक्टिस करते हैं और इन्कमटेक्स देते हैं उनको इन लोगों की बनिस्पत जानकारी ज्यादा है, क्योंकि इन्कमटेक्स इनकम का माप डंड है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इनके योग्यता को जानकारी करके फिर उनको रखा गया है।

श्री जसवन्तसिंह—श्री शतानंद शर्मा १६२८ से प्रेक्टिस कर रहे थे, यह सूचना किस आधार पर आपने प्राप्त की।

श्री दामोदरलाल व्यास—जो सूचना दफ्तर से प्राप्त हुई उसके अनुसार सन् २८ से ४१ तक उन्होंने प्रेक्टिस की और फिर सन् ५० से कर रहे हैं।

श्री जसवन्तसिंह—१५ वर्ष तक वे कहां गायब हुये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जो सूचना सदन के सामने प्रस्तुत की गई है वह कहां से उपलब्ध की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सरकारी सूत्रों से।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस सिलसिले में उन सम्बन्धित व्यक्तियों से कोई स्टेटमेंट लिया है कि जो इतला दी जा रही है वह सही है।

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां, जानकारी करली है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने ऐसा कोई क्राइटेरिया मुकर्रर करके लिस्ट बनाई थी जिसमें से ये व्यक्ति सिलेक्ट किये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह क्राइटेरिया था कि पुराने ऐडवोकेट्स हों और उनको रेवेन्यू का एक्सपीरियेन्स हो। यह पोस्ट आर जी तौर पर १ साल के लिये क्रीएट की गई थी इसलिये सिलेक्शन के लिये कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं समझी गई और जिनको योग्य पाया गया लोगों को सिलेक्ट कर नियुक्त किया गया।

श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि सतानन्द कितने साल तक प्रेक्टिस से कट ऑफ रहे ? उनका कितने साल का एक्सपीरियेन्स रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, मगर यह जरूर कह सकता हूं कि पुराने काफी तजुर्बेकार हैं।

श्री भैरूसिंह[१६]—क्या सरकार की जानकारी में था कि जिन लोगों को नियुक्त किया उनकी आमदनी ४०० रुपये से कम थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उनके प्रेक्टिस की आमदनी का मुझे मालूम नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इनको लेने से पहले किसी से सलाह मशौदा किया।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने कहा है कि इसकी जानकारी की गई थी।

श्री मानसिंह महार—यह जानकारी किससे की गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सरकारी क्षेत्रों से।

Page No 41

श्री श्रीदास गोयल—क्या जब वकीलों को लिया गया उस समय बार एसोसियेशन से भी उनके अनुभव आदि के लिये पूछा गया था।

श्री दामोदरलाल व्यास—इसको कोई जरूरत नहीं थी।

श्री केसरीसिंह—क्या सरकार के पास गजटेड ऑफिसर्स मुकर्रर करने के लिये नहीं थे जिससे कि इनको मुकर्रर किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने जैसा बताया कि कोई कानूनी मसला आ गया। जागीर कमिश्नर या उसके ऑफिसर तो अदालत की हैसियत से फैसला करेंगे इसलिये ऐसे योग्य वकील होने चाहिये जो सरकारी पक्ष के इन्ट्रेस्ट का बचाव कर सकें; इसलिये उनको नियुक्त किया गया।

श्री केसरीसिंह—कानूनी जानकारी का क्या कोई आधार था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सरकार एक साथ किसी को प्रोसीक्यूटर और जज बनाना नहीं चाहती। इसलिये अपने इन्ट्रेस्ट के वाच करने के लिये इनकी नियुक्ति की गई।

श्री केसरीसिंह—क्या जिन लोगों को लिया गया है वे सब कांग्रेस के सदस्य हैं ?

श्री अध्यक्ष—The question-hour is now over.

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकारी तनख्वाह पाने वाले और सरकारी काम करने वाले सरकारी ऑफिसरों में कानूनन क्या फर्क पड़ता है ? Both are trained by Government and briefed by Government.

श्री दामोदरलाल व्यास—इसमें वर्क करने और तनख्वाह पाने का कोई सवाल नहीं, तहसील से कागज आते हैं और कलेक्टर के पास उनको एतराज करना पड़ता है। इसलिये वकील मुकर्रर किये गये।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि उनको प्राइवेट प्रेक्टिस करने की भी आज्ञा है ?

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—अल्पकाल सूचना प्रश्न, श्री कंवरलाल जेलिया।

कोटा शहर में पेय जल का प्रबन्ध करने सम्बन्धी

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि इन दिनों कोटा शहर में पीने के पानी की व्यवस्था संतोषप्रद नहीं है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त असंतोष के क्या कारण हैं और उनके समाधान के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या सामयिक कदम उठाये गये हैं ?

(ग) क्या आगामी गर्मी के मौसम से कोटा में पीने के पानी की व्यवस्था संतोषप्रद हो सकेगी ?

(घ) क्या वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन इन दिनों में हुआ है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक नागरिक को नया (कनेक्शन) नल लगाने की आज्ञा उदयपुर से लेनी पड़ती है और इससे स्थानीय जनता को काफी असुविधा होती है ?

(ङ) यदि हां, तो इस असुविधा को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—(क) सही है।

(ख) इसका मुख्य कारण पर्याप्त मात्रा में बिजली पानी पम्प करने के लिये नहीं मिलना है। इसके अतिरिक्त कोटा की जल वितरण योजना सन् १९२३ में कार्यान्वित हुई थी, जब कि शहर की आबादी ३५,००० थी जो अब बढ़ कर लगभग एक लाख तक पहुँच गई है।

(ग) चीफ इन्जीनियर बिजली विभाग नये इन्जिन इत्यादि खरीदने का प्रबंध कर रहे है। जहां तक निर्माण विभाग का प्रश्न है कोटा के वाटरवर्क्स का पूर्ण रूपेण पुनर्गठन किया जा रहा है। १८ लाख रू० की योजना इसके लिये स्वीकृत हो चुकी है और कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) आगामी गर्मी तक स्थिति में कोई विशेष सुधार होने की आशा नहीं है।

(ङ) जी हां।

(च) जी नहीं, कनेक्शन के लिये प्रार्थनापत्र कोटा में एसिस्टेन्ट इन्जीनियर वाटर वर्क्स के समक्ष प्रस्तुत किये जाने चाहियें।

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कंवरलाल जेलिया—सरकार द्वारा इंजिन की व्यवस्था की गई है, क्या यह व्यवस्था गर्मी के पहले संभव हो सकेगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—मैंने बताया कि इसके लिये टेन्डर मांगे गये हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—टेन्डर आने में काफी समय लगेगा, तब तक के लिये सरकार क्या प्रबन्ध करने की सोचती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—मैंने बताया कि कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है। टेन्डर आ चुके हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—कोटा में नल लगाने के लिये आज्ञा उदयपुर से लेने की व्यवस्था क्यों की गई ?

श्री अध्यक्ष—आप कोटा से उदयपुर आ गये।

श्री रामचन्द्र चौधरी—पहले इसका बिजली विभाग से सम्बन्ध था और अब उसका सम्बन्ध पी. डब्ल्यू. डी. से हो गया है। इसके इन्जीनियर उदयपुर में हैं।

श्री अध्यक्ष—Yes. Counting of votes of the Public Accounts Committee and the Estimates Committee will start from 3.00 P. M. to-day.

एक माननीय सदस्य—It may be started now.

श्री अध्यक्ष—Or earlier, just as it is convenient. At any rate it will start from 3.00.

श्री मथुरादास माथुर—Let it start just now.

श्री अध्यक्ष—We had fixed formerly at 4.00.

श्री मथुरादास माथुर—It may be started now, so that it may be finished by five.

श्री अध्यक्ष—It can be started just now if the members so desire.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

Let it be 1 o'clock. It will start at 1.00.

श्रीदास गोयल।

(अनुपस्थित)

श्री मोतीलाल चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मेरे एडजोर्नमेन्ट मोशन का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—I did inform that it had been rejected. Adjournment motions cannot be accepted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष—शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन दे दीजिएगा ?

(अनौपचारिक चर्चा)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य

राव राजा श्री सरदारसिंह—अध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं लेकिन समय की बचत के लिये मैं एक ही साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष, प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है और दूसरी पंचवर्षीय योजना सन् १९५६-५७ के बजट के करीब साथ ही साथ लागू होती है। इस बजट को देखने से मालूम होता है कि १९५५-५६ में उनियारा से टोंक की सड़क जो एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है उसको बिल्कुल ही ओवरलुक कर दिया गया है, मिसाल के तौर पर, माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि ५५-५६ में टोंक से उणियारा अलीगढ़ और माधोपुर सड़क रखी गई थी और माधोपुर से अलीगढ़ टोंक सड़क मंजूर हुई थी। अब १९५६-५७ के बजट में माधोपुर से टोंक उणियारा तक सड़क ही रखी गई है। इससे मालम होता है कि पहले तो यह था कि दोनों सड़कों से टोंक से

[रावराजा श्री सरदारसिंह]

माधोपुर और माधोपुर से उणियारा आकर मिलती थी। अब माधोपुर से उणियारा तक ही आकर खत्म हो जायगी। उणियारा से आगे सड़क नहीं बनेगी, इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह कि माननीय मंत्री महोदय नये आये हैं या उनके मित्र लोगों ने उनको कह दिया होगा कि उणियारा तक की सड़क पहले ही तैयार हो गई, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर गलती से रह गई है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह दुरस्त करें, उणियारा की सड़क के बारे में हमारे टोंक में वक्तन फक्तन मिटिंगें होती रहती हैं और यहां तक कि टोंक डिस्ट्रिक्ट के नेता लोग भी इस ओर बराबर ध्यान आकर्षित करते रहते हैं।

Bhonwarlal Tambi informed that the road sanctioned in the first Five Year plan from Tonk to Uniara and from Malpura to Seola have not yet been completed.

इससे यह मालूम होता है कि अब तक वह सड़क तैयार नहीं हुई है। मुझे यह देखकर देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उणियारा तक तो माधोपुर सड़क बन जायगी और उणियारा से आगे नहीं बनेगी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसको जल्दी पूरा कराने की कोशिश करें और अगर किसी कारणवश इसको ओवरलुक कर दिया है तो ठीक करेंगे, नहीं तो यह टोंक की जनता और उणियारा की जनता के साथ अन्याय होगा।

माननीय अध्यक्ष, मैंने दो चार दिन पहले एक महत्वपूर्ण सड़क के बारे में निर्माण मंत्री से प्रश्न किया था। टोडा नासिरदा थावला नेगडिया के बारे में तो माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में इसको रखा तो गया था, लेकिन किसी कारण वश वह कार्य नहीं हो सका। मेरा उनसे निवेदन है कि इसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो रखा होता लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि बजट में इस सड़क का नाम-निशान तक नहीं। न मालूम किस तरह से यह सड़क बन जायगी, क्या कोई ऐसा गुप्त फंड है जिसमें चुपके चुपके पैसा लेकर सड़कें बनवा ली जायंगी या शायद नये इलेक्शन आ रहे हैं तो उस समय किसी को जिताने के लिये बनाई जायंगी। भाई साहब इस बजट में तो रखते ताकि सब को मालूम तो हो जाता।

तीसरी बात यह है कि दूनी तहसील नई क्रिएट हुई है। दूणी तहसील के अन्दर सरोली से होते हुए नावा तक सड़क की तजवीज थी। वहां सरकारी तहसील है, जहां सड़क का बनना बहुत आवश्यक है। चौमासे में वहां की जनात को तकलीफ होती है। बनास में कई आदमी बह जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नासिरदा से दूणी से आगे की सड़क बहुत जरूरी है और महत्वपूर्ण है। इस ओर ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है।

डेवलपमेन्ट ब्लॉक्स की बाबत टोंक डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के लिये और डेवलपमेन्ट ब्लॉक के लिये और एन. ई. एन. ब्लॉक के लिए कोई स्थान उपयुक्त नहीं समझा गया। सिर्फ मालपुरा ही एक

[रावराजा श्री सरदारसिंह]

ऐसा स्थान समझा है जहां डेवलपमेंट ब्लॉक व एन.इ.एस ब्लॉक खोले गये खोले गये। जबकि सरकार सामाजवाद कायम करना चाहती है तो मालपुरा ही क्यों, अब तो वह धाप हो गया होगा। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में दूसरों का नम्बर भी आने दिया जाय। इसमें जितनी भी रकम खर्च की जाती है उसमें सबको बराबर हिस्सा मिलना जरूरी है और यही मेरा नम्र निवेदन है। सड़कों के लिये, ब्लोकस जिसका जितना हिस्सा हो उचित रूप में मिलना चाहिये। इस वास्ते मैंने अपने तीनों कटौती के प्रस्ताव रखे हैं ताकि मंत्री महोदय ध्यान दें। इस तरह इस आशा के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव करता प्रस्तुत हूं कि यह उपरोक्त कार्य जल्दी सम्पूर्ण कराने की कृपा करेंगे।

श्री प्रभुदयाल—अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव दो हैं, मैं उन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ। मांग संख्या २३, विषय ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १रू० की कटौती करदी जाय। (द्वितीय पंच वर्षीय योजना में चुरू जिले के साथ की गई उपेक्षा पर विचार करने हेतु)

दूसरा मांग संख्या २३, विषय ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १ रू० की कटौती कर दी जाय (बीकानेर डिवीजन में सडकों की कमी पर बहस करने के लिये)

अध्यक्ष महोदय, सडकों के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। राजगढ़ से तारा नगर सडक के लिये कोई स्कीम नहीं है। राजगढ से तारानगर रोड करीब १२. १३ साल पहले बनी थी। इसके बारे में मैंने असेम्बली में प्रश्न भी पूछा था और उसमें मुझे यह आश्वासन दिया जाता रहा कि इन सालों में सडक बन जायगी। प्रथम पंच वर्षीय योजना समाप्त हो गई, द्वितीय पंच वर्षीय योजना चालू होने वाली है उसमें बन जायगी ऐसा आवश्वासन दिया गया है लेकिन मैं जब बजट को देखता हूँ तो यह मालूम होता है बजट में कोई प्रोवीजन नहीं रखा गया है। बहुत सी सड़कों के नाम हैं; वह करीब १०० के मैं गिना सकता हूँ। राजगढ से तारानगर की सडक से लाखों रूपयों की सरकार को आमदनी होती है। यह सडक जब से बनी है मैं समझता हूँ कि कंकर तक नहीं कुटवाये गये हैं। जब भी मैंने इस बारे में असेम्बली में प्रश्न पूछा तो वहां पर रेत डाल दी गई और कह दिया गया कि मरम्मत करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहूंगा इस प्रकार की जो हरकतें अधिकारी वर्ग करते हैं मैं चेलेन्ज के साथ कहता हूँ वहां सड़क पर केवल रेत डालने के कुछ काम नहीं किया। अगर इसमें गलती हो तो मैं चेलेन्ज स्वीकार करता हूँ, इसमें जिन २ अधिकारियों ने अवैधानिकता बरती है उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाना चाहिए।

राजगढ़ से सिद्धमुख की सड़क की एक दूसरी स्कीम थी, उसका भी पता नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बहुत बेकवर्ड एरिया है, यहां कोई नहर आने वाली नहीं है। अगर राजगढ से सिद्धमुख की सड़क बना दी जाय तो यह इलाका भाखरा नहर से मिल जायगा। यहां हर चौथे पांचवें साल अकाल पडता रहता है, अनाज की बड़ी समस्या रहती है। ऐसी अवस्था में यदि यह सडक बन जाती है तो भाखरा नहर से इसका ताल्लुक हो जायगा और अनाज आदि का आवागमन भी सुचारू रूप से हो सकता है। यहां व्यापार, बिजनेस भी बहुत अच्छा हो सकेगा। वहां पर २०-३०

[श्री प्रभुदयाल]

हजार रूपये का सामान पड़ा हुआ है, कंकर वगैरह इकट्ठा किये हुए हैं लेकिन इस सड़क के लिये कोइ स्कीम नहीं रखी गई है। इस स्कीम को रखते तो इस पैसे का सदुपयोग हो सकता था। दुख के साथ कहना पडता है कि इस स्कीम को जो बेकवर्ड एरिया है यहां आवागमन के साधन नहीं हैं। पानी यहां का खारा है, अनाज आराम से पहुँच पाता। यदि यह रोड बन जाती है तो जनता को बहुत आराम मिल जायगा और अनाज वगैरह की सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये।

तारानगर दूधवा खारा के लिये पिछली पंचवर्षीय योजना के अन्दर दो तीन साल में यह पैसा बराबर खर्च होता रहा है। करीब पचास हजार के खर्च हो चुका है। है। अगर इस साल यह कार्य शुरू कर दिया जाता तो यह पैसा अच्छे काम में लग सकता था, पर इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि इस ओर विशेष तौर से ध्यान दिया जावे तो सरकार का पैसा भी बच सकता है।

दूधवाखारा से चुरू के लिए सडक नहीं है। काफी अरसे से मांग की जा रही है, वह बहुत बडा गांव है। पानी की भी बड़ी समस्या है। अगर इस स्कीम को ले लिया जाता तो गांव की तरक्की हो सकती थी।

लेकिन बडे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सारे बजट में इस गांव का नाम भी नहीं है।

चुरू से बिसाऊ के लिये, इस रोड के लिये टेन्डर किसी के नाम से मन्जूर हुए और अब सड़क किसी ठेकेदार के नाम से मन्जूर हुई है। मैं नहीं समझ सकता कि क्यों ऐसा हुआ ? उसके नाम से रिजेक्ट होने का कारण क्या था ? यह जनता के साथ में मखौल किया जा रहा है। इस विभाग में इस तरह का करप्शन हो रहा है; पहले टेन्डर मन्जूर कर लिया जाता है और बाद में रिजेक्ट करके दूसरे को दे दिया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि खाने को कुछ मिला नहीं, इसलिये रिजेक्ट कर दिया गया है।

ददरेवा सिद्धमुख के लिए सड़क बन जाती है तो नहरी इलाके से आवागमन का साधन हो सकता है, व्यापार अच्छा चल सकता है, नाज मिल सकता है; नहीं तो यह इलाका पिछडा हुआ रह जावेगा। इसको भी इस योजना में ले लिया जाता तो सुन्दर होता। वहां बहुत बड़ा मेला भी लगता है। वहां गोगाजी नामक बहुत बड़े देवता भी हुए हैं। हजारों लाखों की तादाद में आदमी भी वहां इकट्ठे होते हैं। पशुओं का भी मेला लगता है। इससे सरकार को भी आमदनी हो सकती है, बिजनेस भी अच्छी तरह से चल सकता है।

(घंटी)

नोखा से पांचू के लिये सड़क की जरूरत है। पांचू बहुत बड़ा गांव है। सरकार जब सड़कों का निर्माण करने जा रही है तो एक तहसील हैड क्वार्टर से तो इतने बड़े गांव को मिला

देना चाहिये था। इसके लिए नहीं करने से बड़ा अफसोस है। कम से कम उस गांव की तरफ आप दौरा करने को जब पधारें तो मालूम होगा कि कितना बड़ा वह गांव है। अगर मेरी सूचना गलत निकले तो मुझे चाहे जितनी सजा दे सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस ओर गौर फरमावेंगे।

कोलायात से बाप के लिये।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—सारी सड़कों का इन्तजाम हो रहा है ?

श्री प्रभुदयाल—दो चार और बाकी हैं। कोलायात से बाप के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में ढाई लाख की मन्जूरी हुई थी। पर दुख है कि करीब १०।१५ हजार रूपये ही उसमें से खर्च किये गये, बाकी पैसा लैप्स हो गया। मैं नहीं कह सकता कि उन पैसों को किस तरह से खर्च किया गया ? कितनी मुश्किल से पैसा मिलता है, मांग मन्जूर होती है पर इन विभाग वालों की लापरवाही से उस पर पानी फिर जाता है। ऐसे अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये, जो ढील करते हैं और पब्लिक के लिए दिक्कतें पैदा करते हैं।

कोलायत से नोखा के लिए। कोलायत पिछड़ा इलाका है। नोखा तहसील है। यह सड़क बन जाती है तो यह एक अच्छी चीज हो जाती है और तहसील हेडक्वाटर से मिलान हो जाता है।

मेरा प्रस्ताव है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। नोखा कक्कू साकड़ा के लिए सड़क बननी चाहिये। नोखा का मारवाड से मिलान हो जाता है। इसलिये प्रार्थना है कि इस पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाना चाहिये। पर इस स्कीम में इनका नाम भी नहीं है

(घंटी)

बीकानेर से कालू के लिये। कालू अच्छा कस्बा है, वहां डिस्पेन्सरी है, हाई स्कूल भी है, पर बीकानेर से मिलाने के लिए कोई प्रोवीजन नहीं रखा गया। कम से कम इस गांव को मिला दिया जाता है तो जनता को काफी आराम मिल सकता है।

(घंटी)

मैं पांच मिनिट और बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष—Order ! मैंने वार्निग के लिये दो बार घंटी बजाई थी। सब की अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। एक साथ कह सकते हैं कि इन सड़कों पर कुछ काम नहीं हुआ। एक एक

Page No 49

[श्री अध्यक्ष]

सड़क का गुण गान कर रहे हैं। अगर इस तरह से बोलेंगे तो एक ही मांग पास हो सकेगी। नहीं तो बाद में सब पर गुलेटिन लगाना पड़ेगा, तो आप अपनी स्पीच को शोर्ट करिये, विषयान्तर मत जाइये।

श्री प्रभुदयाल—मैं बिल्डिंग के बारे में बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष—Order please ! (घंटी) श्री भैरूसिंह, श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, सिविल वर्क्स के मद पर मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। इसके अन्दर कुछ कहूँ, इससे पहले मैं अपने कटौती के प्रस्ताव आपके सामने पेश कर दूं मेरे कटौती के प्रस्ताव इस प्रकार हैं।

"To discuss the failure of Government to repair the old roads and construct newones in Tehsils Jamua Ramuarh and Amber"

यह जो पहला कटौती का प्रस्ताव है उसको पहले ले लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तहसील जमवा रामगढ राजस्थान में ऐसी तहसील है कि जिसके अन्दर सड़क के निर्माण कार्य में प्रथम पंचवर्षीय योजना में एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया।

यह बहुत ही पहाड़ी इलाका है। इसमें यातायात के साधन बहुत कम हैं। ये सब बातें होते हुए भी सरकार ने इसके लिए उचित नहीं समझा कि इसमें एक भी सड़क नई चालू की जावे। इस तहसील के अन्दर यह बहुत आवश्यक है कि तहसील के अन्दर के इलाकों को प्रत्येक को एक दूसरे से जोड़ा जावे और यातायात के साधन उनके लिए सुलभ किये जावें ? पर में नहीं समझता कि क्या वजह थी कि इस इलाके की क्यों इतनी उपेक्षा की गई। पर यह कटौती का प्रस्ताव मैंने इस नीयत से रक्खा है कि आइन्दा योजना के अन्दर और इस वर्ष में भी सरकार कुछ थोड़ा बहुत कर सके तो अच्छा होगा। यह तो मैंने तहसील जमवा रामगढ की नई सड़कों के बारे में कहा।

पुरानी सड़कों के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर से रामगढ जो कि तहसील का हैड क्वार्टर है और रामगढ बन्धे तक जो कि विजीटर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है और जहां से जयपुर को रोजाना पानी मिलता है पीने का, वहां की जो सड़कें हैं, वे कई वर्षों की बनी हुई हैं। उनकी अगर, अध्यक्ष महोदय, आज की हालत देखेंगे वो वह ऐसी दयनीय हालत है कि जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि मन्त्रीजी यह फरमायेंगे कि उसमें काम शुरू कर दिया गया है, मगर आपका काम इस धीमी रफतार से हो रहा है कि आपने जहां से काम शुरू किया है और जिस रफतार से आप इस १८ मील के टुकड़े को रिपेयर करने में लगे हुए हैं वह

[श्री मानसिंह महार]

इतनी धीमी रफ्तार है कि जो काम आपने आज शुरू किया है वह टूट जायगा, तब तक वह काम पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए इसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि यह बहुत इम्पोर्टेन्ट सड़क है और इस पर सरकार को अवश्य ध्यान देकर बहुत जल्दी रिपेयर करना है। उस सड़क की हालत बहुत खराब है।

अब मैं तहसील आमेर की तरफ जाता हूं। वहां पर एक विशेष परिस्थिति है। मैं मानता हूं कि उस इलाके से एक उपमंत्राणीजी आई हैं, लेकिन फिर भी मुझे यह कहना पड़ता है चोमू से सामोद तक की सड़क जो कि चोमू और सामोद के ठिकानों ने बनाई थी, उस सड़क की बहुत ही दयनीय हालत है। उस सड़क की ऐसी हालत है, उसके बारे में मैं असलियत वर्णन करूं तो शायद अध्यक्ष जी मुझे बिठा दें इस लिए यह कह कर ही सब्र कर लूं कि उस सड़क की खराब हालत है और वह खराब हालत इस वजह से है कि जब से ठिकानों से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने सेस लेना शुरू कर दिया तब से उसको ठीक करवाना ठिकानों ने बन्दकर दिया है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सेस देते हैं तो अब सड़कों को क्यों सुधारा जाय? सामोद ठिकाने को रिज़्यूम किये हुए दो वर्ष हो गये हैं। इन दो वर्षों में सड़कों की हालत सुधरना तो दूर रहा, सड़क के दोनों तरफ गड्डे हो गये हैं कि जिनमें अगर मोटर लारियां गिर जांय तो मैं यह समझता हूं कि कोई आदमी उस लारी में ऐसा नहीं होगा कि जो कि उन खड्डों में से जिंदा निकल सके। ऐसी हालत सड़कों के दोनों तरफ हो गई है। ऐसी दयनीय दशा उस सड़क की है कि जिससे सरकार को एक लाख रुपये प्रति वर्ष मिल जाता है उस खान से जिससे लोहा स्टेशन को ले जाया जाता है। वह उसी सड़क पर होकर आता है। उस सड़क पर बीसों ट्रक चलते हैं और करीब २४० लारियां चलती हैं। लारी वालों से भी काफी मोटा मोटा टेक्स लिया जाता है और ट्रक वालों से भी टेक्सेज लेते हैं और उस लोहेकी खान से एक लाखरुपये साल के लेते हैं, लेकिन फिर भी यह सरकार नहीं सोचती है कि उस सड़कको बनाया जाय। बनाना तो दूर रहा वहां पिछली बरसात में जो १००, १००और ८०, ८० फुट के गड्डे बिल्कुल सड़क के पास हो गये हैं उनको सुधारने की भी गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए भी, माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि यदि सड़क की मरम्मत कराई जायगी तो बहुत ही महरबानी होगी।

इसके बाद आमेर के अन्दर नई सड़कों के बारे में निवेदन करूंगा कि पिछली पंचवर्षीय योजना में एक सड़क चोमू से अमरसर बनाने का प्रोपोजल पास हो गया है। साल भार बाद सुना कि टेंडर्स मंजूर हो गये हैं, अब यह हो गया है, अब वह हो गया है, लेकिन आज तक एक पैसे की प्रगति इस सड़क के लिये नहीं हुई है। आज तक कोई काम नहीं हुआ है। यह आशा करूंगा कि यह भी बड़ा इम्पार्टेंट कार्य है जिसकी सरकार व्यवस्था करेगी।

नई सड़कों के बारे में न जाकर दूसरे कटौती प्रस्ताव पर आता हूं जो कि इस प्रकार है:—

[श्री मानसिंह महार]

"That the Demand No. 23 Major head 50-civil works be reduced by Re. 1/- (to discuss corruption prevelent In the Department.)".

माननीय अध्यक्ष, मेरा जो दूसरा मुद्दा है वह सारे राजस्थान के लिए महत्व का है। पहले मैंने अपने क्षेत्र की बात कही थी। अब मैं एक ऐसे मुद्दे पर आया हूँ जिसका पूरे राजस्थान पर असर है। मैं यह मानकर चलता हूं कि पी. डब्लू. डी. के इस विभाग को हम लोग जयपुर लेजिस्लेटिव कौन्सिल में प्लन्डर विदआऊट डेन्जर का डिपाटमेंन्ट कहा करते थे। उसमें आज भी हाल चल रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान बनने के बाद और ज्यादा हो गया है या कम हो गया है, मैं तो यह कहता हूँ कि वही पुरानी फ्ता है जो कि राजा शाही के जमाने में थी, उससे कुछ परसेन्टेज बढ़ गई हो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का अलग समय आगया है और दूसरी बातें आ गई हैं कि कई प्रकार के एन्टीकरप्शन बोर्ड बना दिये गये हैं। एन्टी करप्शन बोर्ड का परसेन्टेज हो सकता है। पंचवर्षीय योजना बनाने वालों का कुछ हो सकता है और भी कई साधन हैं, वह बढ़ गये हैं। इसलिये वह परसेन्टेज भी बढ़ गया होगा, घट नहीं सकता हैं, ऐसी सूरत में मैं मानता हूँ कि जो परसेन्टेजे लगे तो ५० परसेन्ट आपके प्रत्येक काम का मिनिमम आपके लिए खर्च न हो कर और लोगों की जेबों में चला जाता है। यह निश्चित बात है। इस बात से कोई मुकर नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि गंगापुर के प्राइमरी स्कूल के मामले में इन्जनियरों का जो मामला जिस प्रकार की ढिलमिल नीति से खत्म किया गया, उसके बाद तो इन्जीनियरों के हौसले और भी बढ़ गये हैं, और अब तो काम इतना खुल्लम खुल्ला होने लगा है कि जिसकी कोई हद नहीं है।

लेकिन यह बात कह कर मैं यह समझता हूँ कि इसमें एक-दो अच्छाइयां भी हैं। बुराइयां करने से ही काम नहीं चलता है, अगर अच्छाइयां हैं तो वे बतानी चाहिये। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस विभाग के जो चीफ इन्जीनियर है वे एक राजस्थानी हैं। यद्यपि वे कुछ लेंगे तो रहेगा राजस्थान में। इसके अलावा मैं राजस्थान सरकार को बधायी देता हूँ कि उन्होंने एक राजस्थानी को चीफ इन्जीनियर के पद पर रखा है। दूसरी बात, जो उन्होंने हमारे सामने बड़े न्याय का नमूना रखा है कि एम. एल. एज. के क्वर्टर्स का किराया निश्चित किया है उसमें उन्होंने न्याय किया है। इसके लिए मैं उनको बधाइ देता हूं क्योंकि लोगों में यह फुसफुसाहट थी, कोई कहता था कि २०रु होगा, कोई कहता था कि २५रु महावार होगा, लेकिन उन्होंने ५०रु और ६५रु निश्चित किया है। इसलिए यह महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने अपने सामने रखा है यह बड़ी हिम्मत का काम किया है और इसके लिए मैं उनको जरूर बधाई देता हूँ। यह दो तीन बातें अच्छाई की हैं, इसलिए उनको यहां कहना अनुचित नहीं होगा।

तीसरा मेरा कटौती प्रस्ताव जो है वह यह है कि :

"That the demand No- 23 Major Head 50-Civil Works be reduced by

[श्री मानसिंह महार]

by Re 1 -(To discuss the step moatherly treatment shown to Jaipur District in the 2nd Five year Plan vis a vis' the First plan)."

माननीय अध्यक्ष, मेरी यह धारणा रही है कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट रहा है, और इसकी पोपुलेशन बहुत है। जैसा कि इसी आशय का एक कटोती प्रस्ताव परबतसर से आये हुये मेरे माननीय मित्र ने रखते हुए कम्पेयर करके बताया था कि कोटा डिविजन और उदयपुर डिविजन में उनकी पोपुलेशन और एरिया के आंकड़े एक हो गये हैं। वह तो डिविजन है और हमारा यह एक डिस्ट्रिक्ट है। यह होते हुये भी जिस वक्त पैसे के बंटवारे का प्रश्न आता है तो वे डिवीजन के नाम से पुकारे जाते हैं और दुर्भाग्य से डिस्ट्रिक्ट के नाम से पुकारे जाते हैं। इसलिये उसके डिस्ट्रिक्ट होने से उन डिविजनों से आधे से भी कम पैसा उसको मिलता है।

श्री कंवरलाल जेलिया—जयपुर राजधानी तो है।

श्री मानसिंह महार—मैं जो कुछ अध्यक्ष महोदय, कहता हूँ वह राजधानी की नजर से नहीं कहता हूँ, क्योंकि राजधनी जो है वह सारे राजस्थान की है, वह जयपुर डिस्ट्रिक्ट की अकेली की नहीं है। जयपुर शहर के लिए जो कुछ करते हैं, वह सारे राजस्थान का काम है वह अकेले का काम नहीं हैं, जयपुर डिविजन या जयपुर डिस्ट्रिक्ट का। यह गलतफहमी है लोगों में कि जयपुर राजधानी है और सब कुछ जयपुर में हो रहा है। सही तरीके से जांच कराइये और प्रत्येक काम को ले लीजिये, उस संबंध में मेरी समझ में नहीं आता। आप स्कूलों के मामले को ले लीजिये, वेटरनरी का मामला ले लीजिये, या और ऐसे जितने निर्माण के कार्य हैं उनको आप ले लीजिये, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ जितना अन्याय हो रहा है आज राजस्थान या जयपुर डिविजन के बाहर के किसी डिस्ट्रिक्ट के साथ नहीं हो रहा है। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जयपुर डिस्ट्रिक्ट को जयपुर शहर की वजह से सफर करना पड़ रहा है। जयपुर शहर के अन्दर सारे काम होते हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अन्दर कोई काम नहीं होता है। जयपुर राजधानी होने के कारण हमको सफर करना पड़ता है, यह सरासर अन्याय है। हमारे यहां के गांवों में कहीं भी आप देख लीजिये अध्यक्ष महोदय, कि न तो एक डिस्पेन्सरी है. वेटरनरी डिस्पेन्सरी से मेरा मतलब है। हमारे यहां एक नयी सड़क नहीं बनी है। अगर कोई डिफेन्स के लिए ऑल इन्डिया सड़क बन गई तो वह हमारे लिये नहीं है। सरकार ने कोई नयी सड़क बनाने का काम किया हो तो मैं कहूं कि यह बात उचित है। डेवलपमेंट में और डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में, काम कम मिलता है, कहते हैं कुछ नहीं कर सकते। तहसीलों में पैसे का बंटवारा होता है तो पांच पांच, दस दस हजार पर आकर रह जाता है। पंचवर्षीय योजना में हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ बड़ा अन्याय किया, जिसका जवाब हमारे मित्र ने डिटेल्स में दिया है और मैं उनको न दोहरा कर मैं तीन कटौती के प्रस्ताव जो सदन में प्रस्तुत कर चुका हूं, मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो मैंने चन्द बातें सदन में निवेदन की हैं उनकी ओर अवश्य वे गोर फरमावेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री कुम्भाराम आर्य।

श्री कुम्भाराम आर्य—अध्यक्ष महोदय, मेरा कटोती का प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"मांग संख्या २३, विषय ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १) की कटोती करदी जाय (कार्य व्यवस्था पर विचार करने के लिए)।"

मैंने अपना प्रस्ताव इसलिए रखा है कि सड़कों के निर्माण का कार्य जो राजस्थान के अन्दर पंचवर्षीय योजना के अनुसार चल रहा है उसमें बीकानेर डिविजन को कतई तौर से छोड़ दिया गया है। इस वर्ष के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीकानेर डिविजन के अन्दर कुल १३,४४४ रुपये एक साल के खर्चे के लिए रखे गये है जब कि दूसरे जिलों के लिए, किसी जिले के लिए २६ लाख हैं, किसी जिले के लिए १३ लाख हैं किसी जिले के लिए १५ लाख हैं और कोई छोटे से छोटा ऐसा जिला नहीं जिसमें ६ लाख से कम रकम रखी गई हो, लेकिन, एक बीकानेर ही ऐसा जिला है जिसके लिए १३,४४४) रुपये रखे हैं। यह हंसी की सी बात है कि १३,४४४ रुपये में कौनसी सड़क बन पायगी, कितनी लम्बी होगी, कितनी टार्ड होगी?

श्री चंदनमल वैद—वह सड़क किसी कमरे में बनावेंगे?

श्री कुम्भाराम आर्य—आप साहब को हो सकता है।

दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर ही नहीं किन्तु हिन्दुस्तान के अन्दर गंगानगर की मंडी का पैदावार के हिसाब से पहला नम्बर है और उस मंडी को गाड़ियों के हिसाब से देखा जाय तो, रजिस्टर देख लीजिये जिसमें गाड़ियां दर्ज हैं गंगानगर का पहला नम्बर है और यदि बैलगाड़ियों का जहां तक सवाल है राजस्थान भर की बैलगाड़ियां इकट्ठी कर ली जांय तो भी गंगानगर की बैलगाड़ियां ज्यादा मिलेंगी। उस गंगानगर जिले के अन्दर पन्द्रह मील की एक सड़क रखी गई और उसके लिए पचास हजार रुपयों का खर्चा रखा है, सारा खर्चा उस पर ६ लाख आकर पड़ेगा और इस हिसाब से चलेंगे तो १८ साल के अन्दर १५ मील की सड़क बन पायगी। मारवाड़ में एक कहावत है कि पेट भर खाना और गांव भर चलना। इस तरह से हम चलते गये तो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना कैसी होगी? सेकिंड पंचवर्षीय योजना में सात आठ करोड़ रुपया खर्च करने को मिलेगा वह दूसरी जगह जावेगा और गंगानगर जैसी उपयोगी जगह में खर्चा नहीं हो सकेगा।

उसी तरह से सारे डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिये। मैं कोई भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ किंतु मैं तो हाउस के यह बात ध्यान में दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि सड़कों की जहां आवश्यकता हो वहां होनी चाहिए और जहां आवश्यकता न हो वहां नहीं होनी चाहिए। अगर गंगानगर में पहियों की गिनती करेंगे तो गंगानगर जिला पहियों के हिसाब से सब से अधिक संख्या वाला जिला है और गंगानगर जिले में जो सड़कें बनी हैं वे जीरो हैं। पहली पंचवर्षीय

[श्री कुम्भाराम आर्य]

योजना में यह हाल हैं। सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में वही गोल जीरो चक्कर काटता है, भगवान श्रीकृष्ण के चक्कर की तरह। इसलिए इसमें न्याय किया जाय और माननीय मंत्रीजी जो बजट पास करवा रहे हैं उनसे आशा करूंगा कि वे ऐसा चाहेंगे कि इस असमानता को उन्हें मिटाना है और इसी विश्वास के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री घासीराम।

श्री घासीराम—माननीय अध्यक्ष, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए निवेदन करता हूँ कि तिजारा से टपूकड़ा की सड़क जो पहली पंचवर्षीय योजना में रखी गई है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पांच साल खत्म हो गये किन्तु २२ मील की सड़क नहीं बन पायी। यह दिल्ली रोड से मिलती है। यह इतनी जरूरी सड़क है कि तिजारा के लोगों को ५० ६० मील का चक्कर काट कर जाना पड़ता है और अगर इस वर्ष पूरी न हो पाये तो मैं आयन्दा के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको शीघ्रातिशीघ्र बना दिया जाय।

दूसरा मेरा निवेदन कोटकासिम सड़क से है। यह जयपुर स्टेट का इलाका था जो सरस के नाम से मशहूर है। कोट कासिम जाने के लिए कोई सड़क नहीं बनी हुई है। इसके लिए काफी रिप्रेजेन्टेशन्स, दरख्वास्तें वगैरा दी गई और माननीय मंत्रियों से भी निवेदन किया कि कोट कासिम पहुँचने के लिए सड़क जरूर बनाई जावे। यह पहले एस. डी. एम. की कोर्ट थी, अब सब तहसील का हैडक्वार्टर है, पुलिस स्टेशन है, वेटेरेनरी होस्पिटल है, मगर फिर भी वहां पहुँचने के लिए रास्ता नहीं है। इस सड़क को बनाया जाना जरूरी है। यह सड़क तिजारा टपूकड़ा से मिलाई जा सकती है। सात आठ मील का टुकड़ा ही बनाना है। तो इस एप्रोच से लेकर अगर इस सड़क को सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में बना दिया जायगा तो उन लोगों के साथ न्याय होगा। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कोट कासिम रोड को जल्दी से जल्दी बनाया जाकर कोटडा रोड से जल्दी से जल्दी मिला दिया जाय।

दूसरी बात जो मुझे अर्ज करना है वह यह है कि रोड पर पेड़ लगाये जा रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारे यहां जो पेड़ लगाये गये हैं, वे बर्बाद हो गये हैं और नये लगाये गये हैं वे दिन ब दिन गिर रहे हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पेड़ों की ठीक व्यवस्था करायी जाय अन्यथा उनको लगाने से कोई फायदा नहीं। इतना ही कह कर मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—डा० मंगलसिंह।

डा० श्री मंगलसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं, एक कटौती के प्रस्ताव द्वारा कि इस डिपार्टमेंट का कार्य बहुत अच्छा नहीं है, खराब हो रहा है; चाहे तो रफ्तार के

[डाक्टर श्री मंगलसिंह]

लिहाज से हो और चाहे उसकी क्वालिटी के लिहाज से हो। फाइनेन्स मिनिस्टर के अथवा दूसरों के भाषणों में बताया गया है कि सड़कों के लिए और मकानों के लिए बहुत सा रुपया मंजूर किया गया है। राजस्थान सरकार ने अपनी ओर से और केन्द्रीय सरकार से भी धन लेकर सड़कों के ऊपर बहुत रुपया खर्च किया है और सड़कें भी बहुत सी बनी बतायी हैं। प्रश्नोत्तरों के समय भी यही बताया जाता है कि इतनी लम्बी सड़कें बन गई हैं। लेकिन जितने सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव मेरे पहले रखे है लगभग सभी ने यही कहा है कि हमारे जिले में सड़क नही बनी; हमारे जिले के साथ सौतेला बरताव किया गया, हमारे जिले में प्रथम पंच वर्षीय योजना के समय सड़क नहीं बनी और नाही अब बन रही है आदि आदि। तो फिर आखिर वह रुपया गया कहां ? एक ओर यह कहा जाता है कि ये ये सड़कें बना दी गई हैं और इतनी लंबी सड़कें बन गई हैं और दूसरी ओर इतने जिलों से आने वाले सदस्यों ने यह बात कही है कि हमारे यहां भी नहीं बनी, हमारे यहां भी नहीं बनी तो आखिर वे सड़कें कहां बनीं ? क्या चांद के लिए बनाई जा रही हैं या शुक्र के तारे के लिए बनाई जा रही हैं। यहां सब लोग यही कहते हैं और मुझे भी यही शिकायत है, मैं भी यही पूछना चाहता हूं।

श्री जसवन्त सिंह—मार्क्स के लिए बनी हैं।

श्री मंगलसिंह—(जारी) जी हां, यही होगा। केवल सड़कों का ही सवाल नहीं है, मकान भी बन रहे हैं उनके लिए भी रुपये मंजूर हुए हैं। लेकिन अस्पताल खोलने के लिए या स्कूल खोलने के लिए गांवों की यह सूरत है कि स्कूल के लिए मकान बना दो या अस्पताल के लिये मकान बना दो तो स्कूल या अस्पताल खोला जा सकता है। शहरों में एक एक या दो दो दस दस, बीस-बीस लाख रुपये अस्पताल बनाने के लिये और २,४ लाख रुपये स्कूल या कालेज खोलने के लिये दे दिये जाते हैं लेकिन गांवों के लिये शर्त रखी जाती है कि तुम्हारे यहां स्कूल या अस्पताल तब खोले जायगें जब कि मकान बना कर दोगे। जब ऐसी हालत है तो फिर ये रुपये कहां चले जाते हैं, इसका मुझे आश्चर्य होता है। इसमें शक नहीं कि कहीं पर थोड़ा बहुत काम हुआ है लेकिन उस काम की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैं एक सड़क के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि एक सड़क राजाखेड़ा की है जिसके लिए सन् ५०, ५१ में श्रमदान किया था और उस वक्त किया था जब श्रमदान शब्द प्रचलित नहीं हुआ था और उसके लिये ४५००० आदमियों ने काम किया था ४, ५ महीनों में। इतने बड़े काम के उपरान्त भी गवर्नमेन्ट ने पिछले ४, ५ वर्ष के अन्दर मुश्किल से पत्थर मिट्टी डाली है। पार साल ही कहा गया था कि उस पर तारकोल डाला जायगा और तार कोल वहां पहुंच भी गया था लेकिन २४ मील में से केवल ७ मील तारकोल डाल कर काम समाप्त कर रोक दिया गया है। वहां न कोई मिट्टी है और न कोई सड़क हो रही है। इस प्रकार सड़क बनाने में जनता ने पसीना बहाया और महीनों काम किया उस पर सरकार की ओर से इतना भी काम नहीं किया गया कि इस पर तारकोल डाल कर इसे पूरा किया जाता। मैं यह समझता हूं

[डा० श्री मंगलसिंह]

कि यह श्रमदान करनेवालों के प्रति घोर अन्याय है और श्रमदान करने वालों के उत्साह को कम करना है। श्रमदान करने वालों के हृदयों को ठेस पहुँचती है।

दूसरी सड़क धौलपुर से भरतपुर तक बनने को थी। वह धौलपुर से ७, ७ मील बनने के बाद बन्द पड़ी है। एक दफा उसे देखने को मन्त्री जी वहां आये थे। वहां पर उस सड़क को कई स्थानों पर ७.८इंच खुदवाकर देखा कि इसमें मिट्टी और गिट्टी कैसी है, ज्योंही मन्त्री जी ने वहां से पीठ फेरी त्योंही दो रोलर्स जो २ वहां पर काम कर रहे थे उन्होंने भी मंत्री महोदय के साथ ही पीठ फेरी और वहां से चले गये। और अब ८. १० महीनों से इस सड़क का काम बंद है। सड़क बनाने का कुछ सामान वहां पर पड़ा है लेकिन रोलर नहीं होने से वहां काम बन्द है। पूछने से मालूम हुआ, कि बड़ी भारी जरूरत थी भरतपुर में इसलिये रोलर वहां चले गये हैं क्यों कि ३१ मार्च नजदीक आनेवाला है इसलिये वहां अगर सड़क नहीं बनी तो रुपये लेप्स हो जायेंगे और वहां सड़क अधूरी रह जायगी। यहां लेप्स हो जायेंगे उसका क्या होगा कोई फिक्र नहीं मत्स्य न्याय धौलपुर के साथ लग रहा है, बडी मछली छोटी मछली को खा रही है। भरतपुर से रुपये लेप्स न हो जायं इसलिये सडक बना करी पूरी की जा रही है और यहां लेप्स हो जायेंगे उसकी परवाह नहीं है। मैं समझता हूं इस प्रकार का व्यवहार अच्छा नहीं है। जल्दी से जल्दी उस सडक को पूरा करना चाहिये। कई एक सड़कें हैं जिनका प्रस्ताव रखा गया था और जो स्वीकार भी कर लिया गया था पहली पंच वर्षीय योजना में और जो ड्राफट बना था उसमें छप गया था। उनके साथ ४. ५ छोटी २ सडकों का भी हवाला था। लेकिन बजट बना उसमें वह सडकें और ४. ५ वे छोटे २ टूकडे भी चले गये। पहली पंच वर्षीय योजना में से भी यह चली गई और इस पंच वर्षीय रिपोर्ट को देखते हैं तो इसमें भी वह नहीं आती। इसका कारण क्या है? एक कारण तो यह मालूम होता है कि जब मंत्रीजी के सामने जाकर सड़क और मकानके लिये कहते हैं, हम लोग दौड़ेहुए जाते हैं, समझाते हैं, वे उसे महसूस भी करते हैं लेकिन जबतक वापिस जयपुर आते हैं तबतक गद्दी बदल जाती है और समझाना बुझाना बेकार हो जाता है। फिर दूसरों को शुरू से समझाने की जरूरत आती है। मैंने कहा था कि धौलपुर से सेपऊ सड़क द्वारा धौलपुर से भरतपुर तक कुल ४४ मील पड़ता है आज जिस सड़क से हम आते हैं उससे धौलपुर धौलपुर भरतपुर से ७२ मील दूर होता है। इतना कम होने पर भी इस सड़क की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता लेकिन उस सड़क की मरम्मत होती है और उसमें जो पैसा खर्चते हैं उस सड़क का दो तिहाई हिस्सा आगरे से होकर भरतपुर जाना पड़ता है, उस पर तो पैसा खर्च किया जाता है लेकिन जो सड़क इतना खर्च करके बनाई जा सकती है और जिससे केवल ४४मीलकी दूरी ही रह जाती है और वह भी अपने हद में उस सड़क की की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। एक सड़क बसेड़ी से बन्ध बरेठा तक केवल १० मील का टुकड़ा बनाने से भरतपुर से धौलपुर बगैर किसी दूसरे प्रदेश में गये हुए पहुँच सकते हैं लेकिन आपका बजट हर साल चला जाता है, समाप्त हो जाता है और काम पड़ा रह जाता है। सुना है इस वर्ष के बजट में प्रोविजन रखा है लेकिन पता नहीं पूरा काम होगा कि नहीं।

[डा० मंगलसिंह]

स्कूलों के बारे में भीलवाड़ा मल्टी परपज स्कूल बिल्डिंग के लिए रुपये रखे गये थे। कमरे बने, प्लास्टर हुआ और अधिकतर काम हो गया। अभी एक बड़े इंजिनियर आये थे लेकिन उन्होंने सब कुछ ना पास कर दिया। यह खराब है, यह काम का नहीं है; यह कहकर उसको बीच में ही रोक दिया। मैं समझता हूं बकन फबकन बनते समय, यदि बीच में ही इन इमारतों को देखा जाय और खराबों का पता लगाया जाय तो इससे न तो ठेकेदारों को नुकसान हो और न गवर्नमेंट को ही नुकसान हो। इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से सड़कों, इमारतों, स्कूलों आदि के लिए जो रुपया रखा जाता है उसका जो रिटर्न मिलता है, वह सभी सदस्यों को मालूम है। १०० रुपये खर्च होते हैं तब मुश्किल से ६०-६५ रु. का काम मिलता है और बाकी रुपया कहां जाता है इस बात का किसी को ख्याल नहीं है। यह सब लोग जानते हैं कि वह रुपया कहां जाता है। न ईंट में लगता है और न पत्थर में और न मजदूरों में लगता है। इस ओर भी, मैं समझता हूं, सरकार को ध्यान देना चाहिये।

मैं इस बात पर एक बार फिर जोर देना चाहता हूं कि जिलों में जो रुपये मंजूर होते हैं सड़कों और मकानों के लिए उन जिलों में ऐसे सब डिविजन हैं जो पहले छोटे छोटे राज्य थे, खर्चा न करना और जो स्टेट्स पहले थीं वहां पर खर्चा कर दिया जाता है और छोटों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, यह ठीक नहीं है। मैं आशा करता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसे हिस्सों में जो सड़कें मन्जूर हो गई हैं लेकिन सेन्टर से रुपये आने में कमी हो रही है इस कारण काट दें तो यह ठीक नहीं है, इसका ख्याल पहले ही रखना चाहिये।

मैं एक अर्ज और करूंगा कि बाड़ी से सेपहू की सड़क अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि सेपहू अब बाड़ी की सब तहसील बन गई है और वहां जंगल का रास्ता है। इस सड़क के लिये कई बार मंजूरी हुई फिर भी नजर अन्दाज हो रही है और अन्त में अब तक नहीं बनी। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार की सड़क बनने की बहुत जरूरत है। जहां ऐसी जरूरत की सड़कें हैं वे जरूर आवें। इसके साथ ही मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूँ।

श्री भैरवलाल [काला बादल]—माननीय अध्यक्ष, मेरा यह प्रस्ताव है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण कार्य अधूरे रह गये हैं और इसी कारण से मैंने यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस सिलसिले में मेरा यह निवेदन है कि सरकार सड़कों और कई दूसरे कामों में लाखों रुपया खर्च कर रही है, मगर इस पैसे का इतना दुरुपयोग होता है कि इसका चौथाई पैसा भी जो खर्च किया जाता है वह निर्माणके कामों में खर्च नहीं हो पाता। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूँ कि पहले जब सामन्तशाही का शासन था उस समय यह कहावत प्रचलित थी कि बड़े आदमियों के भूत कमाते हैं आदमी तो थे वे, जो गादी और तकिया लगा कर बैठे रहते और उनके लिए कमाने वाले भूत कहलाते थे; उनको यानी कमानेवालों को भूत

[श्री भैरवलाल कालाबादल]

कह कर कलंकित किया जाता था आज भी वह कहावत इस राज्य में प्रचलित है । मैं चाहता हूँ कि इस कहावत को जल्दी ही समाप्त करना चाहिए । आज के युग में आदमी वे हैं जो हाथ पर हाथ धर कर बैठे नहीं रहते हैं और गादी तकियों पर बैठे रहते हैं । वे भूत हो सकते हैं जो मेहनत करके कमाकर खाते हैं । वह उनको आज के लोक राज्य में आदमी कहलाने का हक है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता दूं कि इन लाखों रुपयों को कमा कर सरकार को देने वाले लोग हैं उनको आज भूत कहते है । मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भूतों का क्या काम है । भूत जब नाराज हो जाता है या किसी को लग जाता है उस समय वह भूत से बचने के लिये और उससे छुटकारा पाने के लिये किसी देवता के यहां जाते हैं और उनको मानते हैं इसलिए घी का हवन करते हैं और कभी कभी एक जीव का बलिदान भी करना पड़ता है जिसके बाद देवता डील में आते हैं ;कहते हैं कि चार रास्तों के नुक्कड़ पर यह ठीकरा रख दिया जावे जिसमें बर्की व पूरी रखी जावे और तब जाकर भूत छूटेगा और यही बात कमाने वालों के लिये है । इस कहावत को इस समय में बदल देना चाहिये । वर्ना एक दिन इन कमाने वाले लोगों को भी अपना हक मांगने के लिए तैयार होना पड़ेगा ।

दूसरी बात माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि विधान सभा के सदस्यों, जिनके द्वारा गवर्नमेन्ट चलाई जाती है उन सदस्यों के इलाकों में शायद जरूर कहीं न कहीं निर्माण का कार्य हुआ होगा । बाकी तो मैं दो-तीन रोज से इन कटौती के प्रस्तावों पर यही सुन रहा रहा हूँ कि कहीं पर कुछ नहीं हुआ । झालावाड़ जिले में झालावाड़ और बारां के बीच एक सड़क है लेकिन सड़क ऐसी है कि वहां पर बरसात में चला जावे तो कीचड़ में से निकलना मुश्किल हो जाता है । जब इन सड़कों पर सरकार लाखों रुपया खर्च करके बना रही है तो इस सड़क की तरफ भी भूतपूर्व निर्माण मंत्री श्री भोलानाथ जी का ध्यान दिलाया गया था । श्री भोलानाथ जी ने कोटा और झालावाड़ की पूरी सड़कों पर दौरा किया और विश्वास दिलाया था कि इन सड़कों को जल्दी प्रथम पंच वर्षीय योजना में ले लिया जायेगा और यह सड़क प्रथम पंच वर्षीय योजना में ले ली गई । रकम भी काफी खर्च की गई मगर अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि झालावाड़ तहसील में खानपुर ऐसी तहसील है जिसमें इतना अनाज पैदा होता है कि जो पूरे झालावाड़ को खाने को देता है । उसको झालावाड़ से मिलाने के लिये जो ६ मील ४फर्लांग का टुकड़ा था जो प्रथम पंच वर्षीय योजना में पूरा होना चाहिए था मगर अध्यक्ष महोदय, अभी तक सिर्फ डेढ़ मील सड़क बन पाई है । ठेकेदारों को टेण्डर दिये गये ।

(घंटी)

अभी तक डेढ़ मील की सड़क बनी है और इस सड़क पर भी जो धनी है पत्थर जिस तरह डाले जाने चाहिए थे नहीं डाले गये हैं और उन पर मिट्टी डाल दी गई है । आज इस सड़क

Page No 59

[श्री भैरवलाल कालाबादल]

की हालत ऐसी है कि अगर कोई भी इंजिनियर जा कर देखे तो कह सकता है कि यह सड़क अच्छी नहीं बनी है। अगर एक बैलगाड़ी इस पर चले तो यह सड़क कुछ ही दिनों में उखड़ जावेगी और इसी तरह की योजना में काम अगर होता रहेगा तो मैं यह कहूंगा कि पैसा खर्च करना बेकार होगा और वह पैसा बरबाद करना होगा।

दूसरी बात में आपको बताऊं कि झालावाड़ से मनोहर थाना उधर बारां झालावाड़ उधर बारां और अटरू को जाने वाली सड़कों की यही हालत चोमेहालाडग पिंडाग सड़कों की है। समझ में नहीं आया कि यह पैसा जहां पर खर्च होना चाहिए नहीं होता और वहां पर खर्च हो रहा है जहां के लोग सरकार को कुछ नहीं देते और जहां के लोग सरकार को आमदनी देते हैं वहां के लोगों के लिए पैसा खर्च नहीं किया जाता। बारां कोटा शहर के लोगों को बहुत सुविधा देती है। इन शब्दों के साथ में यह प्रस्ताव सदन के समक्ष पेश करता हूँ और निवेदन करता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो झालावाड़ जिले के निर्माण के कार्य पूरे नहीं हुए थे उनको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरे करा दिया जावे, इसकी मैं आशा करता हूँ।

दूसरी चीज मुझे कोटा डिवीजन के पटवार घरों के सम्बन्ध में कहनी है। यह पटवार घर गांवों में होते थे। पटवार घर सरकारी इमारत होती थी। वहां पर सामान रखा रहता था मगर आज मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह सब बरबाद हो रहे हैं और वहां पर सांप और बिच्छू पैदा हो रहे हैं। आशा है इन इमारतों की व्यवस्था की ओर सरकार अपना ध्यान देगी।

श्री अध्यक्ष—श्री सुगनचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री कस्तूरचन्द।

श्री कस्तूरचन्द—अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है कि मांग संख्या २३-विषय ५० नागरिक निर्माण कार्य में एक रुपये की कटौती कर दी जावे।

जैसा कि मैंने बताया है कि शाहपुरा से विजय नगर रोड़, अध्यक्ष महोदय, इसके बीच की रोड जब शाहपुरा स्टेट थी तब वहां के राजा साहब ने बनवाई थी, मगर राजस्थान बनने के बाद इस रोड पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह रोड एक बड़ी महत्वपूर्ण सड़क है और शाहपुरा और विजयनगर ऐसे शहर हैं जिसके बीच में ट्रैफिक बहुत चलता रहता है क्योंकि यहां पर व्यौपारी मण्डी होने से यह आवश्यक है कि इस सड़क को बनाया जावे। इसलिये मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है।

[श्री कस्तूरचन्द]

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैंने यह बतलाया कि कोटडी तहसील है और इसका सम्बन्ध जिला भीलवाड़ा से करने के लिए एक छोटा सा झालावाड़ तक सड़क का टुकड़ा है, अगर वह बन जाय तो बहुत लोगों को सुविधा हो जाय। इसके लिए मैंने पहले भी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की थी और फिर भी यही प्रार्थना करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जावे क्योंकि कोटडी तहसील की तरफ कोई भी मिनिस्टर का ध्यान अभी तक नहीं गया है। यह तहसील इतनी पिछड़ी हुई है कि यहां पर किसी प्रकार का पैसा नहीं लगाया गया है। इसलिए इसके बारे में यह कह दूं कि हमारी गवर्नमेंट ने इसके साथ सौतेली मां का सा व्यवहार किया है तो अनुचित नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने दोनों रोडों के लिए प्रार्थना की है जो बहुत आवश्यक है। इस पर मैं आशा करता हूँ कि सरकार शीघ्र ही ध्यान देने की कृपा करेगी।

इसके बाद मैं, जैसा कि कल झालावाड डिस्ट्रिक्ट के लिए कहा गया था कि ४० जगह काम हो रहा है, मैं सदन व आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भीलवाड़ा में जो काम हो रहा है उससे तो बीकानेर में ३३ लाख रुपया लगाया जा रहा है। वह कहीं अधिक है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि भीलवाडा के साथ उपेक्षा की गई है।

मैं बता देना चाहता हूं कि यहां न मालूम किस ढंग से यहां मेवाड की आलोचना की जाती है। भीलवाडा डिस्ट्रिक्ट मेवाड डिविजन का बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। क्योंकि हमारे मेवाड के बहादुर राणाओं और राजाओं ने लडाई के वक्त में लड़ाई लड़कर मेवाड का नाम उज्जवल किया। आज वहां पर कोई सडक बनती है तो यहां क्यों जलते हैं? जो लोग आलोचना कर रहे थे उन लोगों को कहने की जरुरत पड गई है।

इस तरह जैसा कि अभी डा० मंगलसिंह जी ने फरमाया इतना रुपया मन्जूर होता है आखिर चला कहां जाता है। मैं कहता हूं, यह डिपार्टमेंट चोट्टा डिपार्टमेंट है। अगर आप चाहें तो मैं सबूत दे सकता हूं कि भीलवाड़ा डिवीजन में लाखों रुपया इस डिपार्टमेंट के लोगों ने खाया है। हमारे माननीय मंत्री भोले हैं नये हैं, फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस चोट्टे डिपार्टमेंट की ओर ध्यान दें।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय अध्यक्ष, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिन सडकों को रखा था वे पूरी न हो पाईं, इसकी वजह से मैंने एक कटौती प्रस्ताव रखा है। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि सरकार द्वारा पिछली पंचवर्षीय योजना में कोटा, बूंदी, झालावाड तीनों जिलों के लिए सडकें निर्धारित की थीं। कोटा डिवीजन की सबसे प्रमुख सडक थी कोटा से इटावा ४८ मील। किन्तु अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसकी चार वर्ष में १०-१२ मील तक प्रगति हुई है, दस बारह मील तक अभी तक बन पाई है। इस बजट में इसके

[श्री कंवरलाल जेलिया]

लिए ८० हजार रुपया रखा गया है। इससे सहज ही में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन रुपयों में कितने मिल और बनेगी यह सडक। जो सडकें बनने की रफ्तार जिस तरह से यहां रही उससे न मालूम कितने वर्ष में यह सडक बन पायगी। इस और मैं खास तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमारा छबडा सब डिवीजन है। जब पहले टौंक रियासत थी उस समय इस सब डिवीजन को जिले से सम्बन्धित करने के लिए इस सडक की योजना थी। आज भी छबडा सब डिवीजन का हैड क्वार्टर है सब डिवीजन का हेड क्वार्टर है इस लिए जिले से इसका सम्बन्ध स्थापित करना बहुत आवश्यक है फिर भी इस सडक की और ध्यान नहीं दिया जाता, बड़े ताज्जुब की बात है। ८१ नागरिक निर्माण कार्य की सूची में जो नाम दिये गये हैं उनको देखने से ऐसा पता चलता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी इस सडक का काम नहीं लिया गया है। इसके लिए जो धन राशि रखी है वह धन राशि पर्याप्त नहीं है। इससे एक वर्ष मे काम होने वाला नहीं। अगर यही रफ्तार रही तो मैं मानता हूं कि चार वर्ष में भी यह काम पूरा नहीं होगा। मैं आपको आंकड़ों से बताऊंगा कि कोटा डिवीजन के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? उदयपुर और भीलवाडा और राष्ट्रीय मार्ग के आंकड़े बताउंगा। १० लाख ६५ हजार रुपया उदयपुर डिवीजन के लिए, भीलवाडा के लिए १७ लाख ११ हजार रुपये के करीब हैं, वहां कोटा बून्दी और झालावाड इन तीनों के लिए केवल १० लाख ६० हजार रुपया रखा गया है। आज हमें इस संबंध में यह देखना है कि राजस्थान में आमदनी कहां से अधिक आती है और सरकार यदि उसी हिसाब से तय करती है और ज्यादा से ज्यादा वहां के इलाके को सुविधा पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिये। जब हम इन आंकडों को देखते है तो हमें पता चलता हैं कि काश्तकारों को हम राहत कैसे पहुंचा सकते हैं? जिस सडक का मैं जिक्र कर रहा हूँ वहां अनाज की पैदावार बहुत होती है। इसके सम्बन्ध में बराबर आवाज उठाने पर भी कि यह काश्तकारों का इलाका है, उनको बहुत असुविधा होती है, सडक के अभाव में वे लोग अपना गल्ला नहीं ला सकते, शासकीय दृष्टि से भी आवश्यक है, आज जिस रफ्तार से उस सडक का निर्माण हो रहा है उसके लिये मैं क्या कहूँ यह तो माननीय मंत्रीजी ही बता सकते है।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मार्ग जयपुर कोटा झालावाड़ जहां रात दिन आवागमन रहता है उस सड़क का भी इन चार वर्ष के अन्दर, एक पुलिया है उस पर पुल नहीं बनाया गया। वहां सबसे बड़ी दिक्कत बरसात के दिनों में होती है, झालावाड़ से एक तरह से कनेक्शन टूट जाता है, आने जाने का रास्ता रुक जाता है, पानी उस पुलिये पर जाता है। इन पांच वर्षों में वहां कुछ भी कार्य नहीं हुआ जब कि सरकार द्वारा सर्वे की जा चुकी है। हम देखते हैं कि दूसरी जगह तो पुलिये बना दिये जाते हैं किन्तु यह राष्ट्रीय मार्ग होते हुये भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि वे इस ओर खास तौर से ध्यान दें और दूसरी पंच वर्षीय योजना में इसके लिये प्रोवीजन रखें।

श्री अध्यक्ष—आपका कट मोशन क्या है और आप बोल किस पर रहे हैं?

श्री कंवरलाल जेलिया—(जारी) राजमार्ग के लिये हो तो मैंने दिया था ।

इसके अलावा मैं मननीय अध्यक्ष,माननीय मंत्री का ध्यान उन सड़कों की ओर भी दिलाऊंगा जो श्रमदान द्वारा तैयार की गई हैं । जनता का उत्साह बढ़ाने के लिये सरकार से आग्रह करता हूं, उन सड़कों को अगले वर्ष पक्की बनाने की ओर भी ध्यान देवें । इसके लिये बजट में कुछ प्रोवीजन होना जरूरी है । चार कम्युनिटी प्रोजेक्ट अटरू तहसील में हैं जहां लोगों ने श्रमदान करके कई मील सड़क बनायी है । जनता का उत्साह बढ़ाने के लिये जो कुछ सडकें बनी हैं वे पक्की की जायं ताकि जनता का उत्साह बढ़ सके ।

श्री अध्यक्ष—आपका कट मोशन है प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत ली गई सड़कों का काम पूरा न होने पर विचार करने के लिये ।

(घंटी)

श्री लक्ष्मण हीरात—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव यह है कि उदयपुर जिले के जो कार्य इस विभाग द्वारा कराये गये हैं वे सम्पूर्ण नहीं हुए हैं, उस पर विचार करने के लिये ।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान उदयपुर जिले की ओर ले जाना चाहता हूं। उदयपुर भी किसी समय ११ स्टेटों की राजधानी रही है, उस समय भी इसका महत्व बहुत था, आज भी इसका महत्व किसी प्रकार कम नहीं है । यहां सब साधन बड़े महत्व के थे लेकिन आज इस महत्व को नहीं रखा जा रहा है वे वहां की सड़कें जो पहले से बनी हुई है पूरी नहीं कराई जा रही है । जो काम तीन चार साल पहले से बना था वह बहुत अच्छा था, वह छोटे राजस्थान के वक्त में बना था । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं । हमारा सारा जिला पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका होने की वजह से पहाडियों से आने के बहुत कम मार्ग हैं । वहां ऐसे मार्ग नहीं है जिससे जन साधारण आसानी से आ जा सकें । उदयपुर से डूंगरपुर जाने वाली जो सड़क है उसका ऐसा हाल है कि तीन चार साल से वह बन रही है लेकिन अभी तक वह पूरी नहीं हो पाई है । थोडा सा टुकडा बन जाता है दूसरे साल, फिर थोड़ा सा बन जाता है इस तरह से चार साल तो हो गये, वह पूरा नहीं हुआ हैं, रास्ता भी वैसे बहुत खतरनाक है । हर साल वहां एक न एक एक्सीडेन्ट हो ही जाता है । अभी गत साल एक एक्सीडेन्ट हुआ था जिसमें एक बस जल गई जिससे छः आदमी मारे गये । इस रोड की ओर ध्यान मैं माननीय मंत्री महोदय का दिलाना चाहता हूं । उदयपुर जिले के बारे में और ज्यादा न बोलकर एक उदाहरण पेश कर देना चाहता हूं । ऋषभदेव से बोलाबा वाया सराडा होकर जो सलूम्बर रोड जाती है वह अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना में ले ली जावे तो बहुत अच्छा होगा । इससे वहां के रहने वालों के लिये आसानी हो जावेगी ।

[श्री लक्ष्मण हीरात]

सराडा एक तहसील हैड क्वाटर है, पुलिस स्टेशन है और एक छोटी डिस्पेन्सरी भी है, वैसे काफी पिछड़ा इलाका है। ऐसे इलाके में सड़क बन जाती है, तो आने जाने की सहूलियत हो जाती है। इससे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और गांव वालों को बहुत ही आसानी रहती है।

इसी तरह कल्याणपुर से ऋषभदेव घोडासर और ईंटाडी खेडा होकर सलूम्बर रोड जाती है, इसकी भी यही हालत है। बनती है और बन्द हो जाती है, कुछ बनती है और फिर रोक दी जाती है। इस साल उस टुकड़े पर बजट में बताया गया है कि छत्तीस हजार रुपये रखागया है। पांच छः मील का टुकड़ा ही बना है। इसलिये इस टुकड़े को भी पूरा कर देना चाहिये।

इसके अलावा खेरवाडा से रोड जाती है। इसकी भी यही हालत है। उदयपुर से गोगुन्दा होकर फलासिया जाती है वह सड़क भी ऐसी ही है।

लोग कहते हैं कि उदयपुर में काफी काम होता है, पर जितनी तारीफ उदयपुर की की जा रही है उतना काम नहीं हो रहा है और अगर भरोसा नहीं हो तो वहां जकर देखा जा सकता है।

इस विभाग को जो रिश्वतखोरी का कलंक लगा है वह वास्तव में सही है।

(हंसी)

इसमें अधिकारियों के परसेन्टेज बन्धे हुए हैं। ऊपर से नीचे तक का परसेन्टेज बन्धा है और उनका परसेन्टेज का पैसा जब तक उनकी जेबों में नहीं जाता तब तक कोई ठेकेदार काम नहीं कर सकता।

(घंटी)

ठेका देते हैं तो उसका परसेन्टेज उनके पास जाता है। आज वक्त ऐसा होता है कि अगर ठेकेदार पैसा उनका परसेन्टेज का नहीं दे पाता तो बिल समय पर उसके पास नहीं होते जिससे मजदूरों को पैसा नहीं मिलता और इसकी वजह से बेकारी भी बढ़ती है। मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि उदयपुर जिले में कई साल सड़कें बने हो गये हैं, जो पुरानी हैं उनको ठीक करने की तरफ भी ध्यान मंत्री महोदय को देना चाहिये।

श्री चुन्नीलाल बिडला—माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २३, मेजर हैड ५० पर मेरा कटौती का प्रस्ताव है।

भीलवाड़े जिले में मांडल तहसील में पहली पंचवर्षीय योजना में मांडल से देवगढ़ सड़क रखी गई है। उसका सिर्फ पांच मील का टुकड़ा भी पूरा नहीं बना है। मांडल से आसीन्द जाने वाली

[श्री चुन्नीलाल बिड़ला]

सडक का पांच मील का टुकडा आया हुआ है । मांडल माइका का एरिया है और इरिगेशन की वजह से भी प्रगतिशील स्थान है । पर फिर भी पांच मील का यह टुकडा मन्जूर हुआ, पर वह भी अधूरा है तो क्या आशा करूं मैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस ओर जल्दी काम हो जावेगा ।

इसी प्रकार मांडल से वागोर राजपुर वाया पर भी सड़क बननी चाहिये । करेडा से भीम तक की सडक की हालत ठीक करादी जावे, तो अच्छा है । ३२ मील का इस सडक का घेरा है । सदर मुकाम से जोड़ दिया जावे तो यह पहाड़ी इलाका रहा है, यहां आये दिन डकैतियां होती रहती हैं, इससे जनता को राहत मिलेगी । इसलिये मांडल से करेड़ा और करेडा से रायपुर आसीन्द रोड होने पर भीलवाड़ा भी सदर से जुड़ जाता है । इसलिये मैं सोचता हूं कि आइन्दा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस पर ध्यान दिया जावेगा तो इससे बड़ी सहूलियत जनता को हो जावेगी । मैंने इतना ही ध्यान दिलाने के लिए यह कटौती का प्रस्ताव रक्खा है, आशा है इस पर ध्यान दिया जावेगा ।

श्री मोतीराम चौधरी—अध्यक्ष महोदय....,

श्री अध्यक्ष—बहुत संक्षेप में मतलब की बात कह दीजियेगा ।

श्री मोतीराम—मैं सडकों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । मेरा निवेदन यह है कि गंगानगर जिला यातायात के बारे में सबसे पीछे है जबकि वहां की १८ हजार की बस्ती है जहां कि यातायात की चलने वाली मशीनरी से हजारों रुपयों की सरकार को पक्की आमदनी है, आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना रुपया बनता है एक आदमी के पीछे । इस जिले के अन्दर जब इतना रुपया सरकार को मिलता है तो सरकार का फर्ज है कि इधर सडकों की तरफ भी उसी तरह से ध्यान दे । २३ मील की सडकें अबतक कुल बनी हैं, इसके अलावा कोई सडक नहीं बनी है ।

जिस जिले से लाखों की तादाद में यातायात से पैसा मिलता है वहां सड़कों की कोई योजना न हो यहजरूर आश्चर्य की बात है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गंगा नगर-करणपुर सड़क सरकार ने पास की है और वह सड़क पिछली पंचवर्षीय योजना काल में बन जानी चाहिये थी । अब मैं देखता हूं कि उसके बनने की आशा इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी नहीं है । जब कि दस मील का टुकड़ा उस सड़क का इस साल बनने वाला है । जिस सड़क के बनने की यह रफ्तार है क्या वह सड़क कभी पूरा बनने की उम्मीद की जा सकती है ।

गंगानगर जिले के लिये जो सड़कें बनने की बातें की जा रही हैं वे केवल कागजों में ही बनी है । बनाने के लिये कोई रकम नहीं रक्खी गई है । इसकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ और माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन सड़कों के बारे में भी वे कुछ गौर करें ।

[श्रीमोतीराम]

दूसरी मेरी अर्ज यह है कि गंगानगर मोहनपुर सडक का बनना ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एक पैसा भी नहीं रक्खा गया है वह रक्खा जावे। वह सड़क इस साल रक्खी भी नहीं गई है तो रक्खी जावे।

और कुछ सड़कें हैं जिनके बारे में मैंने सरकार का ध्यान कई बार खींचा है। वे सड़कें ४४ मील की हैं। पांच मील ही बनने की बात हो, यह आश्चर्य की बात है।

दूसरा और मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि गंगानर के पास (अअअ्य) गांव है उसके लिये पिछली पंचवर्षीय योजना में कुछ रकम रखी जानी चाहिये थी वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी नहीं रखी गई है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन सडकों के बारे में अवश्य ध्यान देने की कृपा करें और उन सडकों को अवश्य बनवाने की कोशिश करें।

(श्री मुक्तिलाल के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—श्री रामचन्द्र चौधरी।

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने ज्यादातर सडकों के बारे में बातें कही हैं। जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि अपने राजस्थान का क्षेत्रफल करीब करीब १,३०,००० वर्गमील हैं और इसमें रहने वाले डेढ़ करोड़ आदम हैं। हमारे पास बहुत सी रियासतें पहले थीं जिनके कारण सडकों की बहुत ज्यादा तरक्की न होने पाई, और इस वक्त मैं ऐसा मानता हूं कि हिन्दुस्तान में या संसार के किसी भाग से भी सड़कों में सबसे पीछे हैं। लेकिन लोगों का यह कहना कि इस पांच साल के पीरियड में कोई काम नहीं हुआ है, या नहीं के बराबर हुआ है, जैसा कि धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सब लोग कहते हैं कि काम हमारे यहां नहीं हुआ है, हमारे यहां नहीं हुआ है; तो शायद वह आकाश में हुआ है या और कहीं हुआ है। यह बात भी हो कि शायद जहां तक वे कहते हैं अपनी समझ में ठीक कहते हैं क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा है कि कहीं सडक बनेगी तो उसका पता भी नहीं चल सकता है। लेकिन तथ्य ऐसे नहीं हैं। अपने यहां शुरू में जब रोड्स के लिए मन्जूरी हुई तो अपने यहां से एस्टीमेट ७ करोड़ के बनकर गये थे कि कम से कम हमें इस काम के लिये ७ करोड़ रुपया दिया जाय जिससे कि हम अपने यहां के यातायात के साधन कुछ पैदा कर सकें। शुरू में हमको २॥ करोड़ रुपये की मन्जूरी हुई। उसके बाद सन् ५३-५४ में प्लानिंग कमीशन के जो रोड एडवाइजर हैं श्री थापर आइ. सी. एस., वह यहां पर आये और उन्होंने यहां पर ८, १० दिन रहकर सड़कों के या मकानों के काम को अच्छी तरह से देखा। वह उनसे बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने यहां से वापिस जाकर रिकमन्ड किया कि राजस्थान में सड़कों व दूसरे पी. डब्लू. डी के कार्यों में बहुत अच्छी प्रगति हुई है, और हमारा ऐसा ख्याल है कि हम उनको अगर ५ करोड़ रुपये और

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

दे दें तो हमको हैजीटेशन रुपये के खर्चे का नहीं होना चाहिए। लेकिन अव्वल तो राजस्थान में यातायात के साधनों की बहुत जरूरत है, दूसरे वहां पर काम बहुत एफिशियेन्सी से चल रहा है, उस पर फिर वहां के लिए ५ करोड़ की मन्जूरी हुई। उसके बाद फिर वहां से सन् ५५ में रोड एडवाइजर, प्लानिंग कमीशन, आये और उन्होंने उस काम को देखकर कहा कि हमने जैसी आशा की थी उससे अच्छा काम हुआ है और हमको ५० लाख रुपये की इस अरसे के लिए और मन्जूरी दे दी तो अच्छा होगा कि इस पर हमको ५॥ करोड़ रुपये फर्स्ट फाइवयिअर प्लान में रोड्स के लिए मिल गये। यह सारा रुपया करीब करीब इस फर्स्ट फाइव इयर प्लान में ही हमने खत्म कर दिया है। इसलिये आप लोगों का यह कहना कि कुछ काम नहीं किया गया, यह सही चीज नहीं है, और इसमें यह हो सकता है कि इनमें से बहुत से मुलाजिम अपनी ड्यूटी को ठीक तौर से अन्जाम नहीं देकर कुछ गड़बड़ करते हों, लेकिन इसके लिये सारे डिपार्टमेंट को, इसको पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट और कोई प्लन्डर विदाउट डेन्जर कहे। बदनाम करना ठीक नहीं है। मैं जो तथ्य आपके सामने रख रहा हूं उससे आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें बहुत से डिपार्टमेन्ट से अच्छा काम हुआ है, और जो काम दिन रात महनत करके अच्छी तरह से किया गया है उसका श्रेय हम लोगों क उनको देना चाहिए। यह दूसरा सवाल है कि किस कदर इस डिपार्टमेंट में भी दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरह करप्शन चलता है तो उसको रोकने की हमारे सामने तजवीज आनी चाहिए। हम सब लोगों को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। हम कन्सरटेड एक्शन लेगें तभी कामयाब हो सकेंगे। लेकिन हर आदमी को बुरा कह देना, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

तो मैं जिन साहेबान ने जो एतराज उठाये हैं उनका जवाब एक एक प्वाइन्ट पर दूंगा।

सबसे पहले जोधपुर से आने वाले माननीय मेम्बर ने रेल वैगन्स के लिए कहा कि फर्जी सर्टीफिकेट उसमें जारी हो गये हैं और यह डिपार्टमेंट अभी तक उसके लिए कुछ काम नह कर रहा है। पत्थर व बजरी लाने के लिये शुरू शुरू में जोधपुर में बहुत ज्यादा इसका काम था। रेलवे वैगन्स इसके मिलते नहीं थे। इसलिए एक कमेटी नदर्न रेलवे की कायम हुई और उसमें हमारे यहां के चीफ इन्जीनियर राजस्थान को रिप्रेज़ेन्ट करते थे तो उसमें अपनी जगह उन्होंने सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर, जोधपुर, को तजवीज किया, और वह उस कमेटी में काम करते थे, और वहां से जो सिफारिश होकर आती थी उसमें उनके दस्तखतों से रेलवे वेगन्स मिलते थे। उसमें जो गवर्नमेंट वर्क्स थे उसके लिए 'सी' क्लास था और जो म्युनिसिपेलिटीज़ और स्कूल जैसी संस्थाएं थीं उनके लिए डी. क्लास की प्रायोरिटी उनको मिलती थी। यह जो किस्सा उन्होंने बतलाया है वह बीकानेर के क्षत्रिय स्कूल के निस्बत होता है जिसके किसी शख्स ने ४ वैगन्स के परमिट हासिल किये और उसमें म्युनिसिपल बोर्ड, बीकानेर, ने यह सर्टीफाई किया था कि यह आदमी स्कूल के लिए समान ला रहा है। उस सूरत में सुप्रिन्टेन्डिंग इन्जीनियर ने जो सर्टीफिकेट दिया तो उसकी तरफ से कोई फर्जी कार्यवाही नहीं है। डिपार्टमेंट में कोई बात फर्जी हुई हो, ऐसी बात नहीं है।

[श्री रामचन्द्र चोधरी]

उन्होंने उसी वक्त उसकी कार्यवाही एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट को सौंप दी, और उसमें एन्टी करप्शन बोर्ड कार्यवाही कर रहा है। यह उनके जेर तजवीज है। यहां से बराबर रिमाइन्डर्स जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। हमारी तरफ से किसी बात को छिपाने की या दबाने की कोशिश नहीं की गई है।

दूसरा एतराज उनका यह था कि टेन्डर्स शेडूल रेट पर देने का प्रयत्न नहीं किया जाता है, जयपुर में खास करके और उन्होंने हाई कोर्ट के रिस्बत तवज्जह दिलाई थी। हाई कोर्ट के बारे में मैं आपसे अर्ज करूं, उन्होंने यह बतलाया कि ८ परसेन्ट टेन्डर्स एबाऊ दिये गये। यह एक बड़ा काम था। इसलिए ८ परसेन्ट एबाऊ नहीं, बल्कि ८ परसेन्ट बिलो शेडूल रेट के टेन्डर्स दिये गये हैं और उन्होंने यह बतलाया कि २४ से ३० परसेन्ट एबाऊ शेडूल रेट के टेन्डर्स दिये जाते हैं, तो शायद उनको या तो गलतफहमी है या जानबूझकर ऐसी बात उन्होंने कही है जो कि सही नहीं है, क्योंकि १४ परसेन्ट से एबाऊ कोई भी टेन्डर पी. डबलू. डी. की तरफ से किसी को दिया नहीं गया। वह १४ परसेन्ट के टेन्डर भी ऐसे थे जहां ५. या ७ हजार का काम था। शहर में भी पत्थरो की नाली बनाने के लिए जल्दी में काम दिया था और कोई दूसरा ठेकेदार उस वक्त तैयार नहीं था। एकाध ऐसा टेन्डर है जो कि ऊपर दिया गया है, बाकी कोई नहीं दिया गया है। इस समय ऐसे बहुत से काम जयपुर शहर में चल रहे हैं जो कि सिटी इम्प्रूवमेंट की तरफ से चल रहे हैं या सेन्ट्रल पी. डबलू. डी. की तरफ से चल रहे हैं, या युनिवर्सिटी की तरफ से चल रहे हैं, जिनका पी. डबलू. डी. से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके रेट्स शायद मुमकिन हो कि शेडूल रेट्स से ज्यादा ऊपर के हों। उनकी निस्बत मुगालता हो सकता है मेम्बर साहब को। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि कोई टेन्डर इस तरह से एबाउ रेट नहीं दिये गये हैं। जहां कि ज्यादा रेट आये हैं वहां के टेन्डर मन्जूर नहीं करके रिटेन्डर किया जाता है, और इस तरह से कोई गड़बड़ नहीं की जाती है।

तीसरा उज्र रोड रोलर्स के बाबत था। यह भी उनको जो इन्फोर्मेशन मिली है वह बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि ३०० रोड रोलर्स इस वक्त राजस्थान में चल रहे हैं उनमें से ज्यादातर किराये पर हैं। ऐसी बात नहीं है, क्यों कि राजस्थान में इस वक्त सिर्फ १२९ रोड रोलर्स चल रहे हैं।....

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) —(जारी) और उसमें भी ९९ रोड रोलर्स अपनी स्टेट के हैं और ३० रोड रोलर्स ऐसे हैं कि जो किराये पर है। कुछ पी. डबल्यू. डी की ओर से कुछ लोगों को दे रखे है किराये पर। गवर्नमेंन्ट ऑफ इंडिया के मिलिटरी विभाग ने भी लिखा था। तो ४०) ४०) रुपये रोजाना किराये पर रोड रोलर्स दिये हुये हैं, इसमें कोई बेजाब्तगी या बेईमानी हो, ऐसा मुझे नहीं नजर आता।

चौथी बात एम्प्लॉइज़ के निस्बत कही गई। जितनी सहूलियत राजस्थान सरकार दे सक्ती थी उसने दी और आगे भी कोशिश करेगी। लीव रूल्स बना दिये हैं, वीकली पेड होलीडेज़ उनको

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

दी जाती हैं। बोनस, ग्रेचुइटी, साइकल अलाउन्स जैसा कल मैंने अर्ज किया था, वे उनके मंजूर कर लिये हैं। जितनी सहूलियत अपनी तरफ से दी जा सकती हैं दी जा रही हैं और उनके साथ कोई अन्याय नहीं बरता जाता है।

इसके बाद सरदार शहर से आने वाले व्यक्ति ने बीकानेर डिविजन में सड़कों की दुर्व्यवस्था का जिक्र किया। यह बात ठीक है कि बीकानेर डीविजन में सड़कें और जगहों के मुकाबले में बहुत कम हैं। इस के प्रधान कारण यह हैं कि पहले सड़कें बनी हुई नहीं थीं और सिवाय गंगानगर को छोड़ कर बहुतसा इलाका रेगिस्तान है जहां पर आसानी से सड़के बनाना भी संभव नहीं है। इसके लिए कोशिश की जा रही है और प्रथम फाइव इयर प्लान में कुछ सड़कें दुरुस्त की गई, कुछ बनायी गई। चुरू में अभी भी १५ सड़कें बन रही हैं, कुछ बन चुकी हैं और कुछ बन रही हैं और जेर तजवीज हैं।

इसके बाद मेडता से आने वाले माननीय सदस्य ने बतलाया कि डेगाणा के बाजार में पानी भरता है, वहां सडक बनाने के लिए बात भी हुई थी और आश्वासन भी दिया गया था किंतु अब तक सडक नहीं बनाई गई है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी भी म्युनिसिपल बोर्ड के अन्तर्गत वह हो अथवा डेवलपमेन्ट के अन्तर्गत हो तो वहां पर म्युनिसिपल बोर्ड अथवा डेवलप्टमे डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत कार्य होता है और उसका पी.डबल्यू डी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप डेवलप्मेन्ट विभाग में कोशिश करते तो शायद यह काम आपका पूरा हो जाता।

परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बातें कहीं। एक तो उन्होंने यह बतलाया कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ उपेक्षा बरती गई जैसा कि जमुआ-रामगढ़ से आने वाले माननीय साथी ने कही। कम से कम जयपुर वालों को तो ऐसी शिकायत नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जयपुर में सड़कों के लिहाज से यहां पहले से ही काफी सड़कें मौजूद हैं और जो खर्चा जयपुर पर हुआ है वह करोड़ों का हुआ है। सड़कें तो पचास लाख से ज्यादा बन गई। बिल्डिंग्स के लिये पंचवर्षीय योजना में हिसाब करोड़ों पर जावेगा। उन्होंने किशनगढ़ सब डिवीजन की उपेक्षा करने का जिक्र किया। किशनगढ़ सब डिवीजन के लिए अर्ज यह है कि वह चाहे छोटा हो फिर भी फर्स्ट फाइव इयर प्लान में १५ लाख की सड़कें बनी हैं। छोटे डिवीजन के लिए १५ लाख की बन जावे जब कि नेशनल हाइवेज मौजूद हैं और फिर भी यह कहा जाय कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और उपेक्षा बरती गई है तो फिर दूसरे लोग क्या कहेंगे यह समझ में नहीं आता। आपने अर्ज किया कि एक पत्थरों तक पहुँचाने के लिए सड़क नहीं बन पाई है। दो जगह के लिए आपने बताया था खानों तक सड़क पहुंचने के लिए। आपका मतलब यह था कि सेकिंड फाइव इयर प्लान में ऐसी सड़क बने जो कि सडक और क्वेरीज को कनेक्ट करे। अगर आप कोशिश करें और वे Industry dept. सिफारिश करेंगे तो हम क्वेरीज तक सड़क बनाने की कोशिश करेंगे।

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

दूसरा आपने गैंग और रोड मोहरिर के मुताल्लिक जिक्र किया कि गैंग के ग्रेड्स फिक्स नहीं किये गये, तनख्वाहें मुकर्रर नहीं की गई, दूसरी सहूलियतें नहीं और उनको परमानेन्ट स्टाफ नहीं बनाया गया। मैं अर्ज करूं कि अब राजस्थान में सड़कों का काम चलना शुरू हुआ है और अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी से अन्दाज नहीं लगा सकते कि कितने गैंग चाहिए, कितने फिक्स करने पड़ेंगे, कितने स्थाई तौर पर और कितने वर्क चार्ज पर चाहिए। मैं यह भी अर्ज करूं कि सिवाय सेन्ट्रल पी. डब्ल्यू. डी. के गैंग के अब तक कहीं स्थाई गैंग नहीं हैं और न कहीं उनकी ग्रेड मुकर्रर है। अब तक ये अपने यहां स्थाई नहीं हैं और उनको स्थाई तब ही किया जा सकता है जब कि हमको यह पता चल जाय कि कितना गैंग चाहिए और कितने कितने रोड मोहरिर चाहिए और उसी पर गवर्नमेंट विचार करेगी कि स्थाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और उनकी क्या ग्रेड होनी चाहिए।

इसके बाद दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि इस डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा अव्यवस्था है और करप्शन है। जैसा मैंने बताया कि अव्यवस्था है इस बात से तो मैं सहमत नहीं। मैं अर्ज करूं कि पी. डब्ल्यू. डी. गवर्नमेंट का एक ओर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट है और जो काम चलता है यह सुचारु रूप से चलता है। दूसरी बात करप्शन की कही। करप्शन किस हद तक है यह मैं नहीं कह सकता हूं। करप्शन की जिम्मेदारी उन लोगों के साथ साथ हम लोगों की भी और जनता की भी है। मेरे सामने कई केसेज आये। मैंने लिस्ट देखी है। किसी ने एस. डी. ओ. और एक्सीयन के खिलाफ शिकायतें कर दी, जब कार्यवाही शुरू हुई तो या तो किसी अफसर ने शिकायत करने वाले की खुशामद कर ली या शिकायत करने वाले ने रुचि नहीं दिखाई, कोई कारण हो, उस ऑवरसीयर को या एस० डी० ओ० को सस्पेन्ड कर दिया और कार्यवाही शुरू होती है तो यह कहा जाय शिकायत करने वालों की ओर से कि ऐसा हो गया वैसा हो गया और आयन्दा नहीं करेगा, ट्रान्सफर कर दो, सस्पेन्ड कर दिया, साल भर तक कार्यवाही चलती रहती है, गवाहान पेश नहीं होते और इसका नतीजा यह होता है कि इससे गवर्नमेंट को डबल नुकसान होता है, एक तो काम बन्द हो गया और दूसरा जिसको सस्पेन्ड कर दिया उसको उस पीरियड की तनख्वाह देनी पड़ती है और बहाल करना पड़ता है। मैं यह नहीं मानता कि अफसर ही ज्यादा जिम्मेदार हैं। हम भी इसके लिये जिम्मेदार हैं। अगर हमें करप्शन को बन्द करना है तो आप लोगों को सख्त कदम उठाना चाहिए। गवर्नमेंट भी ऐसा सोच रही है कि ज्यादातर बेइमानियां होती हैं वे ठेकेदार और अफसरों के बीच में होती हैं और तीसरे आदमी को पता भी कम चलता है और शिकायतें भी कम करते हैं इसलिए आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज कायम करें जिनको ठेका दे सकें क्योंकि वे सोसाइटीज तो रिश्वत नहीं देगी और गवर्नमेंट का काम सुचारु रूप से चल सके। मिडिल मेन जो अभी बने हुए हैं और रुपया का दुरुपयोग कर रहे हैं इसलिए आप कोशिश करें और रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आगे लाने में मदद करें। लेबर यूनियन्स बनावें तो उन लोगों को भी छोटे छोटे काम बिना दिक्कत के देने को तैयार हो सकते हैं। लेकिन इन सब में आपके कोऑपरेशन की जरूरत है और मेरा ख्याल है कि करप्शन तभी

[श्री रामचन्द्र चौधरी]

बन्द हो सकता है जब कि इस तरफ आप लोग सक्रिय कदम उठावें और इमदाद करें। मैं यह नहीं कहता कि करप्शन बिल्कुल नहीं है लेकिन यह कहना कि इसमें तो करप्शन ही करप्शन है, ठीक नहीं है।

दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनका कोई काम इसलिये नहीं किया जाता है कि वह गवर्नमेंट के अपोजिशन में बैठे हैं और बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह बात नहीं है। कई टेन्डर मांगे गये हैं लेकिन कोई देता नहीं है और देता है तो बहुत ऊंचा देता है जिसे गवर्नमेंट मंजूर नहीं कर सकती। आपने जो सड़क बताई उस पर काम १ महीने से शुरू हो चुका है और सेकन्ड फाइव ईयर प्लान में जो प्रपोज्ड सड़कें हैं वे आपको हफ्ता दो हफ्ता में मालूम हो जायेंगी। आपकी सड़क को जानबूझ कर छोड़ते हैं और अन्याय करते हैं ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरूसिंह—धन्यवाद।

श्री रामचन्द्र चौधरी (जारी)—एक बात यह भी बताई गई कि नावां में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत के मकान की जरूरत थी। किसी कांग्रेसी का मकान जो ५,००० से अधिक का नहीं है वह २५,००० रुपयों में खरीदा जा रहा है। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेंट में कोई इस तरह की तजवीज नहीं है। हमारे डिपार्टमेन्ट में तो यह है कि नया मकान बनाया जायगा और उसकी कीमत का तखमीना भी किया गया है। यह खबर जो आपने सुनी है वह सही नहीं है।

श्री शंभूसिंहजी ने भीलवाड़ा से कांकरोली तक जो सड़क बनाई जा रही है उसमें ढील होने की बात कही। यह बात ठीक है और जितनी तेजी से काम होना चाहिए था उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। कभी कभी बदकिस्मती से ऐसे ठेकेदार मिल जाते हैं जो काम का ठेका तो ले लेते हैं लेकिन बाद में तखमीने तक पहुंचने में कामयाब नहीं होते, आपकी सड़क का काम चल रहा है। पूरा होने पर इन ठेकेदारों के साथ कानूनी सलूक किया जा सकता हैं वह किया जायगा और यदि वाकई बिना कारण के सड़क बनाने में देरी की गई तो उस पर पेनल्टी लगाई जायगी।

दूसरी बात फेअरवेदर रोड के बारे में आपने कही कि वह खराब है। फेअरवेदर रोड मामूली होती है। झाड़ी या रेत साफ करके बनाई जाती है। ऐसी सड़कों की खास मरम्मत की बात नहीं है। सड़कों की बनिस्पत फेअरवेदर रोड्स की हालत खराब ही हुआ करती है।

इसके बाद राजा साहब उणियारा ने अपने यहां के मंत्रीजी से मुखातिब होकर कुछ बातें कहीं हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि उणियारा को सड़क की तरफ से इगनोर किया गया।

श्री वेदपाल त्यागी—थोड़ी दूर से निकाली।

श्री रामचन्द्र चौधरी—(जारी) जो सड़कें अधूरी रह गई हैं उनको सेकन्ड फाइव ईयर प्लान में बनाया जायगा।

राव राजा श्री सरदारसिंह—Thank you.

श्री रामचन्द्र चौधरी—(जारी) चूरू से आने वाले मित्र प्रभूदयालजी ने तारा नगर' राजगढ़ में बहुत सी सड़कों का जिक्र किया है। वैसे तो आपको बताया गया कि सड़कों के मामले में हम जितना करना चाहते थे उतना नहीं कर पाये। उतनी नहीं बना पाये जितनी बनानी चाहिए और इस अरसे तक बना नहीं पायेंगे यहां के एरिया और सीमा को देखते हुए। लेकिन जैसा मैंने बताया चूरू में १५ सड़कें को चालू कर रखा है। सेकन्ड फाइव ईयर प्लान····

राव राजा श्री सरदारसिंह—इसका मतलब क्या यह है कि नहीं बनायेंगे ?

श्री वेदपाल त्यागी—हमेशा पीछे रहेंगे।

श्री रामचद्र चौधरी—(जारी) फिलहाल आप जितनी चाहते थे उतनी सड़कें नहीं बन पावेंगी। डेवलपमेंट कमेटी के सामने सुझाव ३५ करोड़ रुपयों की सड़कों के आये थे। अपनी सारी सुविधाओं को देखकर राजस्थान सरकार ने समझा कि यदि हम को १५ करोड़ रुपये मिल जांय तो हम इम्पोरटेन्ट सड़कें बना सकते हैं। इसमें से भी प्लानिंग कमीशन ने अपनी मजबूरियों के कारण हम को सिर्फ ८॥ साढे आठ करोड़ रुपयों की मंजूरी दी। आप देख सकते हैं कि हम किस हद तक जा सकते हैं क्यों कि आपकी मांग है उसका एक चौथाई पैसा हमारे पास है। उसमें से भी ३ करोड़ रुपये पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए लगेंगे और २॥ करोड़ रुपये या तीन करोड़ रुपये पहले की अधूरी पड़ी सड़कों पर टारकोल आदि पर लगेंगे और एक्च्युली नयी सड़कों के लिए हमारे पास केवल तीन या चार करोड़ रुपये रहेंगे। उनको ध्यान में रखकर हमें खर्च करना है।····

रावराजा श्री सरदारसिंह—मेरा कहने का मतलब है कि तहसील दूनी है उसको मेन सड़क तक बढ़ाना चाहिये।

श्री रामचंद्र चौधरी (जारी)—सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में बढ़ायेंगे।

लेकिन जो सड़कें सब ने तजवीज की उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि ३५ करोड़ रुपयों के बजाय उनके लिए केवल ४ करोड़ रुपये ही रह गये हैं तो जो आप समझ रहे थे उसका नवमां हिस्सा ही बन पायेगा। इसलिए जितनी मजबूरियां हैं वे तो रहेंगी ही। बाकी हमारी तरफ से जो होगा उसके लिए कोशिश करेंगे ही।········

श्री सोहनलाल भटनागर—रोडस के मुत्तलिक सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान कब फाइनेलाइज होगा ?

श्री सभापति—बीच में ऐसे सवालों में क्यों उलझते हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी—(जारी) धौलपुर के बाबत डाक्टर साहब ने कहा वह ठीक है। श्रमदान से जो सड़क बनी उस पर अभी ७ मील तक टार डाला हुआ है और बाकी तारकोल सेकन्ड फाइव ईयर प्लान में पूरा किया जायगा। आपने दूसरी सड़क जो धौलपुर से भरतपुर तक बताई उस पर करीब १। लाख रुपया अभी खर्च हुआ है और ५ वर्षों में करीब ५ लाख रुपये ५ वर्षों में खर्च हो चुके हैं और बाकी सड़क सेकन्ड फाइव ईयर में पूरी करदी जायगी।

श्री कालाबादल साहब ने झालावाड़ की सड़क की तरफ तवज्जह दिलाई और कहा कि वहां पर सिर्फ १।। मील का टुकड़ा बना है। लेकिन यह बात सही नहीं है, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में ७ लाख रुपये अब से पहले खर्च हो चुके हैं और २६ मील सड़क बन चुकी है।

दूसरे जेलिया साहब ने कोटा के निस्बत कहा कि कोटा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है कभी न्याय नहीं होता।

श्री वेदपाल त्यागी—यह बात सत्य ही कही है।

श्री रामचन्द्र चौधरी—(जारी) मैं अर्ज करूं कि कोटा में फर्स्टफाइव ईयर प्लान में २६ लाख रुपयों की सड़कें बनी हैं और १२५ मील बनी हैं फिर भी आप कहते हैं कि अन्याय हुआ।............

श्री सोहनलाल—इस वक्त भी ४ लाख रुपये रखे हैं ३ करोड़ में से।........

श्री चेयरमेन—Order please !

श्री रामचन्द्र चौधरी (जारी)—बूंदी में ४१ मील सड़क बनी और ७,७१,००० रुपया लगा। झालावाड़ में २६ मील सड़क बनी और ७ लाख रुपया खर्च हो चुका है। इस तरह से कोटा पर २४ लाख खर्च होगया और २० मील से उपर की सड़कें बनाई गई। इसलिए यह कहना है कि सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है यह तो वाजिब नहीं है।

श्री कंवरलाल जेलिया—आप कोटा इटावा रोड बता दीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई अन्याय नहीं हुआ है। आप सब लोगों को बुला कर पूछा जायेगा और आपकी राय के मुताबिक ही बनाई जावेगी मगर इस बात को ('हिअर हिअर' की आवाज) ध्यान में रखना होगा कि हमारे लिमिटेशन कितने हैं।

Page No 73

श्री कंवरलाल जेलिया—(बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—आप इनको बोलने दीजिए। समय खराब न करें

श्री रामचन्द्र चौधरी—श्री कुंभारामजी ने गंगानगर पर बहुत जोर दिया है। मैं इस बात को मानता हूँ कि वहां पर जितनी सड़कों का निर्माण होना चाहिए था उतना अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन वहां पर हमारे सामने बहुत दिक्कतें आई सामान नहीं मिलता और राजस्थान में दूसरी सड़कों के निर्माण में जो खर्च लगता है उससे दुगुना वहां पर लगता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह कोशिश की जा रही है कि भाकरा डेम्म रोड से कर्जा लेकर जितनी सड़कें बन सकेंगी बनाई जावेंगी और इससे बाद मेरे ख्याल से कोई शिकायत का मौका नहीं आवेगा।

श्री गुरूदयालसिंह—भाकरा के अलावा बनावें।

श्री रामचन्द्र चौधरी—पदमपुर में बनेगी।

श्री सभापति—Order please!

श्री रामचन्द्र चौधरी—गंगानगर जिले में जो पहले सड़क बनी हुई है उसके कन्टीन्युएशन में २५ मील हैं वह भी रोड बनेगी। इसलिये आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। इतना कह कर मैं सभी माननीय सदस्यों से अर्ज करता हूँ कि पी. डब्ल्यू. डी. ने अपने टारजट से ज्यादा काम किया है इसके लिये आपको उसे धन्यवाद देना चाहिये। अगर कोई करप्शन है तो उसको रूट आउट करने के लिये आप अपने सुझाव दें और उस पर कार्यवाही की जावेगी। चीफ इन्जिनीयर वगैरा ने काफी सहयोग दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने कटोती के प्रस्तावों को वापिस ले लेंगे।

श्री सभापति—माननीय मंत्री महोदय ने कट मोशनों का जवाब दे दिया है और मैं आशा करता हूँ कि अब माननीय सदस्यों को प्रत्युत्तर देने की इतनी आवश्यकता नहीं होगी और जो देना चाहते हैं वे अपना उत्तर संक्षेप में दे दें।

श्री चाँदमल मेहता—सभापति महोदय, मैंने यह निवेदन किया था कि जयपुर जिले कि इसमें उपेक्षा की गई है। इसका जवाब उन्होंने यह दिया कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में लाखों रुपया खर्च किया गया। प्रथम पंच वर्षीय योजना में जो खर्च किया गया उनके लिये मुझे कोई एतराज नहीं है और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में मुझे एतराज है और इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया।

यह कहा गया कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में करोडों रुपया खर्च किया गया। ऐसा कहते समय माननीय मंत्री महोदय ने यह नहीं सोचा कि वे जयपुर जिले की बात कह रहे हैं या

[श्री चांदमल मेहता]

जयपुर डिविजन की बात कह रहे हैं। पी. डब्ल्यू. डी. के जयपुर डिविजन और जयपुर जिले में बहुत फर्क है। जयपुर डिविजन में अलवर, भरतपुर को छोड़ कर सीकर, टोंक, झुंझुनु आदि सभी आ जाता है। लेकिन मैंने जयपुर जिले की बात कही वह इससे बिल्कुल भिन्न है। मैंने जयपुर जिले की बात कही उसकी जनसंख्या १५ लाख है और वह बीकानेर डिविजन के बराबर है और कोटा जितना जिसका एरिया है। अगर आप इसकी तरफ ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में उपेक्षा की गई है। लेकिन फिर भी मैं इस उम्मीद के साथ, जैसा कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि सदस्यों की राय ली जावेगी और फंड को देख कर प्रबन्ध किया जावेगा, मैं अपना कटौती के दोनों प्रस्ताव वापिस लेता हूँ और सडकों के बारे में व्यवस्था करेंगे।

जहां तक तीसरे कटौती के प्रस्ताव का संबन्ध है उसके लिये मैं बहुत बड़ी-बड़ी आशाएं लगा रहा था और वह इसलिये कि सरकार मजदूरों के वेतन के बारे में मामले को लंबा नहीं करेगी मगर जो उत्तर मिला उसमें मजदूरों के वेतन को लम्बा करने की बात कहते हैं तो इस पर सोचना पडता है। अभी हमारे यहां सडकों का काम जारी हैं। हम अभी यह तय नहीं कर पाये इस संबन्ध में कि क्या करना है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सडकें बननी चाहिये, तो बने। लेकिन मजदूरों को इतना मिलेगा यह तो तय हो जाना चाहिये। प्रथम पंच वर्षीय योजना में यह तय नहीं हुआ, दूसरी आयेगी फिर तीसरी आएगी और फिर चौथी बन जाएगी। माननीय मंत्री महोदय इस आधार पर मजदूरों के मामले को लम्बा करना चाहते हैं और मैं यह निवेदन करुंगा कि मजदूरों के मामले को किसी भी रुप में लम्बा करना सहन करने काबिल नहीं है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि नेश्नल हाईवेज पहले सेन्टर गवर्नमेंट के अन्डर में थी वहां पर मजदूरों की तनख्वाह मुकर्रर थी। अगर पी. डब्ल्यू. डी. की मर्जी पर छोड दिया जाता है तो यह बात ठीक नहीं है। आज नेश्नल हाई वेज राजस्थान के कब्जे में आता है। अगर तनख्वाह मुकर्रर नहीं करते और पी. डब्ल्यू. डी. पर ही छोडतें हैं तो मेरे खयाल से यह गल्ती होगी और मैं यह माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि वे इस मामले पर फिर से विचार करें। मैं यह मान कर चलता हूं कि माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया है लेकिन उनके दिमाग में मजदूरों के प्रति सद्‌भावना है ऐसा विचार करके वे इस मामले पर गंभीरता से सोचेंगे और इस संबन्ध में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे। बस इतना ही कह कर मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री सभापति—क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री चांदमल मेहता को चारों कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाएं।

(स्वीकृती)

इजाजत दी गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने चारों कटोती के प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री चन्दनमल वैद—माननीय चेयरमेन, मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को महसूस किया कि बीकानेर की सडकों की व्यवस्था खराब है और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आगे से वहां पर सड़कों की व्यवस्था की जावेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो काम प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूरा नहीं किया गया उसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जावेगा। अगर आप इस संबन्ध में गंगानगर और उदयपुर जिले की तुलना करेंगे तो आपको मालुम होगा कि उदयपुर में ज्यादा सडके बनी हैं। जहां उदयपुर में ३०० मी० से ज्यादा सड़के बनी है वहा गंगानगर में केवल १०० मी० से कुछ ही ज्यादा। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री इसके लिये ध्यान देंगे और द्वितीय पच वर्षीय योजना में इस प्रकार की भेदभाव की नीति नहीं बरतेंगे। इतना कह कर मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति ।

(स्वीकृत)

इजाजत दी गई।

श्री चन्दनमल—मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री मानसिंह महार—माननीय चेअरमेन, सदन के समक्ष मैंने तीन कट-मोशन रखे । मैं आशा करता था कि मेरी कोन्सटीटुएन्सी के बारे में जानकारी करके माननीय मंत्री जबाब देंगे । मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा शायद वे भूल गये। उन्होंने कहा कि जयपुर में सबसे ज्यादा खर्च होता है जयपुर सबसे बड़ा है। आप जयपुर के चक्कर में पड गये जहां अलवर, भरतपुर को छोड कर सभी आ जाता है। आप जयपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में फरमाते तो ज्यादा अच्छा था । आप उदयपुर डिविजन से भरतपुर को कम्पेअर कर लीजिये। आपको मालूम हो जाएगा। मगर फिर भी जो बातें माननीय मंत्री ने कही हैं उससे आशा करते हैं कि कुछ तो जरूर होगा ही क्यों कि नई रोशनी है। कुछ कर सकेंगे। ध्यान तो आया है। बस इतना कह कर मैं अपने तीनों कटोती के प्रस्तावों को वापीस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

इजाजत दी गई।

श्री मानसिंह महार—माननीय सभापति, मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को वापिस लेता हूं।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्माण मन्त्री जी ने जो यह निश्चित रूप से कहा कि जो कुछ ढिलाई बरती गई है उसमें वे किसी प्रकार की लीपापोती करने की कोशिश करने वाले नहीं हैं। भीलवाडा से कुंवारा जाने वाली जो सड़क है उसकी ओर मैंने माननीय मन्त्री महोदय की तवज्जह दिलाई थी, मुझे खुशी है कि इस परटीकुलर केस को स्टडी करके मुझे आश्वासन दिलाये कि आयन्दा इस प्रकार की ढिलाई बरती गई तो वह न होने दी जायगी। और ठेकेदारों के खिलाफ जिनकी गलती से यह हुआ है उनके खिलाफ एक्शन लिया जायगा। मुझे बड़ी खुशी होती जिस परटीकुलर केस की तरफ मैंने ध्यान आकर्षित किया उस ओर ध्यान देते तो मुझे इस प्रकार का मोशन रखने की कतई नौबत नहीं आती। इस फेअर वेदर रोड के बारे में फेरडा से नीम जाने वाली है। इसके मुतल्लिक माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया फेअर वेदर रोड की ज्यादा जरूरत नहीं रहती। खर्चा भी इतना हो जाता है कि इसलिए फेअर वेदर रोड की जरूरत नहीं रहती, मैं निवेदन करूंगा कम से कम मरम्मत करके इसको इस अवस्था लायक बना दिया होता ताकि आवागमन ठीक प्रकार से हो सके आशा है माननीय मंत्री महोदय इस कमी को पूरा कर देंगे इस आशा के साथ मैं सदन से अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है कि श्री शंभूसिंह को कटौती प्रस्ताव वापिस लेने दिये जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

रावत श्री शम्भूसिंह—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

डा० **श्री मंगलसिंह**—चैयरमेन महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर सुन कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने आधा दर्जन के करीब सडकों का जिक्र किया उसमें से एक का भी जबाब नहीं दिया गया, जो सड़के श्रमदान से बनाई गई थी उसके बारे में मैं फिर उनकी सूचना के लिए कहूं कि इस सारी सडक के लिए तारकोल आया पड़ा है चाहें तो इस साल पूरा कार्य हो सकता है। इसके लिए भी यह कह दिया गया कि अगली पंचवर्षीय योजना में वह पूरा हो जायगा। और बाकी की सड़कें गायब हैं! मुझे आप क्षमा करें आज से छ वर्ष पहले एक मुख्य मंत्री वहां गये और उन्होंने इन मांगों के बारे में उत्तर देते हुए कहा था कि धौलपुर तो यू. पी. में जाना चाहता है। जाना चाहे तो जासकता है इसके ऊपर रुपया क्यों खर्च करें? मैंने उनको कहा था हम हिन्दू हैं हिन्दू या कोई कोई भी हो लड़की सबके होती है और वह लडकी जरूर दूसरे घर में जाती है यदि यह मान कर कि लडकी तो दूसरे के घर जाने ही वाली है उसको खाने पीने या पहनने का इन्तजाम नहीं करते हैं तो न्यायोचित बात होगी अर्थात् जब तक लड़की अपने पिता के घर है तब तक उसका हर तरह पालन पोषण करना होगा उसी प्रकार जब धौलपुर राजस्थान में

[डा० श्री मंगलसिंह]

है तो उसके साथ सब समान व्यवहार करना होगा। आज भी वही नियम चल रहा है आज भी उस सड़क को पांच वर्ष हो गये तारकोल खरीदा पड़ा हुआ है लेकिन वह सडक पूरी नहीं होती ! इस के मायने यह है कि अब तक मन्त्री महोदय यह समझते हैं धौलपुर तो हमेशा यहीं रहे अगर नहीं रहता है तो उसको हम किसी प्रकार की सुविधा देने वाले नहीं।

श्री गोपीलाल यादव—धौलपुर तो कहीं जाने वाला नहीं है।

श्री मंगलसिंह—मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जमाना जितनी तेज रफ्तार से बदल रहा है उसको देखते हुए हेरफेर होने में किसी को शक नहीं होना चाहिए। आज जमाना कहां का कहां चला गया है ? न मालूम राजस्थान भी कहां चला जायगा, यह भी पता नहीं। आज राजस्थान को रखने की उतनी फिक्र नहीं जितनी कि अपने आपको रखने की फिक्र हो रही है।

श्री सभापति—आप अपने विषय पर ही कहिये।

डा० श्री मंगलसिंह—(जारी रखते हुए) सभापति महोदय, जो सड़क धौलपुर को राजस्थान से मिलाने वाली है उस सड़क के बारे में कतई जिक्र नहीं। धौलपुर से हमें राजस्थान को जाना है अपने जिले के हैडक्वार्टर को जाना है तो ७२ मील सफर करना पड़ता हैं २४ मील धौलपुर से भरतपुर तक और बाकी ४८मील आगरे जिले को क्रोस करना पड़ता है। राजस्थान में जाने के लिए हमारा सीधा रास्ता नहीं है, करौली से अगर आवें तो २४ मील सरमथुरा से पड़ता है अगर हम उस रास्ते से जाय या तो पूंछ वाले खा जाय वगैर पूंछ वाले लूटलें ऐसा भयानक रास्ता है वह। भरतपुर और करोली के सिवाय और राजस्थान से मिलाने वाला रास्ता दिखता नहीं। चैयरमैन महोदय, मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है कि ऐसी हालत में, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को कैसे वापिस लूं लेकिन स्थिति ऐसी है कि कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने के सिवाय कोई चारा ही नहीं। जिस तरह से लाचार गवर्नमेंट यह महसूस करती है कि वह इससे ज्यादा काम नहीं कर सकती वैसी स्थिति में मैं भी हूं।

श्री जसवन्तसिंह—लाचार क्यों हैं ? इधर आकर बैठिये।

डा०श्री मंगलसिंह—उधर भी आ सकता हूं, आप शायद बैठने को जगह भीं न देगें क्यों कि मुझे तो इन प्रेमीसेज से बाहर जाने की बात है; इससे सहमत हों तो मैं उधर आने के लिए तैयार हूं। मैं यह कह रहा था कि मैं इस आशा में माननीय मंत्री महोदय फिर अपनी बातों पर विचार करेंगे और धौलपुर के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके साथ न्याय करेंगे। इस आशा में मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है कि डा० मंगलसिंह को उनका कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

डा० श्री मंगलसिंह—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री भोपालसिंह—सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह फरमाया कि डेगाना का मैंने जो जिक्र किया वह तो म्युनिसिपल इलाका है अतः म्युनिसिपैलिटी को वह सड़क बनानी चाहिये। डेगाना में म्युनिसिपैलिटी है, लेकिन डेगाना रेलवे स्टेशन भी है वहां पर अब तहसील हैड क्वार्टर भी हो गया। जब बरसात के दिनों ज्यादा पानी भर जाता है तो वहां मलेरिया का ज्यादा प्रकोप रहता है। इसको रफा करने के लिये कलेक्टर और एस० डी० ओ० से मिलकर और हम सब जनता से करीब ढाई हजार रुपया खर्च करवा दिया है मगर सड़क के लिए डेवलपमेन्ट कमेटी की एक हजार रुपये की योजना थी वह नहीं बन पाई है। डेगाना से चाचू तक सड़क बन रही है उसका डेगाने से कोई ज्यादा फासला भी नहीं है, अगर आप वह बाजार से बना दें तो करीब ५०० गज का टुकड़ा पड़ता है अगर आप इस टुकड़े को मिलाने के लिए आश्वासन देते हैं तो मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने के लिये तैयार हूँ।

श्री सभापति—आप कोई शर्त वगैरह नहीं रख सकते। आपको कटौती प्रस्ताव वापिस लेना हो तो लीजिये नहीं तो मैं सदन की राय के लिए रखता हूं।

श्री भोपालसिंह—अगर माननीय मंत्री इस प्रकार का आश्वासन देने को तैयार नहीं हैं तो मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है कि श्री भोपालसिंह के कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कट मोशन गिर गया।

(विराम)

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा।

(विराम)

[श्री सभापति]

Did he move ? मूव ही नहीं हुआ यह तो ।

श्री भैंरूसिंह ।

श्री भैंरूसिंह (१६)—वापिस नहीं लूंगा ।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री भैंरूसिंह ने रक्खा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

श्री श्रीदास गोयल ।

श्री श्रीदास गोयल—मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव रक्खा ही नहीं था इसलिये वापिस लेने का सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री सभापति—रावराजा श्री सरदारसिंह ।

रावराजा श्री सरदारसिंह—माननीय सभापति महोदय, मुझे मंत्रीजी की घोषणा को सुनकर दुख तो बहुत ही हुआ कि उन्होंने पूर्ण रूप से यह नहीं कहा कि यह सड़क बनेगी या नहीं ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अपूर्ण रूप से तो कहा ?

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह—अपूर्ण रूप से भी नहीं कहा । जब चाहे मैं अपने इस कटौती के प्रस्ताव को वापिस लूं या न लूं लेकिन करूं क्या बहुमत तो आपका ही है । अब इससे मैं यह भावना लगाऊं कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन आ रहे हैं उसमें सरकार की पार्टी का सदस्य वहां से खड़ा होगा तब तो बनेगी ही । तो फिर यह कटौती का प्रस्ताव वापिस लेकर ही अहसान क्यों न करूं ? इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि बन जावे यह सड़क तो अच्छी है, पब्लिक का फायदा होगा, कोई रावराजा साहब का तो फायदा होगा नहीं और अगर मेरे कहने से बना दोगे तो सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा । इसलिए पब्लिक पर रहम करके मुख्य मुख्य महत्वपूर्ण जो सड़कें हैं उनको

[रावराजा श्री सरदारसिंह]

तो बना दो। इसलिए इस प्रस्ताव के जरिये सभापति महोदय आपके द्वारा मैं सरकार से यही प्रार्थना करता हूं और यही प्रार्थना करने के बाद मैं अपने इस कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति—क्या यह सदन की अनुमति है कि श्री सरदारसिंहजी को अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

इजाजत दी गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह—मैं अपने कटौती के तीनों प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति—श्री प्रभुदयाल।

श्री प्रभुदयाल—चैयरमेन महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव थे। एक सड़कों की उपेक्षा के बारे में और दूसरा बिल्डिंगों के बारे में।

उपेक्षा के बारे में मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सड़कों के बनाने का जो प्रोग्राम बनाया जावेगा उसमें हमारी भी राय ले ली जायगी और इसमें हमें भी हमारे विचार प्रगट करने का मौका दिया जावेगा। इस आश्वासन के बाद में अपना यह कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

अब बिल्डिगों के बारे में बताऊं। पिछली साल २१ करोड़ रुपया सेन्टर से बिल्डिंगों के लिए मन्जूर हुआ था लेकिन मैं चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि २१ रुपया भी चूरू हेडक्वाटर के लिए खर्च नहीं किया गया। सरकारी बिल्डिंगों के अभाव में जिला हैडक्वाटर आज इस प्राइवेट सेठ की बिल्डिंग में है, तो कल उसकी बिल्डिंग में है बड़ी तंगी की स्थिति में काम चलाया जा रहा है और इससे जनता को बड़ी हैरानी होती है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि जो उपेक्षा हमारे जिले के साथ की गई है, और खास तौर से हैड क्वाटर भी नहीं है, तो उससे ज्यादा खेद की बात और क्या हो सकती है ? पर मंत्री महोदय ने विश्वास दिलाया है तो इस आशा के साथ कि अब ऐसी स्थिति को सुधारा जावेगा में अपने इस कटौती के प्रस्ताव को भी वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति—क्या सदन की यह अनुमति है कि इन्हें अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की जाती है।

श्री प्रभुदयाल—मैं अपने दोनों कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति—श्री कुम्भाराम आर्य।

श्री कुम्भाराम आर्य—सभापति महोदय, मैं अपने कटौती का प्रस्ताव तो वापिस लूंगा ही लेकिन इसके साथ दो शब्द कह देना चाहता हूं कि हमारी हालत भी ऐसी अजीब हो गई है कि मौन रहें गूंगे कहलावें और जीभ हिलावें तो गुस्ताख बताए। अब कह दूं या चुप होकर बैठ जावें, यह हमारे सामने समस्या है। मैं इसलिये कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहा था कि इस साल के बजट पर ही विचार किया जावे। जो जो सड़के रक्खी हैं, दस या पन्द्रह, उनका हिसाब बतलाता हूँ।

देपालसर की तीन मील की एक सड़क रक्खी है। इसका खर्चा जो है वह ६ लाख रुपया रक्खा है और पचास हजार साल के हिसाब से इसका खर्चा तै किया गया। इस तरह से ६ बाई २ बराबर अठारह साल का यह बजट हो गया है, न कि एक साल का, इन अठारह सालों में पहला फाइव ईयर प्लान चला जावेगा, दूसरा भी चला जावेगा तब मिनिस्टर साहब जाकर हमको एक तीन मील का टुकड़ा पकड़ावेंगे। इस तरह से इन अठारह सालों में तीन फाइव ईयर प्लान निकल जावेंगे और चौथे के वक्त वह सड़क पूरी बनाकर हमें दी जावेगी। तो उस सड़क के पूरा बनने के लिए हमें अठारह साल तक इन्तजार करना होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मिनिस्टर आपके ही हैं वे।

श्री कुम्भाराम आर्य—कुल सत्रह सड़कें रक्खी गई हैं। उन सत्रह का ही यही हाल है। पिलानी राजगढ़ से तीन मील है। सात लाख रुपया खर्च होगा इस पर पचास हजार रुपया साल के हिसाब से तो इस हिसाब से १४ सालों में राजगढ़ से पिलानी पहुँचा जावेगा।

इसी तरह से लालगढ़ का तेरह मील का टुकड़ा है जिस पर ६ वर्ष लगेंगे। देपालसर पर ६ साल लगेंगे, देखिए हमारी कैसी दशा है।

आज हमारे बजट की हालत है उस सेठ जैसी थी कि जो सो रहा था और उस पर से सांप निकल गया। यह देख कर सेठ बड़े जोर से रोने लगा। लोगों ने पूछा तो सेठ ने जवाब दिया कि इस बात के लिये नहीं रोता हूँ कि सांप क्यों निकल गया। पर इस बात के लिये रोता हूं कि यह रास्ता

[श्री कुम्भाराम आर्य]

न पड़ जाय । हमारे तीन फाइव ईयर प्लान खत्म हो जावेंगे अगर इसी रफ्तार से हम चले तो ऐसी स्थिति में मैं तो माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन की आशा में जो सड़कें दो-दो तीन-तीन मील की ले रखी हैं इसी साल पूरी करा दें नहीं तो हमारे लिये बड़ी समस्या हो जावेगी ।

एक सड़क रक्खी है बीकानेर से फलोद । कहा जाता है यह सौ मील का टुकड़ा है । पर खर्च नहीं होगा एक पैसा भी । यह इस बजट की रूपरेखा है । इसी तरह से सारी सड़कें हो जातीं तो यह भार लेने की जरूरत नहीं होती । यह हमारे फाइव ईयर प्लान का नमूना है । खर्चा देखते हैं तो जीरो जीरो जीरो जीरो । सब खाने जीरो से भरे पड़े हैं । तो मैं सोचता हूं कि किस तरह से यह सारा काम पूरा हो जावेगा ? मंत्री महोदय के पास क्या कोई जादू है जिससे यह सौ मील की सड़क बन जावेगी ? हमारी स्थिति यह है कि हमको सड़कों के मामले में नौ साल तक इन्तजार करना पड़ेगा । पहली, दूसरी और तीसरी फाइव ईयर प्लान के समाप्त होने पर हमें तीन मील का यह टुकड़ा मिलेगा । हम तो पन्द्रह सालों में तीन मील आगे बढ़ेंगे । यह हमारी अजीब सी स्थिति है । हम इसमें सुधार चाहते हैं, इसका आश्वासन मिलना चाहिए ।

श्री रामचन्द्र चौधरी—मैंने पहले अर्ज किया कि सेकिंड फाइव ईयर प्लान में तीन करोड़, ढ़ाई करोड़ और साढ़े पांच करोड़ रुपया हमने रक्खा है उसे पूरा खर्च किया जायेगा यह सारा सेकिंड फाइव ईयर प्लान में खत्म हो जावेगा ।

श्री सभापति—(श्री कुम्भाराम आर्य से) आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेंगे ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव लेना चाहता हूँ ।

श्री सभापति—क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री कुम्भाराम आर्य को अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

इजाजत दी जाती है ।

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति—श्री भैरवलाल कालाबादल ।

श्री भैरवलाल कालाबादल—माननीय चेयरमेन, माननीय मंत्रीजी ने २६ मील की सड़क झालावाड़ के लिये तैयार होना बताया है तो २६ मील से मैं यह नहीं समझा कि यह एक

Page No 83

[श्री भैरवलाल कालाबादल]

सड़क २६ मील बनाई गई हो किसी सड़क पर १० फर्लांग या किसी पर १॥ मील काम हो गया है। वहां काम ऐसा हुआ है कि पत्थर जो ठेकेदारों ने डाले हैं वह चपटे डाले हैं. जैसे फर्शी डाली जाती है और उन पर थोडी सी मिट्टी डाल दी जाती है। उस मिट्टी से यह होता है कि इंजीनियर साहब देखने आते हैं तो वह मिट्टी देखकर चले जाते हैं कि हां मिट्टी डाल दी गई। इस तरह से वहां चीज चल रही है। झालावाड़ में ७ लाख का खर्चा हो गया २६ मील पर जब कि बूंदी में ४० मील पर ७ लाख का खर्चा हुआ है। तो जो झालावाड़ में २६ मील पर ७ लाख का खर्चा हुआ है और बूंदी में ४० मील पर ७ लाख का खर्चा हुआ है तो क्या वहां (झालावाड़ में) सड़कें सीमेन्ट की या डामर की बनाई गई हैं ? मंत्री महोदय ने यह कहा कि इन सड़कों के बारे में अब व्यवस्था ठीक होगी और जल्दी से जल्दी दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह काम पूरा होगा यह आश्वासन दिया है इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की मांग रखता हूं।

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है कि श्री कालाबादल को अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

इजाजत दी गई।

श्री भैरवलाल कालाबादल—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति—श्री कस्तूरचन्द।

श्री कस्तूरचन्द—माननीय चेयरमेन महोदय, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया था उसका कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए मेरे कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने का कोई सवाल नहीं उठता है।

(विरोधी पक्ष की ओर से 'हियर, हियर')

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि श्री कस्तूरचन्द ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है वह पास किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

(सरकारी पक्ष की ओर से 'ना' की आवाजें)

श्री जसवन्तसिंह्—Ayes have it, Sir.

श्री कस्तूरचन्द—मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को····

(सदन में चारों ओर से विभाजन की मांग एवं विभाजन घंटी)

श्री कस्तूरचन्द—माननीय चेयरमैन महोदय....

श्री जसवन्तसिंह्—Mr. Chairman, Sir, there should be no pressure tactics in the House. The Whip is broken.

(हंसी)

श्री सभापति—Order please ! प्रश्न यह है कि कटौती का प्रस्ताव जो श्रीकस्तूरचन्द ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

श्री कस्तूरचन्द—I withdraw.....

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Chairman, Sir, he can withdraw at any stage.

श्री जसवन्तसिंह्—Not after pressure tactics.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It cannot be withdrawn after the question has been put.

श्री मथुरादास माथुर—The question has nct been put.

श्री गोपीलाल यादव—वह मांगते हैं तो इजाजत देनी चाहिए ।

श्री श्रीदास गोयल—He can wiihdraw at any stage.

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है । The question has beeu put once. अब तो केवल डिवीजन की मांग की जा रही है । The question is being put...

श्री मथुरादास माथुर—At any stage he can withdraw.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am in the possession of the House, Sir, and I do not want any interruption, Sir. अब इस स्टेज पर जब कि यह प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है प्रस्ताव के वापिस लेने की अनुमति का प्रश्न ही नहीं उठता है। डिवीजन मांग रहे हैं और डिवीजन के निर्णय के रूप में निर्णय सदन का हो जायगा, वापिस लेने के प्रस्ताव को उठाकर रूल्स को नहीं तोडा जाय। मेरी यह दरखास्त है कि डिवीजन की आज्ञा दी जाय।

श्री जसवन्तसिंह—अब वह स्टेज पहुंच चुकी है और डिवीजन कॉल कर ली गई है और सिवाय इसके कि डिवीजन हो और वोट लिये जायें, कोई चारा नहीं है। विद्ड्रोअल की स्टेज निकल चुकी है। अब तो डिवीजन होना चाहिए।

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरे खयाल से विद्ड्रा करने के लिये मूवर को राइट है कि किसी भी स्टेज को विधड्रा करें। हाउस उसकी पर्मिशन दे या न दे, वह देखा जायगा, लेकिन विद्ड्रा करने का उसको राइट है।

श्री जसवन्तसिंह—मेरा यह निवेदन है कि हाउस से पर्मिशन मांगी गई थी विधड्रा करने के लिए और हाउस ने इन्कार कर दिया कि पर्मिशन नहीं दी जा सकती है। इस पर डिवीजन बैल कॉल कर ली गई। डिवीजन कॉल के बीच में प्रेशर केक्टिक्स लगाये जायं और जोर से कहा जाय कि तुम विद्ड्रॉ करो, यह बिल्कुल पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस के खिलाफ हो रहा है। और इस कन्डीशन में यह पोसीबल नहीं है कि एक सदस्य को दबाकर विद्ड्रॉ कराया जाय। इसका निर्णय यह सदन करेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—चेयरमेन महोदय, मैं समझता हूँ कि दबाने का प्रश्न ही नहीं आता। कोई गलतफहमी का प्रश्न हो गया है।

(हंसी)

और इस वजह से प्रेस किया गया था। अब रूल्स इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट हैं कि जब तक वोट क्लेक्टेड नहीं हों इसके पहले कोई भी व्यक्ति अपने मोशन कोई विद्ड्रॉ कर सकते हैं।

श्री सभापति—रूल ६१ ऑफ रूल्स दी प्रोसीजर में इसके बाबत साफ है—

"At any time after a question on a motion has been proposed from the Chair and before the voices both of ayes and noes have been collected, the motion may, with the leave of the Assembly and not otherwise, be withdrawn by the member who moved it."

श्री गोपीलाल यादव—यह तो विद्ड्रॉ हो सकता है। वोइस कलेक्टेड (Voice collected) नहीं हुई हैं।

श्री जसवन्तसिंह—वोइस कलेक्टेड (Voice collecected) हो गई हैं ।

श्री गोपीलाल यादव—The voices are now to be collected.

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमेन, वोइसेज का केल्कुलशन होने का वर्ड सेक्शन ६१ में बड़ा इम्पॉर्टेन्ट है और जैसा कि कुछ माननीय मित्रों ने कहा कि नोज और ऐज का केल्कुलेशन नहीं था किन्तु एक एस्टीमेट करना था । माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जिस रूप में इसको लिया है कि माननीय चेयरमेन महोदय ने निर्णय दिया है कि "नोज हेव इट" तो वह केल्कुलेशन एक्चुअली नहीं हुआ था । अब केल्कुलेशन होने वाला है और उससे पहले विद्ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं ।

कई माननीय सदस्य—विद्ड्रॉ करने का सवाल पैदा नहीं होता है ।

श्री सभापति—ज्यादा झंझट में पड़ने का सवाल नहीं है । I think he can withdrawit

(राज्य पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

श्री कस्तूरचंद—माननीय चेयरमेन, यह इसलिए हुआ कि मेरे कट मोशन का कोई जवाब नहीं दिया ।

(हंसी)

मैं सदन की अनुमति चाहता हूँ कि मैं इसको विद्ड्रा करलूं ।

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है ।

(बाधा)

मुझे पहले सवाल कर लेने दीजिये ।

(विराम)

क्या सदन की अनुमति है कि श्री कस्तूरचंद को उनका कट मोशन वापिस लेने को इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

इजाजत दी जाती है ।

श्री कस्तूरचंद—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति—श्री कंवरलाल जेलिया।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय चेयरमेन, मेरे कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी मैंने जो आश्वासन दिया और आपने यह आश्वासन दिया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में माननीय सदस्यों से आवश्यक जानकारी ली जायगी इसलिए मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ ?

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है कि श्री कंवरलाल जेलिया को उनके कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

इजाजत दी जाती है।

श्री कंवरलाल जेलिया—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति—श्री लक्ष्मण हीरात।

श्री लक्ष्मण हीरात—माननीय चेयरमेन, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा था उस सम्बन्ध में माननीये मंत्रीजी ने विशेष ध्यान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने जो बातें कहीं कि सदस्यों की सलाह लेकर कार्य करावेंगे इस आश्वासन पर मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है कि श्री लक्ष्मण हीरात को उनका कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

इजाजत दी जाती है।

श्री लक्ष्मण हीरात—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति—श्री चुन्नीलाल।

श्री चुन्नीलाल—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है कि श्री चुन्नीलाल को उनका कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इजाज़त दी जाय ?

(स्वीकृत)

इजाजत दी जाती है।

श्री चुन्नीलाल—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति—श्री एच. के व्यास, पांच प्रस्ताव हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किये जांय। विद्ड्रा करने का सवाल नहीं उठता है।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि श्री एच. के व्यास ने जो पांच कटौती के प्रस्ताव रखे हैं वे स्वीकर किये जांय ?

(अस्वीकृत)

पांचों कटौती के प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

श्री घासीराम।

श्री घासीराम—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से इजाज़त चाहता हूं।

श्री सभापति—क्या सदन की अनुमति है कि श्री घासीराम को उनका कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाज़त दी जाय ?

(स्वीकृत)

इजाज़त दी गई।

श्री घासीराम—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण

[श्री सभापति]

कार्यों के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्री मान् राजकुमार को ३,१२,२४,००० रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री बृजसुन्दर।

मांग संख्या ३०—विविध

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ३०, मुख्य शीर्षक ५७ विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्री मान् राजप्रमुख को ७७,२५,००० रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(विराम)

श्री सभापति—मांग प्रस्तुत हुई। कटौती के प्रस्ताव, श्री एच. के व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन महोदय; जो मांग प्रस्तुत हुई है उस पर मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। दो का सम्बन्ध एक विभाग से है और एक का सम्बन्ध एक दूसरे विभाग से है। इस मांग में कई विभागों का ताल्लुक आ जाता है और इस नाते में समझता हूँ कि इन विभागों के बारे में कटौती प्रस्ताव अलग अलग लिये जांय तो ज्यादा सहूलियत होगी, मसलन पब्लिसिटी और पंचायत बोर्ड इसमें है और एक दूसरे से जुडे हुए प्रश्न जहां हों उनको एक साथ लिया जा सके और इस लिये आज्ञा दें तो में दो प्रस्ताव एक साथ मूव कर दूं और पब्लिसिटी का काम काम पूरा हो जाने के बाद दूसरा प्रस्ताव मूव करूं।

श्री सभापति (राज श्री हिम्मतसिंह)—ठीक है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman, Sir, my suggestion was first to dispose of the inter connected departments; for instance publicity and punchayat Board and then the other on the separate cut motions.

कुं श्री जसवन्तसिंह—We push it department wise.

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो माननीय चेयरमेन महोदय, मैं अपने पहले दो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री सभापति— क्रम संख्या ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—नम्बर २६ एण्ड २७ ये दो ही पहले मूव करता हूं।

श्री सभापति—yes, 26 and 27.

श्री हरिकृष्ण व्यास—विविध मांग में जिन महकमों का सम्बन्ध आता है उनमें पहला नम्बर में पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट है। और मैंने जो दो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं वे इस आशय के हैं चेयरमेन महोदय, कि एक तो इस विभाग द्वारा अपनी खुद की जो छपाई कराई जाती है या प्रिन्टिंग का काम कराया जाता है उसमें अनियमिततायें बढ़ती जा रही है और दूसरा सरकार के विज्ञापन देने का काम जो इस विभाग को सौंपा गया है उस विज्ञापन देने के काम का भी बहुतसी गलत नीतियों के बुनियाद पर और गलत नीति के साथ आज काम चलाया जा रहा है। सरकारी विज्ञापनों के सिलसिले में, सरकारी विज्ञापनों का प्रश्न कुछ दिनों पूर्व प्रश्नोत्तर काल में भी और श्रीमान् राजप्रमुख के अभिभाषण में भी चर्चायें हुई हैं और मुझे अच्छी तरह से याद है कि गृह मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है। उन्होंने उसमें कुछ आंकडे भी प्रस्तुत किये। मेरी यह मान्यता है चेयरमेन महोदय, कि राजस्थान में राजस्थान सरकार की ओर से विज्ञापन देने और न देने के बारे जो नीति बरती जा रही है उसको केवल पक्षपातपूर्ण नीति कहा जाय तो मैं समझता हूँ कि अन्याय होगा और अनियमित नीति कहा जाय तो हल्के दर्जे का होगा, सही माने में अगर उस नीति की आलोचना करता है तो मैं कहुंगा कि कुछ विशेष व्यक्तियों को पारवरिश देने की वह नीति है और यही मेरा उस सिलसिले में कहना है।

सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो अलग अलग समाचार पत्र हैं उनके लिये अलग अलग विज्ञापन की दरें कैसे हुई और किस प्रकार मौजूद हैं। कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी कह रहे थे कि जितने दैनिक पत्र हैं उन सब को ७ रुपया कोलम के हिसाब से दिया जाता है इससे एक दूसरे से कम ज्यादा नहीं है। दैनिक की बात ठीक है लेकिन राजस्थान में बीसियों साप्ताहिक पत्र निकलते हैं।........

श्री हजारीलाल शर्मा—८० साप्ताहिक पत्र निकलते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं तो बीसियों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उनके पास जो लिस्ट है उनमें से २०-२२ की ही दौड़ पहुँचती है बाकी किसी श्रेणी में गिने जाते हैं या नहीं लेकिन सरकार के पास २०-२२ की ही पहुँच है। बाकी साप्ताहिक हैं उनकी विज्ञापन की दरें ७ रुपये कालम इंच से २ रु० कालम इंच तक परिवर्तन होता है और है। कुछ साप्ताहिक

[श्री हरि कृष्ण व्यास] .

ऐसे हैं जिनको ७ रु० की दर दी जाती है और कुछ साप्ताहिक है उनको ५ रु० की दर दी जाती है, कुछ साप्ताहिक हैं जिनको ३ रु० पर कोलम इंच दिये जाते हैं और कुछ ऐसे साप्ताहिक हैं जिनके २ संस्करण निकलते हैं और दोनों अलग संस्करणों को अलग अलग विज्ञापन दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, किस बिनापर होता है सरकूलेशन के आधार पर होता है क्या ? स्टेन्डिग के आधार पर होता है क्या ? इस बारे में जहां तक हमको जानकारी है कोई स्थिति ध्यान में नहीं आती। केवल एक आधार नजर आता है और वह यह कि सरकार के उच्च स्तर के लोग चाहे अधिकारी हों, चाहे मंत्री लोग हों, उनके कृपा पात्र समझ कर ही उनकी दर अलबत्ता ज्यादा दी जाती है। उदयपुर का एक साप्ताहिक पेपर है जो मशहूर है। नवजीवन उसका नाम है। मैं अभी उसका बहुत ज्यादा जिक्र करूंगा, माननीय चेयरमेन, यह दुनिया जानती है और जिस किसी ने उसको देखा है उसमें से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि न तो उसकी छपाई खास सुन्दर है और न खबरें उसमें ज्यादा या विशेष पाई जाती हैं। लेकिन जहां तक विज्ञापन देने का सवाल है डेलीज के मुकाबले में उसका नंबर आता है। क्यों आता है ? सिवाय इसके कोई कारण नहीं कि उसका राजस्थान के मंत्रीगणों और विशेष कर मुख्य मंत्रीजी से नजदीकी संबंध है और इसी कारण से विशेष कृपा के रूप में ऐसी दरें देने की बात हो रही है।

दूसरा समाचार पत्र है अमर ज्योति जिसकी ७ रुपये कोलम इंच की दर है। दूसरों को किसी को ५ रु० है तो किसी को तीन रुपया मैं फिर यह पूछना चाहता हूँ चेयरमेन महोदय, कि यह किस बिना पर तय किया गया ? मुझे जानकारी है, निश्चित तौर पर कि आज तक कोई जांच नहीं हुई जिस की बिना पर यह तय किया गया हो कि अमुक अमुक पेपर का स्टेन्डर्ड अमुक अमुक तरह का है इसलिये अमुक अमुक दर दी जाय। लेकिन केवल इतनी ही बात नहीं है। कुछ दिन पहले विरोधी पक्ष के नेता कह रहे थे कि उनकी दर देने के मामले में न सिर्फ कोई नीति नहीं है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि सरकार के पास में कोई जानकारी भी नहीं है। एक कोई समाचार पत्र है चाहे दैनिक है या साप्ताहिक जिनका विज्ञापन कोई छपा हुआ है जो अपने यहां से अपनी ओर से विज्ञापन कार्ड सारी दुनिया में भेजते हैं, फर्म्स को भेजते हैं, कंपनीज को भेजते हैं,, एडवरटाइजिंग एजेन्सीज को भेजते हैं। उस कार्ड में उनकी दरों को देख लीजिये आपको नजर आयगा कि २ रु० या ३ रु० कालम इंच है। दूसरी ओर सरकार की विज्ञापन दर देखिये ७ रु० या ५ रु० कोलम इंच नजर आती है और छपी हुई दरों को जरा बाजू में रखें, जो रेट कार्ड्स में उनको बाजू में रखें और वास्तविक स्थिति क्या है, हकीकत में दूसरी कंपनियों के एडवरटिज्म को किस दर से छापते हैं। आप देखेंगे तो १२ आना १० आना कोलम इंच के हिसाब से छपने वाले समाचार पत्र सरकार से ७ रु० या ५ रू० कोलम इंच का बिल बनाकर पैसा वसूल करते हैं, इसका क्या कारण है ? सरकार के पास जानकारी पहुँच नहीं पाती क्या ? नींद खुली नहीं क्या कारण है कि पता नहीं लगाया जाता ? बाजार में सामान खरीदते के लिये भेजते हैं और ५ रु०की चीज का ५० रुपयादे दिये जावें तो कहेंगे कि ऐसे नालायक भ्रष्टाचार अधिकारी को हम कभी नहीं चला सकते। लेकिन समाचार पत्रों

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

में विज्ञापन देने वाले अधिकारी आपके सामने बैठे रहें, एक नहीं २० बैठे रहें और सरकार के हजारों,लाखों रुपये खर्च किये जावें। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अखबार के दुनिया के विज्ञापन १ रु० कोलम इंच में छापते हैं उनको राजस्थान सरकार सात गुना या आठ गुना किस बिना पर देती है ? यह क्यों दिया जाता रहा और आज तक क्यों कायम रखा गया ? केवल इतनी ही बात नहीं है। दर की ही बात हो इतना ही नहीं है। जो विज्ञापन देने का तरीका है सरकार का और जो स्टेन्डर्ड है उसमें भी विचित्र बात नजर आएगी। डिस्क्रिमिनेशन्स भी किये जा रहे हैं सरकार के विरूद्ध राय रखनेवाले पत्रों के साथ। उनको विज्ञापनों से महरूम रहना पड़ता है और उनको महरूम रखने की नीति अपनाई जाती है उसका बाद में जिक्र करूंगा। लेकिन विज्ञापन देने का तरीका इस प्रकार का है कि कुछ को बहुत दिया जाता है और कुछ को बिल्कुल कम दिया जाता है। मैं अर्ज करूं कि जयपुर से दैनिक पत्र जो निकलते हैं उनका उल्लेख गृह मंत्रीजी ने किया लेकिन शायद वे भूल गये कि जयपुर में दैनिक लोकवाणी और नवयुग को रखा गया है इसके अलावा भी और कई समाचार पत्र हैं राजस्थान में। वह जो नवयुग साप्ताहिक पत्र है जिसका उल्लेख करना मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी भूल गये उस एक साप्ताहिक पत्र को पिछले वर्ष में १३००० रु० से ज्यादा दिये गये हैं। शायद दैनिक के नजदीक उसका नंबर आया है। मुझे भी अनुभव है चेयरमेन महोदय; और मैं कह सकता हूं कि इसके आधार पर कि उस पत्र के स्टाफ में एक या दो आदमी गिनलें १०० रु० या १२५ रु० माहवार की तनख्वा वाले और उस पत्र की कुल कोस्ट छपाई पर होती है, जैसी छपाई होती है उसका अन्दाजा लगालें और आप अच्छी से अच्छी छपाई की कोस्ट गिनलें तो भी उसकी टोटल कोस्ट साल भर की ११ हजार से ज्यादा नहीं बैठेगी। और उसको अकेले विज्ञापन से १३००० रुपये दिये गये सरकार द्वारा। यह बिल्कुल सच्ची बात है और मैंने इसका पता लगाया है खास तौर से। और भी कई समाचार पत्र हैं। कई साप्ताहिक हैं जिनको किसी को काम और किसी को ज्यादा दिया गया है। प्रजासेवक और अमर ज्योति को भी दिया गया है। यह मैं मानता हूँ कि प्रजासेवक और अमर ज्योति अपने ढंग के अच्छे साप्ताहिक समाचार पत्र है उनका स्थान माभूली नहीं है। लेकिन फिर भी उनके स्टेन्डर्ड के बीच में जमीन आसमान का अंतर है और दूसरे ऐसे भी साप्ताहिक समाचार पत्र हैं जिनकी सूरत शक्ल नजर आवे तो मेरा ख्याल है कि सारा सदन सिवाय हंसने के और कुछ कर नहीं सकता। सदन की मदद के लिये मैं एक साप्ताहिक की स्पेसिमेन कोपी लाया हूँ। यह जनवाणी पत्र कोटा से निकलता है। इसके कुल ४ पेज हैं और यह पूरा समाचार पत्र है। इसकी स्टेन्डिग का पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि कुल १५०. २०० कोपीज का प्रिन्ट ओर्डर है कंपलीमेन्ट्री कोपीज मिनिस्टर्स के पास पहुँच जाती हैं इसलिये इसको विज्ञापन दे दिये जाते हैं।

आप इसके आखिरी पेज को देखें इसमें आधे से ज्यादा एडवरटाइजमेंट हैं, बीच के पेज को देखें इसमें भी आधे से ज्यादा विज्ञापन है। अब सिर्फ एक पेज रह जाता है जिसमें थोड़ी सूचनाएं हैं बाकी सब विज्ञापनों से भरा हुआ है। मेरे ख्याल से इस अखबार पर जितना खर्चा होता होगा उससे दस गुना या बारह गुना विज्ञापनों के रूप में उनको उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा यह

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

निकलता कब है, जब इसको विज्ञापन मिल जाते हैं। इस पत्र के चलाने वाले राजस्थान के एक मंत्री के नजदीकी संबन्धी है और चल रहा है और उनको विज्ञापन दिये जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे कोनसी पब्लिक का हित हो सकता है। किसके सामने आपकी यह सूचना भेजी जा रही है ? किस विभाग के फायदे के लिये यह खर्च किया जा रहा है ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह गवर्नमेंट की तरफ से विज्ञापन दिये गये हैं या कोई व्यापारी की तरफ से ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह गवर्नमेंट के विज्ञापन हैं साहब।

कु० श्री जसवन्त सिंह—यही मैं आपसे कहलवाना चाहता था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो मैं अर्ज कर रहा था कि यह एक नमूना है विज्ञापन देने का इतना ही नहीं लेकिन मैं यह निश्चित तौर से कह सकता हूँ और इस बात को जानता हूँ कि इसको कौन्ट्राडिक्ट किया जाएगा इस बात को जानते हुए भी कहता हूँ और फिर मैं इसको दोहराऊंगा, इस इरादे से कहता हूं कि कुछ समाचार पत्रों को सरकार की तरफ से ऑर्डर मिले नहीं तो भी उन्होंने विज्ञापनों को छाप दिये, छाप देते हैं। छापे हैं बावले होकर बगैर ऑर्डर के छाप देते हैं। सरकार को कोई अफसोस की जरूरत नहीं क्योंकि वहां ऐसे ठाठदार तरीकों से काम करने वाले बैठे हैं छापते हैं। महीनों बीत जाने के बाद वे लोग जयपुर में आकर अपना बिल बना कर सरकार को देते हैं। जब कहा जाता है कि ऑर्डर तो नहीं भेजा गया था। उसका उत्तर देते हैं कि ऑर्डर नहीं दिया तो क्या हुआ काम तो आपका हो गया। आपकी नीड सर्व हुई या नहीं यह बताइये। डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स को टेलीफोन से इत्तिला मिलती है और वे फाइल में लिखते हैं हालां कि ऑर्डर तो नहीं था लेकिन सरकार की नीड पूरी हुई है। यह बात विभाग के लोग कहते हैं और नीड पूरी हो जाने का फारमूला पर दो चार रुपये नहीं सैकड़ों रुपये दे दिये जाते हैं। यह कौनसा तरीका है ?

श्री जसवन्त सिंह—यह जन-सेवा का।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कौनसा तरीका है जिसमें सरकार का कोई ऑर्डर नहीं ? कहा जावेगा और क्या कहा जावेगा कि ओरल ऑर्डर थे। इसको मैं स्वीकार करने के लिये तैयार हूंगा कि जिस दिन औरल ऑर्डर जिसने दिया है उसने एमरजेन्सी की वजह से ओरल ऑर्डर दिया और उसको दूसरे वर्किंग डे पर फाइल में इसका इन्द्राज किया कि एमरजेन्सी की वजह से जुबानी आर्डर दिया गया और अब ऑर्डर भेजा जाता है। अगर ऐसा है तो वे मैं उनके जुबानी ऑर्डर को मान सकता हूँ। मगर ऐसा है नहीं, कई महिनों के बाद बिल पेश होते हैं। यह पक्षपात नहीं तो क्या है ? यह रुल को छोड़ कर सरकारी पैसों को बरबाद करना नहीं तो और

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

क्या है ? यह गवर्नमेंट का विज्ञापन देने का नमूना है। माननीय चेयरमेन, मुझे थोड़ा समय तो इसमें लगेगा मगर पी. डब्ल्यू डी. के कटौती के मोशन में मैंने जबाब को फोरगो किया क्योंकि मैं जानता था कि इसमें तो मुझे ज्यादा समय लगेगा। तो मैं कह रहा था विज्ञापन के लिये व उसकी रेटस के बारे में वगैर ऑर्डर के छपते हैं सो छपते ही हैं एक बात मैंने देखी जो कहीं पर भी नहीं होती वह यह कि जब कभी कोई सरकारी अधिकारी ने भाषण दिया वह भी विज्ञापन के रूप में छपा। भारत वर्ष में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता।

('हिअर हियर' की आवाज विरोधी दल की ओर से)

मैंने हिन्दुस्तान में समाचार पत्रों को देखा है। कभी भी किसी के भाषण विज्ञापन के रूप में नहीं निकलते। सिवाय बड़ी बड़ी कम्पनियों के जब बैलेन्सशीट छपते हैं। अगर सरकार भी कम्पनी के रूप में जाती है तो यह अलग बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कम्पनियों का रुख इस तरह से हो तो उनका दिवाला हो जावेगा। ऐसी गलत कम्पनी का दिवाला निकल जावेगा यह आप मान कर चलें।

अब मैं आपको आगे बताऊं कि यहां क्या हो रहा है। हमारे यहां पुरानी कहावत है मारी मारी छालियों ने दइयो दुधियो पांउ और नारियो आवे तो लात री मचकाऊ : यानी मेरे मेरे लोगों को दूध दही खिला पिला कर मोटा और ताजा करें और जो कोई गड़बड़ करनेवाला आवे तो उसको लात मार कर हटा दें। यही नीति आज कल विज्ञापनों के सिल सिले में बरती जा रही है। एक जमाना था जब राजस्थान में एक समाचार को ही प्रोटेक्शन मिलता था। उस समय की सरकार ने दूसरे समाचार पत्रों के साथ गड़बड़ी करने का दृष्टिकोण रखा और मैं समझता हूँ कि वह भी गलत था। उसके बाद सरकार के व्यक्तियों में परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन का नतीजा यह हुआ कि उन्होंने उनके विरोध करने वाले समाचार पत्रों के साथ विज्ञापनों को न देने की नीति अपनाई और वह भी गलत मानता हूं और आज तीसरी गलती जो हो रही है जो दोनों पिछली सरकारों से ज्यादा खराब है इसलिये कि तीसरी गलती जब हो रही है जब जब प्रेस आयोग की रिपोर्ट हमारे सामने आई है। इसमें साफ साफ लिखा है। इसमें मैं समझता हूं कि कोई दो राय नहीं होनी चाहियें मैं आपको उसे पढ़ कर सुना देता हूं। पेज ३२३ पर उनके शब्द इस प्रकार हैं जिनको मैं कोट कर रहा हूं:

"In any case the withdrawal of advertisements cannot and should not be a substitute for or alternative to legal action. We also hold that liberty and freedom to place advertisements wherever it likes which a private advertiser enjoys cannot be conceded to the Government which is a trustee of public funds and therefore bound to utilize them without discrimination,"

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अभी कुछ दिन पहले इस पर जब चर्चा हो रही थी तो मैंने सुना, मेरे माननीय मंत्री कह रहे थे कि हम अखबारों का स्तर देखते हैं। यदि किसी का स्तर नीचा चला जावे तो सरकार विज्ञापन नहीं देगी। प्रेस अयोग यह कहता है कि इस प्रकार की आजादी सरकार को नहीं दी जा सकती उसको बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन, बगैर किसी पक्षपात के सब को देना होगा और यह भी कोई उत्तर है कि अमुक पेपर सरकार की तारीफ नहीं करता और आलोचना करता है इसलिए इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जावे कि इसको विज्ञापन नहीं दिये जावें।

लेकिन चाहें वे आलोचना करते हों या नहीं नीति में प्रोटेक्शन होना जरूरी है। आज आलोचना करने का हमको अधिकार है, राजस्थान सरकार की विज्ञापन में भेद करने की नीति पक्षपात करने की नीति है वह प्रजातंत्र को गला घोंटने वाली नीति है। अपनी तारीफ करने वाले पत्रों को ही विज्ञापन दिये जाते हैं चाहे उसका स्तर कुछ भी हो यह अन्धी नीति है जिसको बन्द किया जाना चाहिये। मैं कई बातों में खुद राष्ट्रदूत पत्र की नीति से सहमत नहीं हूं लेकिन मैं इस सिद्धान्त को मानता हूं प्रजा-तंत्र में एक दूसरे को अपने विचार व मतभेद प्रगट करने का पूर्ण अधिकार है एक विशेष रुख रखने का वैसा अधिकार हम लोगों को और हर व्यक्ति को प्राप्त है। सरकार की नीति विरोध करने वाले समाचारपत्रों को इसलिये विज्ञापन नहीं देना कि वह उनकी नीति से मेल नहीं खाता है वह उनकी तारीफ नहीं करता है घोर अन्याय है यह ओछी प्रवृति और अशोभनीय नीति है इसको किसी भी हालत में ठीक नहीं गिना जा सकता। यह जो डिसक्रीमिनेशन की नीति सरकार ने अपना रखी है उसकी मैं घोर आलोचना करता हूं। और इसी नीति को प्रदर्शित करने के लिये मैंने इस विविध के सिलसिले में कटोती का प्रस्ताव रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक दूसरे पहलू की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विज्ञापन के बारे में प्रेस आयोग ने यह कहा है कि जब अत्यंत आवश्यक हो और बिल्कुल आवश्यक हो तभी विज्ञापन के लिये दिया जाना चाहिये। केवल इस लिये कि कुछ समाचार पत्रों को आमदनी करानी है, महज इस नीयत से यदि विज्ञापन दिये जायेंगे तो वह बिल्कुल अन्यायपूर्ण और सरकार को नुकसान देने वाला हो सकता है और ऐसा हुआ भी है। मैं एक आपके सामने मिसाल दूं शिक्षा विभाग द्वारा एक विज्ञापन शाया किया गया है कुछ समय पहले। वह विज्ञापन शिक्षा विभाग द्वारा जिन पुस्तकों को मन्जूर शुदा कराया गया वह सारी की सारी पुस्तकों की लिस्ट थी, इसके विज्ञापन पांच पत्रों को दिये गये। इस विज्ञापन के पीछे करीब ८ हजार रुपया खर्च हुआ है वह सरकार को भुगतने पड़े हैं। एक एकपत्र को १२०० और १४०० रुपये के करीब दिये गये। विज्ञापन में क्या था कि अमुक-अमुक पुस्तकों को सरकार द्वारा मन्जूरी दी गई है। अब आप देखिये वे बुक्स क्या नयी थीं, नहीं। आज से तीन साल पहले जिन पुस्तकों को मन्जूर कर लिया था उन्हीं पुस्तकों को १९५४. ५५ में रखा गया था यदि कुछ संशोधन होता तो बात दूसरी, इस पर विचार विनिमय हुआ यह निर्णय हुआ कि पहले से जो मन्जूर शुदा पुस्तकें हैं वही कायम रहेगी। नो चेन्ज, नोट इवन वन, नोट इवन इन रेस्पेक्ट आफ वन आइटम। अब केवल विद्यार्थियों और नागरिकों को केवल यह बताना था कि पहले से जो किताबें मन्जूर शुदा हैं वे ही कायम

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हैं केवल यह बात बताने के लिए एक एक पत्र १४०० और १८०० रुपये तक विज्ञापन के लिये दिये गये कि अमुक अमुक पुस्तकें कायम हैं। यह १८०० रुपये एक प्रकार से कुये में डालने के बराबर था। अगर विज्ञापन ही देना था तो केवल इतना ही विज्ञापन दे सकते थे कि आज तक जितनी भी पाठ्य पुस्तकें मन्जूर थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है वे ही लागू हैं इतना सा लिख देने मात्र से सारी दुनियां को मालूम हो जाता। सरकार यही उचित समझती थी कि पाठ्य पुस्तकों की सूची ही प्रकाशित करनी है तो जितना पैसा इस विज्ञापन के लिये दिया गया उतने पैसों में १० लाख प्रतियां छप सकतीं थी और वह हर जगह आसानी से बांटी जा सकती है। लेकिन यह कुछ न करके इन पत्रों को विज्ञापन के रूप में छापने के लिये दिया गया नवयुग, कांग्रेस सन्देश, लोकवाणी, नवजीवन और एक और पत्र को इस तरह से पांच पत्रों को यह विज्ञापन छापने के लिये दिया गया। इस चीज में विज्ञापन देने वाले महोदय ने कितनी दिलचस्पी ली यह देखने की बात है। शिक्षा विभाग ने यह लिखकर भेजा था कि केवल एक समाचार पत्र को ही यह विज्ञापन दिया जाय। पब्लिसटी डिपार्टमेंन्ट ने क्या किया केवल एक पत्र को ही नहीं उसने पांच पत्रों को पूरा विज्ञापन दे दिया। और इस तरह में इसमें सरकार का आठ हजार रुपया खर्च हो गया यह किसी को पता नहीं किसके हुक्म से यह हुआ ? जब शिक्षा विभाग को पूछते हैं तो वह कहता है कि हमने तो एक ही विज्ञापन के लिए कहा था और दर असल वे विज्ञापन पांच पत्रों में शाया हुआ है और इस तरह से हजारों रुपया खर्च हुआ है। अब इसकी जिम्मेवारी किस पर है पब्लिसिटी विभाग पर या शिक्षा विभाग पर ? यह केवल इसलिए किया गया कि कुछ समाचार पत्रों को हजार दो हजार रुपये की आमदनी कराई जाय इसलिये पांचों अखबारों को यह विज्ञापन दिया गया। शिक्षा विभाग का इस विज्ञापन के देने का महज एक ही दृष्टिकोण था वह यह कि एक ही बड़ा सा विज्ञापन दे दिया जाय हालां कि छोटा सा विज्ञापन से काम चल सकता था। विज्ञापन देते समय सारे भारत में एक तरीका बरता जाता है। भारत सरकार भी वही तरीका बरतती है वह यह कि अमुक अमुक विज्ञापन इतनी स्पेस में छाप दिये जांय। लेकिन राजस्थान सरकार की खासियत है कि आज तक जितने भी विज्ञापन दिये जाते हैं जहां सरकारी ब्लाक बनाकर देने का सवाल है वहां तो जितना ब्लाक होगा उतनी ही स्पेस में वह चीज आयगी किन्तु जिन चीजों का ब्लाक नहीं होता है उन दूसरे विज्ञापनों के लिए कभी स्पेस मुकर्रर नहीं की गई है। आज से करीब एक साल पहले से यह स्थिति चलती आ रही है कि जिस किसी पत्र में डाइरेक्टर महोदय की स्तुति छाप दी उसके दूसरे ही दिन उसके दूसरे अंक में पूरे पेज का विज्ञापन आपको नजर आजायगा। डाइरेक्टर महोदय की स्तुति छाप दीजिए उस हफ्ते में उस अखबार में सरकारी विज्ञापन नजर आजायगा। इस तरह के आचरण से क्या असर पड़ता है जनता में, क्या असर पड़ता है राजस्थान के उन लोगों पर जो कुछ पढ़े लिखे हैं, इसका क्या असर पड़ता है लोगों के दिमाग में कि विभागाध्यक्ष की स्तुति छाप दी उसकी एवज़ में उसको विज्ञापन छापने को मिल गया। यह आजकल हमारी प्रवृति चल रही है छोटी सी सूचना के तीन तीन पेज विज्ञापन दे दिये गये। मैंने जैसा कि पहले कहा भारत सरकार और दूसरी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सरकार सारी की सारी सरकारें अपनी स्पेस को स्पेसिफाइ करते हैं लेकिन राजस्थान सरकार ऐसा नहीं करती।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय का पूरा सदुपयोग कर रहा हूँ। मैंने पहले भी अपना समय काफी आपके समर्पण कर दिया, मुझे केवल पांच सात मिनिट और चाहिए।

यह विज्ञापन देने के बारे में जान बूझकर बड़े विज्ञापन देने की नीति बरती जाती है ताकि आमदनी ज्यादा हो उसकी एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। ३१ जनवरी का नवयुग है। उसमें शिक्षा विभाग द्वारा कुछ सामान खरीदे जाने का विज्ञापन छापा गया है। यह है वह विज्ञापन जो मैं सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ; यह पूरा पेज है। इस पेज को आप गौर कर के देखें इसमें सारी की सारी लिस्ट छाप दी है। आपको स्पेसिफिक लिस्ट चाहिये उसके डिटेल्स चाहिए तो आपको हमारे दफ्तर में मिल जायेंगे। इसी तरह से टेन्डर आदि देने वाले लोग होते हैं उनके साथ स्पेसिफिकेशन की लिस्ट जाती है। डिटेल्स जिस किसी को देखनी हो वह दफ्तर में आकर देख सकता है, लेकिन इस पत्र में क्या किया गया मैं समझता हूं या सारी दुनियां में अपनी तरह की एक ही मिसाल होगी कि एक टेन्डर फार्म को विज्ञापन के रूप में पूरा का पूरा नार्मल साइज में विज्ञापन के रूप में छाप दिया गया। इस बात को गृह मंत्री नोट कर लें टेन्डर फार्म को विज्ञापन के रूप में पूरा का पूरा नार्मल साइज में छापा गया। इसके बाद भी यह कहा जाता है कि सरकार इस बात में दुर्लक्ष्य नहीं कर रही है, मेरा यह दावा है कि टेन्डर फार्म का विज्ञापन अगर कहीं भी निकल आये किसी दूसरी सरकार की आप मुझे मिसाल बता दीजिए कहीं भी ऐसा नहीं देखने में आया। यह महज नवयुग की आमदनी बढ़ाने के लिए ही दिया गया है इसके सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता। टेन्डर फार्म दफ्तर में उपलब्ध हैं। दफ्तर से ले सकते हैं सारी दुनियां में यही परिपाटी है। पर इसमें टेन्डर फार्म का भी हुलिया दिया गया पूरे नारमल साइज में टेन्डर फार्म भी छापा गया। कुल कालम्स जो हैं उनका क्या खरचा पड़ेगा यह सरकार को अन्दाज से पता लगाना चाहिए था। सात रुपया पर इन्च कालम से साढ़े बारह इन्ची का स्पेस है उसका ढाई सौ, दो सौ रुपया होता है। दो सौ रुपया इसमें सरकार को अधिक खर्च करना पड़ा। इस रकम में पचास हजार टेन्डर फार्म अलग से सरकार छपा सकती थी और उनको हवाई जहाज से शहर में वितरित भी कर सकती थी। पर नवयुग को फिर आमदनी कहां से होती? यह भी तो बात थी। दो सौ, ढाई सौ, पौने दो सौ रुपया उसे कमवाने के लिए टेन्डर फार्म भी उसे छापने को दिया। तो मैंने सदन में दावा किया था कि सरकार की यह नीति दुर्नीति है, नीति नहीं है, वह कोई विज्ञापन की नीति नहीं है, कुनबापरस्ती की नीति है। तो यह दावा कोई गैर जिम्मेदार तरीके से नहीं किया था। मैंने पूरी पूरी छानबीन की है इन मामलों की, छ महीने मैंने इसको स्टडी करने में छान-बीन करने में, खोज करने में और अपनी जानकारी बढ़ाने में बिताये हैं ताकि आज जो वस्तु-

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

स्थिति है वह सही वस्तुस्थिति, वह सही सही हकीकत मेरे सामने आ जावे और इस पर पूरे छः महीने की खोजपूर्ण अध्ययन करने के बाद जिस निर्णय पर मैं पहुँचा हूं वह आपके सामने जाहिर करना चाहता हूं। और वह निर्णय यह है कि राजस्थान सरकार की ओर से अपने विरोध करने वाले पत्रों के साथ पक्षपातपूर्ण तरीके से गैर प्रजातांत्रिक तरीके से व्यवहार किया जाता है और शरारतपूर्ण तरीके से उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है और अपनी स्तुति गाने वाले समाचार पत्रों को शह देकर भद्दी तरह से विज्ञापन देकर विज्ञापन देने की नोबत न आवे तो वैसी स्थिति क्रीएट करके उन्हें विज्ञापन दिया जाता है, आमदनी उसकी बढ़ाई जाती है और नतीजा इसका क्या होता है? यह होता है कि सरकार की विज्ञापन में कोई नीति नहीं है तो यह नीति अपनी स्तुति करने वाले पत्रों की, अपने गुट्ट के पत्रों की विज्ञापन देकर परवरिश करने की नीति। सरकारी विज्ञापनों में सरकार की नीति परवरिश की नीति है, कुछ लोगों की परवरिश की नीति है और यह परवरिश की नीति प्रजातन्त्र का, जनतंत्र का, डेमोक्रेसी का गला घोंटने की नीति है, जनतंत्र का गला घोंटने वाली चीज है। लोगों के दिमाग में असर करने वाली चीज है। जो लोग देखना चाहते हैं उनके सामने यह परवरिश का मामला है, कोई नीति नहीं है, उसूल नहीं है, अपनी परवरिश करने की नीति के अनुसार कार्य करने की उनकी तैयारी है। उसूल के आधार पर आगे बढ़ने की उनकी तैयारी नहीं है।

कु. श्री **जसवन्तसिंह**—यह सोश्यलिस्टिक पेटर्न तो नहीं है?

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—इसको सोशलिस्टिक पेटर्न कहा जावेगा तो सोशलिज्म की जानकार रखने वाले को महसूस करना पड़ेगा कि यह सोशलिस्टिक पेटर्न के साथ आला दरजे का मजाक है और मजाक करने के सिलसिले में भी कहें तो तो ठीक है पर इसमें और कुछ नजर आता है। यह कुनबा पेटर्न है, ग्रुप पेटर्न है, स्वार्थ पेटर्न है और सबसे ज्यादा पेटर्न है वजीफेदारी का। अपने लोगों को बढ़ाने को वजीफेदो। इसमें यह सब है। नीति नाम की कोई चीज इसमें नहीं है। यह नहीं मान सकते कि इसमें किसी पार्टी का उसूल हो सकता है यह तो दुर्लक्ष की वजह से समझ लीजिये या अपने लोगों को प्रोत्साहन देने की वजह से इसका उपयोग करते हैं। नजदीकी ताल्लकु की वजह से इसका उपयोग करते हैं। यह एक कमजोरी का नमूना है इस कमजोरी को दूर करना चाहिये। अगर थोड़ा प्रयत्न किया जावे तो यह कमजोरी दूर की जा सकती है। इसमें फिर न नीति आड़ी आवेगी और न कोई उसूल आड़े आवेगा। पर चाहिये हिम्मत।

तो इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो तथ्य सामने रक्खे, जो आंकड़े सामने रक्खे और जो चीजें मैंने आपके सामने रक्खीं उन पर मैं चाहूंगा कि उधर से निश्चित रूप से जबाब मिले या जो मैंने आलोचना, शिकायत या टीका की है उसको स्वीकार करके सही नीति पर चलने की तैयारी यह सरकार दिखावे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने दो कटौती के प्रस्ताव में से एक का जिक्र करते हुए अपना कथन यहीं समाप्त करता हूं।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दूसरे प्रस्ताव के बारे में दो शब्द कहूँगा। क्योंकि समय कम है। पब्लिसिटी डिपार्टमेंट........

श्री नाथूराम मिर्धा—सदन के समय का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो ?

श्री हरिकिृष्ण व्यास—सदुपयोग कर रहा हूँ, इसलिये बताना पड़ रहा है। सरकार की क्या मनोवृत्ति है ? यह कहा जाता है यहां से बाहर कि सरकार हमारी है तो हमें तो ये विज्ञापन वगैरह देगी ही। हमारा पक्ष तो सरकार लेगी ही। तो मैं उस मनोवृत्ति के खिलाफ लड़ रहा हूँ और लड़ने की मेरी तैयारी है और इसमें मेरा मानना है यह कि समय का यह सदुपयोग होरहा है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस विभाग की ओर से जो पुस्तकें और पुस्तिकाएं आदि भी छपाई जातीं हैं उनके बारे में भीं यही स्थिति है। लगातार गवर्नमेंट प्रेस से छपाई कम होती जा रही है। और इधर उधर से छपाई होती है। रेट्स भी हाई दी जा रही हैं जो गवर्नमेंट प्रेस की मन्जूरशुदा रेटों से भी कहीं ज्यादा है और मुझे तो यहां तक पता चला है कि कई बार तो ऐसा होता है कि एक प्रेस को पहले से आर्डर देकर कह दिया जाता है कि कम्पोज करके मेटर तैयार कर लो। फिर कहते हैं गवर्नमेंट प्रेस से कि परसों तक ये किताबें छापकर दे सकते हो क्या ? तो परसों तरसों तक तो कोई प्रेस नहीं छाप कर दे सकता। इतनी जल्दी कोई नहीं दे सकता। तो इस आधार पर उनसे इनेबिलिटी सरटीफिकेट ले लिया जाता है। यह सरटीफिकेट आने पर इधर उधर छपाने को ले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इलेक्टरोल रोल के बारे में जो तरीका अपनाते हो, वह यहां क्यों नहीं अपनाते हो। प्रेस के पास छपाई का शिड्यूल बना पड़ा है और यह शिड्यूल सन् ५३ में बनी थी। तो दूसरे प्रसों से ऊंची ऊंची रेटों पर छपाने से पहले इस शिड्यूल को भी कम से कम गौर फरमा लें तो अच्छा है। पर सरकार की इस बनी शिड्यूल से सवाये, ड़ेढ़े भाव पर छपाई जाती है इस पर सोच विचार किया है आपने कभी ?

मैं समझता हूं कि जो तथ्य मैंने रक्खे हैं उसके बाद और ज्यादा दलीलों की आवश्यकता नहीं है और समय के बारे में भी उपाध्यक्ष बार बार सुचना देते जारहे हैं इसलिये और ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस गम्भीर प्रकार की खामी को दूर करने के लिये अब तो सरकार की तत्परता से आगे बढ़ने की तैयारी दिखाई देनी चाहिये और मैं समझता हूं कि सरकार भी यह चाहती है कि तत्परता से इस खामी को दूर करने के लिपे आगे बढ़ा जाय और इस बढ़ने का एक ही तरीका है मेरे ख्याल से और वह यह है कि मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करके वह आगे बढ़े। सरकार नहीं माने तो पार्टी को वह इधर उधर बान्धनेवाली नहीं। मैं मानता हूं कि राष्ट्रदूत कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाला पत्र है पर इसके बावजूद पार्टी के आधार पर इस प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता। यह सार्वजनिक नीति और नैतिकता का प्रश्न है मेरे इस प्रस्ताव के पक्ष में इधर उधर बैठने वाले सभी इसकी पार्टीबाजी का प्रश्न न बनाकर नैतिकता का प्रश्न बनाकर इसका समर्थन करें और सरकार की तैयारी नैतिकता के आधार पर चलने की न हो तो अपना मत इस कटौती के प्रस्ताव पर देकर सरकार को सही नैतिकता आने के रास्ते पर आने के लिये उसके

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हाथ मजबूत करें मुझे विश्वास है वे आज इस नीति को परित्याग करके सही नीति की ओर आगे बढ़ेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री अवनी कुमार मुकर्जी,—Hoping against hopes.

श्री हरिकृष्ण व्यास— मैंने कहा था "होप" नहीं "होप्स" । No hope from the Government.

श्री छीतरलाल शर्मा—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव मांग नम्बर ३३ पर प्रस्तुत करता हूँ ।।

एक म्यूनिसिपल कमेटी और दूसरा पंचायत....

श्री वेदपाल त्यागी—हम विभाग वाइज चलें तो ठीक होगा । अभी तो पब्लिसिटी ही चल रहा है । पंचायत को बाद में लिया जावे तो ठीक रहेगा ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—पब्लिसिटी ही पहले लिया जावे; ऐसा निर्णय हो गया है।

श्री चन्दनमल वैद—यह तो तय हो चुका है कि पब्लिसिटी पहले और पंचायत बाद में इससे बहस में और उसका उत्तर देने में दोनों में सहूलियत रहेगी ।

श्री भैरू सिंह—कइयों के कटौती के प्रस्ताव एक ही हैं। उनको इसमें दुविधा जरुर रहेगी तो इसको देखते हुए दोनों को एक साथ रख दिया जावे तो उचित होगा ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—इससे खिचड़ी हो जावेगी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो फैसला हो चुका है पहले ही कि पहले पब्लिसिटी ले लिया जावे और बाद में पंचायत ।

श्री उपाध्यक्ष—कौनसे सिलसिले की बात चाहते हैं ? पहले पब्लिसिटी और बाद में पंचायत, यही ठीक रहेगा।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय; इस विषय में मेरे दो स्पेसिफिक कटौती के प्रस्ताव हैं। इसका थोड़ासा शब्दों में ही हेर फेर है यह मैं पढ़कर सुना देता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष—कौन से सिलसिले की बात चाहते हैं, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की ?

श्री मानसिंह महार—पब्लिसिटी पर हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में मेरे दो स्पेसिफिक कटौती के प्रस्ताव हैं। उनमें थोड़े से शब्दों का ही हेर फेर है। यह मैं पढ़कर सुना देता हूँ—

"That the Demand No. 30 Major head 57-Miscellaneous be reduced by Re. 1/-(To discuss the wrong policy followed by the Publicity Department)."

एक तो यह है और दूसरा यह है—

"That the Demand No. 30 Major head 57-Miscellaneous be reduced by Re. 1/-(To discuss the favouritism shown by the Publicty Deptt. in giving Government Advertisements)."

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी दो रोज पहले मैंने कुछ बातें कहीं तो उस पर कुछ लोग नाराज हुए और यह कहा गया कि मुझ में बड़ी क्षेत्रीय भावना है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर राजस्थान के पब्लिसिटी के महकमे को देखेंगे तो क्षेत्रीय भावना मुझ में है या उन कहने वालों में है यह चीज तो उस महकमें के काले कारनामों से ही महसूस हो सकती है। उपाध्यक्षजी, अगर राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया में उन राज्यों को छोड़ दिया जाय जो कि बहुत बेकवर्ड हैं, राजाशाही के पुराने नमूने हैं उनको छोड़ कर, डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज में चलेंगे तो आज पब्लिसिटी विभाग राजस्थान में जैसा चल रहा है उसके मुकाबले में शायद ही कोई दूसरा राज्य कर सकेगा। मैं मानता हूँ कि राजस्थान बुरा कर रहा है या अच्छा कर रहा है, लेकिन और हिन्दुस्तान के प्रांतों के लिए वह एक ऐसी मिसाल पेश कर रहा है कि उनको इसका अथनकरण करना चाहिए राजस्थान की कुछ अनुकरणीय बातों को मैं सदन के समक्ष पेश करूंगा। मैं यह कहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि स्टेप मदरली ट्रीटमेंट राजस्थान सरकार कुछ पत्रों के साथ एडवरटाइजमेंट के मामलों में कर रही है। वह बहुत ही अन्यायपूर्ण है। मेरी शुरू से ऐसी कोई धारणा रही है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो पत्र सरकारी कार्यों की आलोचना करते हैं उसको मैं हमेशा से पढ़ता हूं और मैंने यह देखा है कि सरकारों के साथ साथ आलोचना करने वाले पत्र भी बदलते जाते हैं। कुछ हद तक ऐसी बातें हैं। मेरा दुर्भाग्य रहा है कि इन पत्रों के पढ़ने की वजह से मैं सरकारी एडवरटाइजमेंट से महरूम हो जाता हूं। पहले एक सरकार आई तो उसने बेचारे लोकवाणी अनायास ही नाराज होकर सरकारी एडवरटाइजमेंट देना बन्द कर दिया। इसके बाद जो देखा कि मैंने राष्ट्रदूत पत्र खरीदना शुरू कर दिया तब उस बेचारे राष्ट्रदूत को सरकारी एडवरटाइजमेंट देने बन्द होगये।........

श्री चन्दनमल वैद—यह कुसूर आपका है।

श्री मानसिंह महार—यह मेरे दिमाग की रचना है, उसका कुसूर है। क्योंकि मैं हां में हां करना और ज्यादा बड़ो हुकम पसन्द नहीं करता हूँ। इसलिए मैं समझता हूं कि यह मेरा दुर्भाग्य है। यह एक ऐतिहासिक चीज है कि कोई पत्र कोई सरकार के पद पर बैठते ही शुरु होता है। मुझे वे कहते हैं कि मुझ में क्षेत्रीयता है। वह पत्र है नवयुग उसका स्पष्ट नाम लेना चाहता हूं इसमें आप क्षेत्रीयता कह लीजिये चाहे और कुछ भावना कह लीजिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह पत्र महज इसलिये चालू किया गया है वह सरकार की वाहवाही करे। पुराने जमाने में भाट और चारणों को जागीरें देते थे। वह जागीरें इसलिए दी जाती थीं कि वे उन राजाओं की प्रशंसा के गीत गायें, गाने गायें। आज की सरकार उसी प्रकार से अपने काले कारनामों की प्रशंसा करवाने के लिए पत्रों में विज्ञापन देने की यह नीति अपना रही है। यह बिल्कुल सही बात है। इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है सरकार के पास। सरकार यह जो हमारा आरोप है उससे मुकर नहीं सकती। अगर सरकार इस बात से मुकरे तो हम सरकार से यह कहते हैं कि सरकार इसकी जांच कराये कि यह कहा तक वाजिब है। राष्ट्रदूत जैसे एक डेली पेपर को जो कि आज के दिन कम से कम मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थान की खबरों को बड़ी निर्भीकता से छापता है।

(हियर, हियर)

राष्ट्रदूत ही एक ऐसा जयपुर की राजधानी में पत्र है कि जिससे सही खबरों की आशा कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रदूत को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, जिन राजाओं के पुराने जमाने में यह कहा जाता था कि तुम लोग अन्यायी हो राजाओं का निरंकुश शासन है, उस निरंकुश शासन से उनके विरोध करने वाले पत्रों को कुछ विज्ञापन तो जरूर मिलते थे, लेकिन हमारी सरकार उस सीमा को पार कर चुकी है, और उन्होंने आज तो वह नीति अपनाई है कि उन्होंने आलोचना की कि वे नाराज हुए और उन्होंने फौरन विज्ञापन देना बन्द कर दिया।

दूसरी तरफ उदयपुर के नवजीवन को ले लीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसकी एक, दो कापियां ही देखी हैं। उनके देखने में मुझे तो यह मालूम पड़ता है कि यह तो अखबार नहीं है सरकारी गजट है। कोई खबर नहीं है। एक पाने पर माननीय मुख्य मंत्रीजी का फोटो होगा, उसके पीछे की तरफ १०-२० बातें होगी और ५०-६० परसेन्ट विज्ञापन होंगे।

यह एक तरह के दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पत्रकार लोग भी इस प्रकार की बातों की ओर जा रहे हैं। यह तो और भी दुर्भाग्य की बात है। हम सरकार को उलाहना देते हैं। मैं कहता हूँ कि राजस्थान के पत्रकारों को अपनी एक युनियन बनाकर यह तय करना चाहिए कि इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण कार्य होता है तो उन पत्रों को सरकारी विज्ञापन लेने से बायकाट कर देना चाहिए। अगर वे निर्भीक पत्र और पत्रकार हैं तो उन्हें यह तो कर ही देना चाहिए। आज डेढ़ साल के अन्दर, सरकार, मैं जरूर तारीफ करता हूँ, कि उन्होंने पत्रकारों के ऊपर, मैं यह आरोप पत्रकार भाइयों

[श्री मानसिंह महार]

के ऊपर आपके जरिये लगाना चाहता हूँ, ऐसा जादू का डंडा फिराया कि सरकारी नीति के लिए कई लोग कुछ कहते हैं तो उनके ऊपर बिल्कुल काली स्याही फेरी जाती है। मैं नहीं समझता कि हमारे मित्र सरकार के विरोध में जो वाजिब कहते हैं उसको वे नहीं कहते हैं। उसको कहां डाटी दे देते हैं। यह भी एक रहस्य की बात है। सुना जाता है कि जहां पत्रकार जाते हैं वहां पर बड़ी बड़ी पार्टियां दी जाती हैं। हमको तो असेम्बली से २०० रु० मिलता है और यह १२ रु० रोज जो मिलते हैं वे तो यहीं खर्च हो जाते हैं, तो पार्टियां दे नहीं सकते। लेकिन हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट उनको बड़ी २ पार्टियां देता है, अच्छी बात है कि पत्रकारों को पार्टियां डट कर खानी चाहिए इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, लेकिन पार्टियों से इतना नहीं डरना चाहिए कि फिर ज्यादा बात लिखने से नमक हराम हो जायेंगे। ऐसी बात नहीं चलनी चाहिए। नमक खाकर हम सरकार के समर्थक हैं, सरकार को जी हुजूर कहते है, लेकिन जहां सच्चा मामला आता है वहां सरकार को कहते हैं। हम सरकार से न्याय करवाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि हमारे पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं उनकी अन्तरात्मा इन शब्दों में मेरा साथ दे रही है। वह भी इस बात को महसूस करते हैं कि राष्ट्रदूत जैसे पत्र को जरूर विज्ञापन देना चाहिए। लेकिन अन्तरात्मा क्या करे? जब कि ऊपर की आत्मा आती है तो सबको दबोच लेती है। (हंसी) यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत अन्याय है और अगर राजस्थान में क्षेत्रीय भावना, कुनबा परस्ती, गुट परस्ती इन बातों की अगर कोई वाकाई मिसाल चाहे तो वह है पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट। आप कई मौकों पर उपाध्यक्ष महोदय, यह पावेंगे कि हमारे पब्लिसिटी ऑफिसर्स हैं उनकी इस प्रकार की पब्लिसिटी अखबारों में मिलती है कि जिसकी कोई हद नहीं। पब्लिसिटी का महकमा जयपुर रियासत में था जब सर मिर्जा इस्माइल थे, उस समय वह कायम किया गया था और इस महकमों को जिन लाइन्स पर शुरू किया था उनके बारे में चन्द बातें निवेदन कर दूं। उस समय ईश्वरदत्त नियुक्त किये गये उनको मिर्जा साहब स्पेशियली मैसूर से लाये थे। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय उन्होंने भी यही नीति अपनाई थी और इसी हाउस के अन्दर इन कुर्सियों पर तो नहीं किन्तु मैं उन दिनों उन कुर्सियों पर बैठता था, पीछे की तरफ आगे नहीं। उस समय भी मैंने आरोप लगाया था कि आपका जो पब्लिसिटी का महकमा है वह आपकी वाह—वाही के सिवाय वास्तविक जनता को लाभ नहीं पहुँचा रहा है। उन्होंने भी उस वक्त महसूस किया था। आई सी. एस. होते हुए भी जनता की आवाज की किस तरह कदर करना चाहिए। उन्होंने भी अपने महकमे में एक तरीका अपना लिया था, पब्लिसिटी के लिए, एग्रीकल्चर महकमे में काश्तकारी के मुतल्लिक जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उन सब के बुलेटिन्स छपवाते थे, हजारों और लाखों की तादाद में बुलेटिन्स छपवाते थे और उन बुलेटिन्स को गांवों में वितरित करते थे और उनके छापने से क्या होता था? जनता को लाभ होता था। लेकिन आज तो परिस्थितियां विपरीत हैं। अगर राजस्थान में पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट चीजें छापेंगे तो उनका बड़ा मुलायम कागज होगा, बड़ा कीमती कागज होगा और उनके अन्दर लिखा पढ़ी

[श्री मानसिंह महार]

तो बहुत कम होगी और उनके अन्दर ज्यादा चीजें ये होंगी कि फलां जगह मंत्रीजी कैंची लिये हुए फीता काट रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, कई जगह तो स्कूल का उद्घाटन होगा, कहीं गटर का उद्घाटन होगा और कहीं पर पब्लिसिटी के अफसरान हैं उनकी मोटी मोटी चीजें छपी होंगी और उसके अलावा कोई चीज नहीं होती। वे जो बुलेटिन्स हैं, कोई चीज कह दीजिये, वे ऐसी चीजें नहीं हैं कि जो जनता के जीवन के लाभ के लिए होती हों और बांटी भी इतनी कम तादाद में जाती हैं कि या तो वे सदन के माननीय सदस्यों को या नवयुग जैसे पत्र हैं उनको या डेली अंग्रेजी के जो पत्र हैं उनको मिल जाती हैं।

सरकार की नई पोलिसी देखें। राजस्थान के अन्दर जो सबसे ज्यादा बटने वाला पत्र है उसको विज्ञापन नहीं दिये जाते और दिल्ली में जो पत्र छपते हैं, जिनका सरकुलेशन राजस्थान के अन्दर नहीं के बराबर है, उनको विज्ञापन दिये जाते हैं। इसका अर्थ क्या होगा ? इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि सरकार उन पत्रों को विज्ञापन देकर सरकार उन पत्रों को यह बता देनी चाहती है कि देखो हम आपके साथ हैं इतनी रियायत कर रहे हैं, इस सरकार का जरा ध्यान रख कर लोग जो कहते हैं उसको रद्दी की टोकरी में रख दें। इसका नतीजा यह हो रह है कि जो सरकार चाहती है वह होता है। उन पत्रों से और सरकार से निवेदन करूंगा कि इन विज्ञापनों को देने की नीति में इस प्रकार की जो गलत बातें कर रहे हैं वह बहुत अन्यायपूर्ण हैं।

आज एक नई बात और है

(घंटी)

मेरा तो कटौती का प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष—बहुत प्रस्ताव हैं, संक्षेप में कह दीजिये।

श्री मानसिंह महार—पहले वालों को एक घंटा दे दिया। मैं तो दो चार मिनिट में इधर उधर की कह कर खत्म कर दूंगा।

उपाध्यक्षजी, एक नई बात यह है कि आज कल हमारी सरकार ने राजस्थान में बड़े २ विकास खंड खोल रखे हैं, बड़े बड़े डेवलपमेन्ट के काम कर रही है, सरकार वहां भी पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट पत्रकारों को लेजाता है, बड़े बड़े इन्तजाम किये जाते हैं उन पत्रकारों के लिए, उनके लिए वो इन्तजाम किये जाते हैं जो मैं सदन में कहना नहीं चाहता लेकिन उसमें भी बड़ी भेद की नीति बरती जाती है। अंग्रेजी पत्रकारों को लेजाया जाता है इसलिए कि अंग्रेजी के पत्र हिन्दुस्तान भर में छपते हैं इसलिए हमारी सरकार के वे गुणगान करें और उनको घुमाया जाता है इसलिए कि सरकार के लू पोल्स को न पहुँचाये जाय। हिन्दी पत्रकारों को नहीं लेजाया जाता है और उनको

[श्री मानसिंह महार]

बिलकुल नेग्लेक्ट किया जाता है। वह जानती है कि यदि हिन्दी दैनिक वाले जावेंगे तो वे जनता से संपर्क स्थापित करेंगे और विकास खंडों में जो गुट परस्ती की बातें हो रही हैं उन गुट परिस्ती की बातों को छाप देंगे तो सारा मामला चौपट हो जावेगा। इसलिए उनको कभी नहीं लेजाया जाता। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के हिन्दी के दैनिक पत्र हैं, उनके संपादकों को ऐसे अवसरों पर लेजाया जाय ताकि आपके अच्छे अच्छे काम हैं, हमारे हिन्दी दैनिक पत्र जो गांव गांव में जाते हैं, राजस्थान की ग्रामीण जनता तक पहुँचते है उन सभी तक वे पहुँचे उससे जनता का लाभ हो, जनता यह सोचे कि हमारी सरकार यह कर रही है वह कर रही है।

इसके बाद मैं एक दो बातें और निवेदन करना चाहता हूं। वे यह है कि मेरी बातें कुछ लोगों को अप्रिय मालूम हो रही हैं, कुछ लोग यह समझते हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वे बिलकुल निराधार हैं। मैं तो चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारी सरकार इस प्रकार से चले कि हम जो कुछ कहते हैं वे बिलकुल निराधार साबित हों और आगे भी सरकार निराधार साबित करें। मैं पहला आदमी होऊंगा जो खुश होऊंगा और कहूँगा कि हमारी सरकार ने अन्याय नहीं किया है। लेकिन अन्याय किया है, इतना ग्लेरिंग अन्याय किया है जो पुराने जमाने में नहीं होता था। सामान्तशाही को मात करने वाला अन्याय आज किया जाय तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है।

मैं यह कहूंगा कि कुछ पत्रों को जब विज्ञापन बन्द किये गये थे उधर बैठने वाले कुछ साथियों ने खूब क्रिटिसाइज किया था लेकिन आज राष्ट्रदूत को बन्द है यह नहीं कहेंगे कि अन्याय हुआ है, आपको तो येन केन प्रकारेण करना है। मेरे पास कई रिपोर्ट वगैरा भी मौजूद हैं जिनमें से चाहूँ तो एक्स्प्लेनेटरी पढ़ कर सुना सकता हूं। लेकिन मैं ये बता नहीं सकता और आप घंटी बार बार बजाते हैं इसलिए उनको पटक देता हूँ। फिर भी आपकी आज्ञा मानता हूँ क्योंकि मैं इस कुर्सी को तीर्थ समान मानता हूँ। (हंसी) मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे जो होम मिनस्टर साहब हैं उनके पास यह महकमा है। उनको इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए और हमारी तरफ से सबसे बड़ी मांग यह है कि अगर आप न्याय करते हैं, अगर आप यह समझते हों कि हम न्याय करना चाहते हैं तो आप सदन में उठकर कह दीजिये कि सदस्यों ने वाजिब बात कही है, इस बात को उठकर कह दीजिये कि हमने राष्ट्रदूत के साथ अन्याय किया है और आयन्दा से हम इस अन्याय को रेक्टीफाई करते हैं, तो हम समझें कि आपने गलती करके भी बुद्धिमानी की है, आपकी चेतावनी के बाद हमने उसको अब रेक्टीफाई कर दिया।

पब्लिसिटी के बारे में ही क्या, इलेक्टोरलराल्स के बारे में जो पक्षपात हुआ है वह कुछ छिपा नहीं है।

लेकिन इलेक्टोरल रोल्स की तो यहां तक बात हुई कि ऐसी प्रेसेज से भी छपाई गई जिनको सरकार इलेक्टोरल रोल्स छापने के लिये नहीं दिये थे। उन प्रेसेज को कुछ मुनाफा लेकर दिया है। ये नये मिडिल मेन खडे किये गये हैं। ऐसे और भी मामलात

[श्री मानसिंह महार]

हैं । आज मैं हमारे होम मिनिस्टर साहब की परीक्षा का दिन मानता हूँ कि वे किस प्रकार के स्टेट फॉवर्ड आदमी हैं । किसी भी कारण से गलती हुई हो । चाहे वह गलती पब्लिसिटी ऑफिसर की हो या और किसी ओफिसर की हो तो भी उसे मंजूर करें । वाजिब बात को मंजूर करलें । इसमें लीपा पोती नहीं करें । कल सार्वजनिक विकास के बारे में जबाब मिला उससे बडा संतोष हुआ । मंत्री लोग अपनी भावना को क्लीयर करें हम चाहते हैं उन भावनाओं की कदर करते हैं । जो वाजिब बात है उसको अस्वीकार न करें । इतना कह कर क्योंकि आपकी आज्ञा आज ज्यादा कहने देने की नहीं है इसलिये अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री चांदमल मेहता—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है : "मांग संख्या ३० विषय ५७; विविध: में १ रुपये की कटौती कर दी जाय (विज्ञापन देने में सार्वजनिक संपर्क विभाग की पक्षपातपूर्ण नीति पर बहस करने के लिए)"

उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग के संबंध में बजट के समय भी वाद विवाद हुआ और आज भी दो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । मैं भी इस विषय पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं ।

सब से पहले हमें यह सोचना है कि अखबारों में विज्ञापन दिये क्यों जाते हैं और इस पर इतने रुपये क्यों खर्च किये जाते हैं ? सबसे पहली बात यह सोचने की है तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि आम तौर से सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि विज्ञापन देने का एक मकसद यह है कि जो बात विज्ञापन द्वारा जाहिर करनी चाहते हैं वह अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच जाय । इस दृष्टि से व्यापारी, दूसरे उद्योगपति आदि देते हैं और सरकार भी, जहां तक मैं समझता हूं, इसी दृष्टि से विज्ञापन देती है । यदि यह उसूल देखें तो हमें सोचना पड़ेगा कि राजस्थान सरकार ने अब तक जो विज्ञापन दिये हैं उनके लिए क्या आधार रखा है और उसके साथ दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो उसूल जाहिरात में हैं वह इस माने में ज्यादा बलवान है कि प्रेस कमीशन ने यह निश्चय किया जिसकी चर्चा जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने की कि इसमें किसी विचारधारा या किसी भेद भाव को नहीं मानना चाहिए । जो व्यक्ति अखबार देखने वाले हैं वे सभी विचारधारा के होते हैं । तो उन लोगों के पास इन चीजों को पहुँचाने के लिये सभी अखबारों के पास इस तरह के विज्ञापन भेजे जांय । कुछ लोग इस विचार के होते हैं कि सरकार के समर्थक पत्रों को पढ़ते हैं । कुछ लोग इस विचारधारा के होते हैं कि वे सरकार की आलोचना करने वाले अखबार पढ़ते हैं और कुछ लोग इस विचार-धारा के होते हैं कि सरकार का विरोध करने वाले पत्रों को पढ़ते हैं । तो जितनी भी विचार-धारा वाले अखबार हैं उन सब को विज्ञापन देने चाहिएं और यह इस आधार पर हो कि उस पत्र का सर्कूलेशन कितना है क्योंकि जिसका जितना अधिक सर्कूलेशन होगा और जिसका जैसा स्टेन्डर्ड होगा उसी के आधार पर उस पत्र को पढ़ने वाले लोग होते हैं । लेकिन जो आंकड़े

[श्री चांदमल मेहता]

सरकार की ओर से दिये गये हैं और जो चर्चाएं सामने आई हैं उनको देखने से मैं जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ वह नतीजा दूसरे ढंग का है और मैं दो तरह के विचार बनाने के लिये मजबूर हुआ हूं। मेरा पहला विचार यह है कि कुछ पत्रों को विज्ञापन देकर, सरकार की आलोचना की जाती है उसको बंद किया जाता है या आलोचना को बंद कराने के लिये विज्ञापन दिये जाते हैं जिसको दूसरे लफ्जों में यदि यह कहूँ कि रिश्वत दी जाती है तो बेजा नहीं होगा। और दूसरी ओर ऐसे पत्र हैं जिनको कुछ आदमियों को अपनी तरफ बनाये रखना है या अपनी विचारधारा का अधिक से अधिक प्रकाशन करना है। जहां तक पहली बात के बारे में निवेदन किया और जहां तक राजस्थान में विज्ञापन के जाहिरात का तालुक है, यह काम राजस्थान के पत्र अच्छी तरह से कर सकते हैं। राजस्थान में दैनिक पत्र जयपुर से अधिकतर निकाले जाते हैं यदि उनको विज्ञापन दिये जाते हैं तो एक तरह से ठीक ही है। लेकिन दिल्ली के पत्रों को भी विज्ञापन सरकार की ओर से जाते हैं। दिल्ली के पत्रों का चलन सिर्फ कुछ शहरों को छोड़ कर देहात में बिल्कुल नहीं है। जो अंग्रेजी पत्रों को पढ़ने के उत्सुक हैं उनको छोड़ कर आम तौर पर दिल्ली के पत्रों का सर्कुलेशन राजस्थान में कम होता है। जहां तक दिल्ली के पत्रों का संबंध है, दिल्ली के पत्र भारत की राजधानी से निकलते हैं। उनके सम्पादकीय लेख राजधानी से निकलते हैं। और बड़े बड़े लोगों तक पहुंचते हैं और उनमें जो कुछ खबरें छपती है उनसे सत्ता में परिवर्तन होने की गड़बड़ी हो सकती है। तो इस तरह की गड़बड़ न होजाय और खबरें ठीक तरह से निकल सकें इसलिये उन पत्रों को विज्ञापन दिये जाते हैं। मैंने कई बार दिल्ली के पत्रों को देखा है। एक पत्र हकूमत का समर्थन करता है और हकूमत की नीति में परिवर्तन हुए बिना ही शनैः शनैः हकूमत की बुराई करने लग जाता है। और अपनी नीति में परिवर्तन कर देता है। यह तब्दीली इस बात की द्योतक है कि यहां सरकार की नीति में परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन उनका मुंह बन्द किया गया है विज्ञापन देकर जो कि एक तरह का भ्रष्टाचार है। मैंने भ्रष्टाचार के वक्त बोलते हुए कहा था कि एडी से चोटी तक भ्रष्टाचार है और कहा गया था कि आखिर कुछ लोगों को और महकमों को तो बख्शिये। मेरे विचार में भ्रष्टाचार की परिभाषा है, जो रिश्वत लेते हैं, जो रिश्वत देते हैं वे भ्रष्टाचारी हैं और जिसकी निगाह में आ जाय और वह जांच करने में असफल रहे अधिकृत होते हुए भी वह भी भ्रष्टाचारी है। इसी कारण से एडी से चोटी तक की चर्चा की थी। यदि माननीय गृह मंत्रीजी की निगाह में आ जाय कि इस तरह के पत्रों को विज्ञापन दिये जाते हैं और उसके बाद भी यदि वही बात चालू रहे तो उसके बारे में क्या विचार होना चाहिए, इस बारे में कहने की आवश्यकता नहीं रहती है।

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि किस का कितना सर्कुलेशन है तो इस बारे में कोई आंकड़े हमारे सामने नहीं हैं लेकिन यह निश्चय तौर से कह सकता हूं कि यहां पर ३ दैनिक पत्र मुख्य हैं। उनमें सबसे अधिक सर्कुलेशन यदि किसी का है तो वह है राष्ट्रदूत का और कोई दैनिक पत्र जो सबसे पुराना है वह है लोकवाणी और जो नया पत्र है वह है नवयुग मुझे नवयुग से विरोध नहीं है। मैं उसको फलता फूलता देखना

[श्री चांदमल मेहता]

देखना चाहता हूँ। लेकिन ठेस दिल में पहुंचती है यहां के रवैये को देखकर जो पत्र अपना ऊंचा स्थान रखे सबसे अधिक जिसको सर्कुलेशन हो और जो प्रेस ब्यूरो से रजिस्टर्ड है और सिर्फ राष्ट्रदूत ही एक मात्र पेपर है जो रजिस्टर्ड है। ऐसे पत्र को एडवरटाइजमेन्ट देना बंद करें तो यह उचित नहीं हैं। मैं समझता हूं मंत्रीजी जब जवाब दे रहे थे तब विरोधी दल के नेता के भाषण के सम्बन्ध में कहा था कि हम उन पत्रों को इसलिए विज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे यहां दैनिक पत्रों की कमी है। असल में कमी है इसलिए प्रोत्साहन देना चाहते हैं। मेरे समझ में समझ में नहीं आया कि एक पत्र को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। क्या विज्ञापन न देकर उस पत्र को बंद करना नहीं चाहते हैं ? सरकार इसे स्वीकार करेगी कि जब एक पत्र को काफी अर्से तक विज्ञापन दिये जाते रहे हैं वे बंद कर दिये जांय तो उसका कारण क्या है ? यदि सही कारण है तो खोलकर सदन के सामने रखना चाहिये। यदि क्लीयर नहीं किया जाता है तो शक पैदा होता है कि आखिर इतना महत्वपूर्ण पत्र जो है उसको विज्ञापन देना बंद क्यों किया गया ?

माननीय उपाध्यक्ष, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि विज्ञापन देने के बारे में चर्चाएं हुई हैं। यदि विज्ञापन के खर्चे की तुलना गत वर्ष के खर्चे से की जावे तो कहना पड़ेगा कि गत वर्ष के मुकाबले में खर्चा काफी बढ़ा है वह इस माने में नहीं बढ़ा है कि उसका उपयोग हो बल्कि इस माने में बढ़ा है कि कोई किसी के जरिये से अपने समर्थकों को बिठाया जा सकता है। इस दृष्टि से यह खर्चा बढ़ाया गया है। मैंने कुछ पत्र देखे। मैं इस बात को मानता हूं कि मैं किसी ग्रुप में नहीं हूं। मुझे जो कुछ कहना होता है तो मैं विरोधी पक्ष के सदस्य जो सही बात कहते होते हैं उनका समर्थन करता हूं लेकिन मत देते वक्त तो मुझे व्हिप के आदेशानुसार जाना पड़ता है। मैंने अखबारों को देखने की कोशिश की और इस बात को खास तौर से देखने की कोशिश की कि आखिरकार इतना बड़ा रुपया दिया जाता है उसका सदुपयोग होता भी है या नहीं। तो मुझे इत्तफाक से एक पत्र मिला उस पत्र के बारे में आपसे निवेदन करूं और बताऊं कि किस तरह से विज्ञापन दिये जाते हैं। अलवर पत्रिका के संबन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ। उसमें यह पेज सारा प्रकाशन का है, यह पेज सारा, या पेज सारा विज्ञापन का है इसके आगे चलें तो सारा पेज विज्ञापन से भरा। इसका मतलब यह कि ८ पेज का अखबार है उसमें से ८० प्रतिशत तो माननीय उपाध्यक्ष, सरकारी विज्ञापनों से भरा है और जिस पत्र में ८० प्रतिशत विज्ञापन सरकारी हों उसको लोग क्यों पढ़ेंगे ? इसका एक ही कारण है कि आखिरकार सरकार को इस अलवर पत्रिका को जिन्दा रखना है। उनके पद को जिन्दा रखना है और उसे भी जिन्दा रखना है। अगर इसे जिन्दा रखने की बात है तो इसके संबन्ध में दूसरी बात हो सकती है। आप देखिये कि व्योपारी कितना समझदार होता है। मैं एक व्योपारी वर्ग का रहने वाला हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर व्योपारी किसी पत्र में एडवर्टाजमेंट देना चाहता है तो वह या तो जब देता है जब वह देख लेता है कि यह पत्र सरकार का कृपा पात्र है और इससे उसको कुछ फायदा होने वाला है तब देगा या दूसरा दृष्टिकोण उसका

[श्री चांदमल मेहता]

यह रहता है कि वह देखेगा कि जिस अखबार में एडवरटाइजमेन्ट देना है वह कितना पुराना है और वह कितने लोगों के पास पहुँचता है यानि कितने लोग उसको खरीदते हैं । इसका सारा नतीजा यह होगा कि वह जो एडवरटाइजमेन्ट देता है सब देखकर देता है उसी तरह से विज्ञापन सरकार को भी देना चाहिये । उसका पहला दृष्टिकोण जो अधिक फायदा उठाने का होता है उसमें सरकार को नहीं जाना चाहिए । सरकार को तो अपना जो दूसरा दृष्टिकोण है कि वह कितने लोगों के हाथ पहुंचता है उसको अपनाना चाहिए।

मैंने कुछ पत्रों को देखा, मालूम हुआ किसी में ६० परसेंट और किसी में ४० परसेंट और किसी में ८० परसेंट विज्ञापन दिये जाते हैं । इस सम्बन्ध में प्रेस कमीशन ने अपनी ओर से जो निश्चय किया है उसकी रिपोर्ट के पेज ३६६ और ६७ हैं उसमें यह कहा गया है कि किसी भी पत्र में सरकार की ओर से विज्ञापन दिये जावें वे ४० प्रतिशत से ज्यादा नहीं होने चाहिए ।

एक माननीय सदस्य—४० प्रतिशत या ४ प्रतिशत ।

श्री चांदमल मेहता—४ प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए । मगर मेरे पास अलवर पत्रिका है इसको देखने से पता चलता है कि कितना विज्ञापन दिया गया है । आज कल कई झूठे सांचे भी अखबार बहुत निकल जाते हैं, अन्त में निवेदन करूंगा कि स्पष्ट तौर से सरकार को समझना चाहिए कि विज्ञापन का आधार क्या है ? अगर सरकार का यह आधार है कि व्यक्तियों को प्रोत्साहन देना या उनको अपने साथ मिलाना है या जो पत्र अपने विचार देते हैं उसको ही विज्ञापन देना है तब तो दूसरी बात हो जाती है और अगर यह दृष्टिकोण है कि हम जो बात प्रकाशन करना चाहते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े और वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो उसकी सरकार को घोषणा करनी चाहिये कि क्या आधार है ।

(घंटी)

दूसरी बातें जो कही गई हैं उनको मैं यहां पर दोहराना नहीं चाहता । मगर मैं यह जरूर कहूँगा कि मैंने खास तौर से देखा है कि यहां के जो डाइरेक्टर हैं उनके ब्लोक देने का अवसर आवेगा तो उनका बहुत सुन्दर ब्लोक देंगे दूसरों के मुकाबले में । वह इसलिए कि हमने डाइरेक्टर साहब का ब्लोक दे दिया हमको अधिक विज्ञापन मिलेंगे । इस तरह की और भी कई बातें हैं ।

(घंटी)

इस संबंध में पिछले समय माननीय मंत्री ने बताया कि इस पर विचार रहे हैं । इसके अलावा यह भी देखना है किसरे एडवरटाइजमेन्ट की मारकेट में क्या रेट हैं और सरकार की रेट

[श्री चांदमल मेहता]

कितनी है और इस दोनों रेटों में कितना अन्तर है और इस संबंध में सरकार क्या करना चाहती है। इसके बारे में कहा यह जाता है कि सरकार सचेत रहती है। जिसमें नुकसान होता है उस मामले में सरकार हमेशा सचेत है। मैं चाहूंगा कि आज माननीय मन्त्री महोदय जब इस पर अपना उत्तर दें उसमें इसका भी उल्लेख करें और सदन को बतावें। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

(घंटी)

श्री चंदनमल वैद—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा कटौती का प्रस्ताव पत्रों में सरकार की विज्ञापन देने की नीति के सम्बन्ध में है। प्रजातंत्र के जमाने में हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी भिन्न भिन्न राय रखने की आजादी है और यह भी आजादी है कि वह अपनी राय को प्रगट करे। केवल इस आधार पर कि ये पत्र हमारी राय को प्रगट करते हैं उनको हम विज्ञापन देंगे और जो हमारी राय जाहिर नहीं करेंगे उनको विज्ञापन नहीं देंगे, प्रजातंत्र का गला घोंटना है। मैं यह कहूंगा कि इस प्रजातंत्र के युग में पत्रों की आजाद राय का गला घोंटना मानो प्रजातन्त्र का गला घोंटना होगा, केवल इस बिना पर कि एक पत्र हमारे बड़े बड़े ब्लाक नहीं छापता, हमारी नीति से अलग नीति रखता है उसको विज्ञापन नहीं देंगे, गलत है। अभी जो प्रेस कमिशन की रिपोर्ट निकली है उसमें यह साफ है कि चाहे पत्र साम्यवादी हो या सम्प्रदायवादी या दूसरे विचारों का उसका विज्ञापन बंद नहीं किया जा सकता सरकार द्वारा विज्ञापन देने के संबंध में क्या क्रीटेरिया होना चाहिये प्रेस कमीशन ने यह बताया है। मैं सबसे पहले यह बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन पत्रों को विज्ञापन नहीं दिया जावे, उन पत्रों को विज्ञापन नहीं दिया जाना चाहिये जो देश के लिए घातक हों, या गाली गलोज देने वाले हों या अनुचित काम करते हों उनको विज्ञापन नहीं दिया जाना चाहिये। अगर कोई पत्र समाज वादी और साम्यवादी है या किसी पार्टी की आलोचना करता है और विचार प्रगट करता है। तो केवल इसी आधार पर उसका विज्ञापन बंद नहीं किया जा सकता। माननीय उपाध्यक्ष, इस सिलसिले में मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति जो इलहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उनके फैसले की चार लाइनें जो बहुत एहम है उनको मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा जिससे कि हमारे माननीय होम मिनिस्टर इस पर ध्यान दें कि इस तरह की नीति अपनानी चाहिये—

Last para, Justice Bhargava of Allahabad, All India Reporter 950,. page 450, observed :—

" It is the right of every citizen of democratic government. to de spread dis-affection against a particular party government. "

The words are:—" disaffection against a particular party government. "

[श्री चंदनमल वैद]

" This right is, of course, subject to the condition that dis-affection should not be so spread as to result in violence and there should be really no incitement to use of violenc ore resort to other illegitimate fonrce. "

तो आज प्रजातंत्र के युग में इस बात का अधिकार दिया गया है कि अगर कोई सरकार के प्रति डिस अफेक्शन फैलता है तो कोई अपराध नहीं है। आपकी नीति से भिन्न नीति रखना आपके ब्लाक नहीं छापना, आपके फोटो नहीं छपना आपसे भिन्न राय प्रगट करना, इस तरह का अगर कोई व्यवहार करे तो विज्ञापन न दिया जाय। जो आपकी नीति है वह प्रजातंत्र के लिए घातक नीति है।

दूसरी बात की तरफ मैं और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह यह कि विज्ञापन किस को दिया जाना चाहिए। इसके लिए प्रेस कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया नियुक्त किया है। विज्ञापन देते वक्त यह ध्यान में रखना चाहिये पेपर्स का सरकुलेशन कितना है और किस एरिया में सरकुलेशन है यह भी देखना है कि किन लोगों में सरकुलेशन है उसके बाद पत्रों में विज्ञापन देना चाहिए। हमारे राजस्थान में विज्ञापन उन पत्रों को भी दिया जाता है जिनकी केवल कम्पलीमेन्टरी कापीज ही निकलती हैं जिनका संबन्ध इस एरिया से कुछ भी नहीं है। जयपुर सिटी डिवीजन के एक्जीक्युटिव इन्जीनियर विज्ञापन देते हैं और वह छपता है उदयपुर के पत्र में जिसका सरकुलेशन उदयपुर के बाहर कहीं नहीं है। जयपुर से सिटी डिवीजन के एक्जीक्युटिव इन्जीनियर टेन्डर इनवायट करते हैं वह विज्ञापन छपता है उययपुर से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र नवजीवन में। यह सरकार के पैसे का दुरुपयोग नहीं तो क्या है। वहां उस टेन्डर नोटिस और टेन्डर फार्म को कौन पढ़ने वाला है और उदयपुरके रहनेवाले वहां टेन्डर भेजने वाले कितने हैं इंसतरह की बातें होती हैं। आज अगर किसानों के सम्बन्ध में कुछविज्ञापन देना होता है तोयह छपता है शहरोंके पत्र में। और अगर शहर के आदमियों के लिये कोई विज्ञापन देना होता है तो वह छपता है गांव में जाने वालों पत्रों में। आज हमारी सरकार की केवल नीति है विज्ञापन देने की वह है किसी पत्र को परवरिश करने की। मैं बहुत जल्दी में सब मसाला इकट्ठा नहीं कर पाया फिर भी मैं कुछ चीजे इकट्ठी कर सका हूं वह आपके सामने रखने की चेष्टा करूंगा। विज्ञापन केवल परवरिश के लिये ही नहीं बल्कि कोमर्सियल बेसिस पर दिये जाते हैं। जनता से जो भी टेन्डर मांगे जाते हैं उसके लिये यह तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस सम्बन्ध में मालूम हो। लेकिन यदि इसमें भी परवरिश करने का तरीका हो तो मैं कहूंगा परवरिश करने के दूसरा तरीका है जो आप अपना रहे हैं और अपनाते रहे हैं और भविष्य में भी आप द्वारा अपनाये जायेंगे। आपने विज्ञापन को एक परवरिश करने का तरीका समझ रखा है। प्रेस कमीशन ने इस विषय में अपने विचार प्रगट करते हुए कहा है कि एक पत्र को सरकार कितने परसेन्ट विज्ञापन दे सकती है। उन्होंने सारे हिन्दुस्तान का एवरेज निकाल कर बताया है कि आम तोर पर सारे हिन्दुस्तान का एवरेज कोमर्सियल और सरकारी विज्ञापन सरकारी

[श्री चंदनमल वैद]

विज्ञापन सात परसेन्ट आया। बड़े बड़े शहर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और देहली के पत्रों में सरकारी विज्ञापन दूसरें विज्ञापन के तीन से सात परसेन्ट हैं। कमीशन ने इस बात की आलोचना की सरकारों ने १५-१६ और २० परसेन्ट तक विज्ञापन दिये हैं इस बात की उन्होंने भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का अन्तर नहीं होना चाहिये। प्रेस कमीशन ने १५-१६-२० परसेन्ट की जो भर्त्सना की और वह आलोचना करता है, मैं उसी के आधार पर सरकार को बतलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने सेन्ट परसेन्ट विज्ञापन उन पत्रों को दे रखा है जिनमें कमर्सियल विज्ञापन मिलते ही नहीं यदि मिलते भी है तो वे वन परसेन्ट से अधिक नहीं हैं।

मेरे पास नवजीवन पत्र की दो प्रतियां हैं, मैं ये दोनों अंक एट रेन्डम लाया हूं। इस विषय में मै माननीय गृह मंत्री से अर्ज करूंगा वे किसी भी साल के नवजीवन का कोईभी अंक उठा लें जो आंकड़े मैं दे रहा हूँ अगर वे गलत साबित कर सके तो कोई भी अंक छांटकर लायें मैं यह अंक छांटकर नहीं लाया हूं ये दोनों अंक ५५ तथा ५६ के अंक हैं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं पहले अंक ५५ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस अंक में जिसके आठ पेज हैं एक पेज पर चार कालम हैं इस तरह से ३२ कालम हैं इन बत्तीस कालमों में १७॥ कालम सरकारी विज्ञापन है। जहां ३२ कालमों में १७॥ कालम सरकारी विज्ञापन हो वहां दूसरे विज्ञापन का यह हाल है केवल आधा कालम सिनेमा का विज्ञापन है। और १७॥ कालम सरकारी विज्ञापन है। इन विज्ञापनों में पूरे के पूरे पेज विज्ञापन हैं टेन्डर नोटिस के पूरे के पूरे पेज भरे पडे हैं जिधर भी आप उलटिये आप को टेन्डर नोटिस के पेज के पेज मिलेंगे इसी तरह से अन्दर भी टेन्डर नोटिस हैं। यदि हम इसका परसेन्टेज निकाले तो मैं कह सकता हूँ ६६ (Point) ६ रेकरिंग सरकारी विज्ञापन हैं इस में जहां प्रेस कमीशन लिखता है, १५-२० परसेन्ट की भी भर्त्सना करता है वहां यहां पर ६६ (point) ६ रेकरिंग के सरकारी विज्ञापन हैं। आधा अखबार केवल सरकारी विज्ञापनों से भरा हुआ है इस अंक के छापने में जितना खर्चा हुआ उससे दस या आठ गुना खर्चा उसका विज्ञापन से निकल गया। क्या यह परवरिश की नीति नहीं है तो आखिर क्या नीति है आप ही बताइये ? आप इस पत्र की छपाई को देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा इसमें ऐसे चित्र छपे हुए हैं यदि किसी पुरुष का फोटो है तो उसको पहचान नहीं सकते वह स्त्री का फोटो या पुरुष का। इसी एक अंक में श्रीमन् राजप्रमुख का फोटो छपा है मैं समझ नहीं पाया कि यह राजप्रमुख का फोटो है या किसी जानवर का। इस बेहूदा तरीके से छापना और जिसमें ६६ प्रतिशत सरकारी विज्ञापन देना जिसमें अन्य कोई एडवरटीजमेन्ट नहीं। इसके लिये भी कोई लिखत ऑर्डर नहीं। उसके लिए कहा जाता है कि हमने मौखिक आर्डर दिया था। उपाध्यक्ष महोदय, नवजीवन को तो मौखिक ऑर्डर दिया था, क्या लोकवाणी या अन्य किसी पत्र को भी मंत्री महोदय कोई बतला सकते हैं ? हमारी सरकार यह मौखिक ऑर्डर कब से देने लगी सरकार का विभाग है, जहां मौखिक ऑर्डर भी दिये जाते है, टेन्डर भी मौखिक ही मांगे गये और अब तो मौखिक ही ऑर्डर देने लगे हैं। यह मौखिक ऑर्डर को साफ साफ क्यों नहीं स्वीकार किया जाता कि हमने ऑर्डर तो नहीं दिया था हमारे सम्बन्धी या हमारे रिश्तेदार थे हमारी गुड बुक्स में थे इस वास्ते हमने उनको छापने के बाद

[श्री चंदनमल वैद]

payment करने का ऑर्डर दिया। मौखिक ऑर्डर देने का कहां से नियम है और उसका पेमेन्ट कर दिया गया हो तो ऐसे डाइरेक्टर महोदय को चाहे वे किसी के कृपा पात्र क्यों न हो फौरन हटा देना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष, इसके अलावा मेरे पास इसी नवजीवन का एक दूसरा अंक भी है।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय का सदुपयोग ही कर रहा हूँ। मैं कुछ नयी बातें ही बता रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—संक्षेप में बतलाइये।

श्री चन्दनमल वैद—यह मेरे पास नवजीवन का ५६ का अंक है। इसमें ३२ कालम में १२॥ कालम सरकारी विज्ञापन है। १२ पेज में तीन पेज पर सरकारी विज्ञापन हैं पच्चीस परसेन्ट विज्ञापन हैं। इसमें भी कोमर्सियल विज्ञापन का वही हाल हैं, सिर्फ एक चौथाई कालम सिनेमा का विज्ञापन है। इसमें २५ प्रतिशत है पहले वाले में ५०परसेन्ट सरकारी विज्ञापन थे इस तरह से ६६ परसेन्ट विज्ञापन देना शायद हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहला ही उदाहरण होगा वह भी किसी ऑर्डर के मुताबिक नहीं बल्कि यह भी मौखिक ऑर्डर से ही दिया गया है यह हमारे लिये बड़ी शोचनीय बात है।

इसके बाद माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूँगा कि आखिर यह हिपोक्रेसी क्यों हो रही है? यह बनावटी बात क्यों हो रही है, हम कहते कुछ और करते कुछ और हैं। यह क्या बात है? हम कहते हैं समाजवाद की बात पर करते हैं वे बातें जिनको कुनबापरस्ती और न जाने क्या क्या परस्ती कहा जा सकता है। हम आंकड़े देते हैं और बताते हैं कि आपने जो पे स्केल बनाई है उसमें छोटे बड़ों में अन्तर बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ तो इसके विपरीत आप आंकड़े नहीं देते साबित आप कर नहीं सकते पर बड़ी अदा से, पान चबाते हुए, मुस्कराते हुए कहते है कि असमानता घट गई है और आंकड़ों का कोई उत्तर नहीं। तो इस तरह से मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार हिपोक्रेसी में क्यों आती है। कहती कुछ और है और करती कुछ और है।

माननीय उपाध्यक्ष, इसी तरह यह जो विज्ञापन की नीति इस सरकार ने अपना रक्खी है वह केवल गुट्ट विशेष को खुश रखने की भी नहीं है, बल्कि अपने खुशामदियों को खुश करने की है, यह भी नहीं कि कांग्रेस के पेपरों को विज्ञापन दिया जावे पर वहां तो केवल उन्हीं को दिया जाता है जो उनकी हां में हां मिलाने वाले हैं।

[श्री चन्दनमल वैद]

अभी बजट की बहस का उत्तर देते हुए हमारे गृहमंत्रीजी ने बताया नि लोकवाणी को नवयुग से ज्यादा विज्ञापन दिया गया है। यह इसलिए कहा गया कि लोग यह समझें कि नवयुग के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया है और यही समझ कर थोड़ा बहुत हिस्सा उसको भी डालते रहें। और फिर जगलरी ऑफ फिगर्स से बता रहे हैं कि नवयुग से ज्यादा लोकवाणी को दिया गया। यह जगलरी ऑफ फिगर्स है। और वह इस तरह से है कि लोकवाणी को एक फरवरी से दिये गये विज्ञापनों की यह कीमत है और नवयुग को अप्रेल से दिया गये विज्ञापनों के ये फिगर्स हैं। इस चीज को छिपा जाते हैं। और कहते हैं कि नवयुग को तो हमने २८,६५१) के विज्ञापन दिये और लोकवाणी को ३७५३२॥) के विज्ञापन दिये हैं। तो इस तरह से यह एक का ११ महीने का हिसाब है और दूसरे का ६ महीने का। ६ महीने और ११ महीने की बात छिपा कर कम्पेअर करना जगलरी ऑफ फिगर्स है और यह हमारे साथ मज़ाक किया गया है।

दूसरे ५६ के इस साल के दो महीनों के फिगरों के बारे में भी माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपको बताऊं लोकवाणी को ४४०३।) के विज्ञापन दिये गये और नवयुग को ४३७८।) रुपयों के इस रेशो से दो महीने की यह फिगर्स साल भर में ५२६६२) होते हैं। तो एक अखबार को विज्ञापन देने के लिए एक को खुश करने के लिए तिगुना खर्चा भी सरकार का विज्ञापन के लिए कराया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया गया कि सन् ५३ में राष्ट्रदूत और लोकवाणी को कितना विज्ञापन दिया गया। उन विज्ञापनों के फिगर्स १८६३४॥) होते हैं। सन् ५४ के उन्होंने नहीं बताये और ५४ के फिगर्स हमारे लिए मालूम करना सम्भव नहीं। तो ५३ के फिगर्स को कम्पेअर करें तो मालूम होगा कि ५३ में जयपुर में हमने १८६३४॥) कुल खर्च किये साल भर में जब कि जिस रेशो से हम ५६ के दो महीने में खर्च कर चुके हैं उससे साल भर में ५२६६२) बनते हैं तो इस तरह से यह विज्ञापन का खर्चा सन् ५३ से ५६ में करीब करीब तीन गुना हो गया। तो मैं पूछता हूं कि ऐसा कौन सा काम सरकार का बढ़ गया है, ऐसी कौनसी जरुरत आ पड़ी है सरकार को कि जयपुर जयपुर में विज्ञापन करने के लिए तीन गुना खर्च करना पड़ा। ५३ से तीन गुना विज्ञापन देना पड़ा पत्रों को और वह भी केवल जयपुर शहर के पत्रों को। ऐसा कौन सा काम हो गया। कौनसी ऐसी विज्ञापन करने की खास जरुरत आ पड़ी कि तीन गुना खर्चा जयपुर में करना पड़ा? यह सरकार के पैसों का रथलैस दुरुपयोग नहीं है तो और क्या है? इस तरह से पैसा लुटाया जा रहा है।

इसी तरह से ५६ के साल की दो महीने का औसत देखिये ८७८१) के लगभग रुपया दिया गया दो महीने में जब कि सन् ५३ में साल में १८६३४ रुपया कुल खर्च किया गया। उस साल भर का करीब करीब आधा रुपया हमने दो महीने में खर्च कर दिया। तो तीन गुना रुपया पिछले साल से ज्यादा अपने दैनिक को देने की कोशिश की जा रही है। यह समझ में नहीं आता इस तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? इतना ही नहीं विज्ञापन छापने में और मजाक की जाती है। जब बोर्ड का एक फार्म है।

(घंटी)

[श्री चन्दनमल वैद]

एक मिनिट और बोलूंगा उपाध्यक्ष महोदय, वह पूरा का पूरा फार्म नवजीवन में छपता है। मेरी समझ में नहीं आया जो फार्म लाखों की संख्या में छपाये गये, हर जिले में जल बोर्ड की ब्रांच को, पंचायत को, जिला आफिस को ये भेजे गये फिर उसी फार्म को अखबार में छपाये जाने का क्या मतलब है? एक फार्म और छपा है जागीरदारों के प्रतिदान के लिए। वह भी सारा नवजीवन में छपा है। इसकी पब्लिसिटी पंचायतों में भेज कर की जा सकती थी, हर कलेक्टर के यहां इसकी प्रति है, सरकारी गजट में यह आया हो चुका पर एक ही पेपर में उसे निकालने का क्या मतलब समझ में नहीं आया, फिर उसका सरकूलेशन भी कोई गांव गांव में हो ऐसी बात नहीं है, ये फार्म कलेक्टर के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। पर उन्हें तो पत्र को फायदा पहुँचाना था न उसने पूरे के पूरे पेज में उसे छापा और यह वह पेपर है जिसके बारे में मैंने अभी अभी काफी आंकडे प्रस्तुत किये हैं। तो सारे सदन के सदस्य और अच्छी तरह से देख लें और गृहमंत्री भी देख लें मैं इस दृष्टि से नवजीवन अखबार के दो अंक एक ५५ का और दूसरा ५६ का सदन की मेज पर रखता हूँ और रखते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल।

श्री उपाध्यक्ष—श्री व्यास।

श्री भैरू सिंह (दातां रामगढ़)—मेरा भी तो कटौती का एक प्रस्ताव है माननीय उपाध्यक्ष जी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने तो मूव कर दिया है साहब।

श्री उपाध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री भैरू सिंह—हरिकृष्ण व्यास तो बोल चुके हैं साहब। सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय पर बहस चल रही है। दूसरे प्रस्ताव बाद में लिये जावेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री राम किशोर व्यास—आपका कट मोशन तो मिला नहीं।

श्री वेदपाल त्यागी—सपोर्ट में ही बोल लो।

श्री भैरू सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सार्वजनिक सम्पर्क विभाग के सम्बन्ध में जो मांग इस सदन में प्रस्तुत की गई है उसके विषय में मेरा कटौती का प्रस्ताव है इस विभाग की अनिमितताओं के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये...

श्री उपाध्यक्ष—वह कट मोशन तो आपका डिसअलाऊ कर दिया गया।

श्री भैरूं सिंह—तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले मेरे पूर्व वक्ता ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसी का समर्थन करता हूँ।

श्री रामकिशोर व्यास—यह आप करें।

श्री भैरूं सिंह— माननीय उपाध्यक्षजी, जब कभी बाहर गांव में जाने का संयोग होता है और राजपूत होने के नाते कोई भांड या भांट किसी प्रकार की आकर तारीफ करता है चाहे मेरी जागीर पांच रुपये की हो लेकिन आमेर पति कहकर सम्बोधित करता है तो शर्म सी महसूस होती है। यह प्रथा कोई आज से नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही थी। जितने भी भांड होते थे उनका एक ही काम था कि मेरा अस्तित्व चाहे एक पैसे के बराबर हो पर जिस समय तारीफ की जाय तो लखपति बताए। इसके साथ दूसरी प्रकार की भी प्रथा थी और वह चारणों के द्वारा प्रतिपादित की जाती थी। जितने भी जागीरदार थे उनकी जहां एक तरफ ये भांट या भांड बेजा तारीफ किया करते थे, वहां दूसरा वर्ग ऐसा भी था जो उन जागीरदारों को उनकी सही स्थिति बताने का प्रयत्न किया करता था और वह वर्ग था चारणों का। जागीरदार धीरे धीरे इन भांडों की तारीफ के कारण से गिरते गये और आज वह दिन आगया कि जागीरदारी प्रथा समाप्त हो गई। चारण जब उनकी सही स्थिति का वर्णन करते थे तो उन पर ये जागीरदार रोष प्रकट करते थे और उनकी जमीन जायदाद जब्त भी कर लिया करते थे। उन बातों को आज जब याद करते हैं और इन बातों के साथ आज की सरकार की तुलना करते हैं तो ऐसा लगता है कि आज की सरकार भी उसी प्रकार की जागीरदारों की संस्था सी बनती जारही है। जो तारीफ करे उनकी हां में हां मिलावे उनको पसन्द आते हैं और उनको तरह तरह के इनाम दिये जाते हैं और जो आलोचना करते हैं उनको सजा मिलती है, इस सरकार का जब उदय हुआ तो इसके उदय के साथ साथ ही उनके भांटों और भाडों का भी उदय हुआ।

(हंसी)

इन भांडों के लिये नवयुग आया, नवजीवन आया, भांडों के लिये लोकजीवन आया भांडों के लिये लोक जीवन के साथ लोक जागरण, लोक जीवन इसी प्रकार की कई चीजें चलीं। इन मतवाले जागीरदारों के लिये इनकी बेजा तारीफ के लिये कई भांड पैदा हो गये। पर चारणों के नाम से शिकार हुआ राष्ट्रदूत। चारणों के नाम से दूसरी पार्टीज के पत्र चलते हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं वे शिकार होना शुरू हो गये हैं उन मतवाले जागीरदारों का। पहले जागीरदार चारणों की जमीनें छीना करते थे। आज इन मतवाले जागीरदारों ने छोटे छोटे अखबारों पर अपने हथियार चलाना शुरू कर दिये। एक दफा नहीं इस सदन में कई दफा चर्चाऐं हुई हैं। सदन के बाहर भी कई बार चर्चाऐं हुई हैं। जहां प्रजातान्त्रिक सिद्वान्तों के आधार पर सरकार पर नियन्त्रण करना चाहते हैं, सरकार के प्रशासनिक कामों की

[श्री भैरूंसिंह]

ठीक व्यवस्था करना चाहते हैं वहां यह भी सोचना पड़ेगा कि प्रजातन्त्र के जो मूलभूत सिद्धान्तों है उन सिद्धान्तों को वे कहीं आघात तो नहीं कर रहे है। यदि इस बात का अवलोकन हमें स्पष्ट रूप से कहीं मिलताहै तो राजस्थान सरकार की विज्ञापन संबंधी जो नीति है उस नीति के अन्दर उसकी झलक मिलती है माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक इन समाचारपत्रों का प्रश्न है इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि जो पत्र सरकार की आलोचना करते हैं उन्हें किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं मिलता है। आज कोई इस बात से इन्कार नहीं कर सकता है कि जो सरकार की तारीफ करने वाले पत्रों को सबसे ज्यादा विज्ञापन दिये जाते हैं। विज्ञापन देने का प्रश्न आया तो उसके बारे में यदि नियम हों और उन नियम में ऐसा हो कि राजस्थान सरकार की जो आलोचना करते हैं उन पत्रों को विज्ञापन न दिया जाय और सरकार की तारीफ करें तो तारीफ करने वाले पत्रों को ज्यादा तादाद में विज्ञापन देगें और विज्ञापन द्वारा ज्यादा से ज्यादा सहायता करेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम यह मानकर चलेंगे कि उनका नियम इस प्रकार का है और इस प्रकार से अगर सरकार ऐसा करती है तो वह उनके नियम के अन्दर है, लेकिन जब कोई नियम नहीं है और नियम नहीं होने की सूरत में परम्परा यह बताती है कि निष्पक्ष व्यवहार के साथ विज्ञापन संबंधी नीति अपनायें।

विज्ञापन देने में पक्षपात हो इसकी चिन्ता नहीं हैं, लेकिन विज्ञापन की रेट्स में ऐसा पक्षपात होता है तो हम ऐसा समझते हैं कि सरकार जनता की परिश्रम से कमाई हुई जो धनराशि है उस धनराशि का स्पष्ट रूप से दुरुपयोग करती है। जितनी विज्ञापन की दरें है उनको देखा जाय तो बाजार में कमर्शियल बेसिस पर काम करने वाले व्यापारी हैं या जितने बिजीनेस सेन्टर्स हैं यदि हम उनसे पूछें तो हमें पता लगेगा कि उनके रेट्स किसी कालम के लिए १।। रु० या २ रु० ज्यादे में ज्यादा होता है, और उसी दिशा में सिनेमा वालों से जाकर पूछें तो सिनेमा वाले यह कहेंगे कि विज्ञापन में चाहे किसी एक्ट्रेस का फोटो दिया गया हो या एक्टर का फोटो दिया गया हो या एक फिल्म के बारे में कोई विशेष जिक्र किया गया हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, एक कालम के हिसाब से १० आने की रेट पर विज्ञापन करते हैं। राजस्थान सरकार अजीबो-गरीब की हालत से गुजर रही है। वहां तो ७, ७ रु० की रेट के ऊपर एक एक कालम के विज्ञापन दिये जाते हैं। यह समझ में नहीं आता कि जब बिजीनेस सेन्टर्स के ऊपर जितने बिजीनस मेन हैं वह डेढ़ रुपये में उसी पत्र के अन्दर जिस पत्र के अन्दर सरकार विज्ञापन निकलवाना चाहती है निकलवाता है और सिनेमा वालों से उन्हें १० आने में ही मिलते हैं तो राजस्थान सरकार जब ७, ७ रु० कालम विज्ञापन के हिसाब से विज्ञापन कराये तो मैं समझता हूं कि उसमें औचित्य नजर आता हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष, सरकार मे कई पत्रों के लिए अपनी सरकारी मशीनरी लगा दी है। मुझे 'नवयुग' से कोई द्वेष हो ऐसी बात नहीं है किसी समाचार पत्र को सरकार विशेष रूप से प्रोटेक्शन दे, इस प्रकार की जो नीति है उस नीति का विरोधी हूँ। सरकार अपने विभागों के उच्चाधिकारी हैं उनसे परामर्श करके सरक्यूलर इश्यू कराने में एक सरक्यूलर एजूकेशन

डिपार्टमेंट से इशू हुआ है उस सरक्यूलर के मुताबिक २४ रुपये सालाना के हिसाब से दूसरे लोगों को मिल सकता है एजूकेशन डिपार्टमेंट उसी नवयुग को ३० रुपये वार्षिक धनराशि पर लेने के लिए एजूकेशन डिपार्टमेंट के एक विभागीय अधिकारी ने इस प्रकार के आदेश जारी किये हैं कि स्कूलों के अन्दर नवयुग को मंगाया जाय। एजूकेशन डिपार्टमेंट में ही इस तरह की बात होती हो तो ऐसा सन्तोष शायद किया जा सकता था कि एक डिपार्टमेंट ही इस प्रकार का प्रचार कर रहा है, लेकिन यदि पंचायत विभाग को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पंचायत विभाग ने एक विज्ञप्ति के जरिये, आर्डर के जरिये, नहीं, दिनांक १६. ५. ५५ का एक आर्डर निकाला है कि:—

"जयपुर से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्रों के अनुसार स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, की आज्ञा संख्या ६२४। एल. एस. जी. डी.।५५, दिनांक १९-५-५५, मान्यता दी जा चुकी है। पंचायत पुस्तकालय अथवा वाचनालय इस दैनिक पत्र को अपने यहां २४ रु० वार्षिक शुल्क मनी आॅर्डर द्वारा भेजकर मंगाने का प्रबन्ध करें।

चाहे पंचायत की हालत मंगाने की हो या न हो, चाहे वह चन्दा करे या पंचायत गरीब जनता पर टेक्स लगाये लेकिन नवयुग मगाये और मिनिस्टरों का फोटो देखे और उसमें मिनिस्टरों की तारीफ के संवाद जो आते हैं उन संवादों को पढ़े और अपनी लियाकत को बढ़ाये।

आज नवयुग के लिए ही लिखा है क्योंकि वह सरकार का साथी बनकर आया है और उसका प्रचार सरकार करे तो ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन यह सरकार एक दूसरे समाचार पत्र के लिए लिखती है कि:—

"कांकरोली से प्रकाशित होने वाला पंचायत मांग, मासिक पत्र, को राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए आदेश संख्या ५०१० । एल. एस. जी. डी.। ५२ दिनांक ३१-७-५५ द्वारा मान्यता प्रदान की है। अतएव इस समाचार पत्र को पंचायतें अपनी आर्थिक स्थिति को दृष्टिकोण में रखते हुए मंगवायें।" इसको भी मंगवाये। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण की बात हो या नहीं वह लिखने की बात है, लेकिन पंचायतों को ऐसा लिखा दिया है कि उसको मंगाने का प्रबन्ध करिये। आर्थिक स्थिति को दृष्टिकोण में रखते हुए ये शब्द होते हुए भी प्रबन्ध मरजी से करें ऐसा नहीं है लेकिन सरकार जबरदस्ती मंगाये जाने का प्रबन्ध करवाना चाहती है, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में एक दूसरे सरक्यूलर में लिखा नहीं है उसके लिए मैं यह समझूंगा कि दूसरे पत्र को जबरदस्ती मंगाने की सरकार ने व्यवस्था की है। वह दूसरा पत्र 'कांग्रेस सन्देश' है। पंचायत विभाग की ७-१२-५२ की एक विज्ञप्ति है कि:—

"जयपुर से प्रकाशित होने वाले सप्ताहिक 'कांग्रेस सन्देश' को राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए आदेश संख्या १५४५३। एल. एस. जी. डी.। ५३, दिनांक ७-१०-५३ द्वारा स्वीकार कर लिया है। अतएव इस पत्र को पंचायतें मंगवाने का प्रबन्ध करें।"

[श्री भैंरूसिंह]

इसमें आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण का कोई उल्लेख नहीं है। मैं इस बात को मानकर चलूंगा कि जहां आर्थिक स्थिति को दृष्टिकोण में रखकर पंचायतें किसी पत्र को खरीदें इस बात की सुविधा सरकार प्रदान करती है वहां उस बात का उल्लेख करना बिलकुल आवश्यक है कि आर्थिक स्थिति को दृष्टिकोण में रखते हुए मंगायें। जहां यह संभव हो वहां इस बात की मान्यता देनी पड़ेगी कि सरकार मजबूर करेगी कि कांग्रेस संदेश और नवयुग अखबार दोनों को मंगायें चाहे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो, और आर्थिक स्थिति में चाहे उनके पास एक पैसा भी नहीं हो, लेकिन कहीं न कहीं से लूट खसोट करके, जुर्माना करके, या चन्दा मांग करके कुछ भी बात करके कांग्रेस संदेश को शुरू कर दें उनके पास भेजना जो कि सरकार का प्रचार करता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक विज्ञापन संबंधी सरकार की नीति है वह बहुत ही एतराज के काबिल है। लेकिन इतना सा ही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात का उल्लेख, माननीय उपाध्यक्ष, मैं और आपके समक्ष करूंगा कि जहां तक इन अखबारों का प्रश्न आता है वहां एक प्रकार कि नीति हमारे सामने देखने को मिलती है कि राजस्थान के अखबारों को प्रोटेक्शन मिलता है। उनको विज्ञापन दिया जाता है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वहां किसी न किसी रूप में सही हो सकता है कि वह अखबार राजस्थान के हैं। जिस प्रकार का प्रकाशन उस अखबार के द्वारा करवाना चाहते हैं उनका राजस्थान में सरक्यूलर होने के कारण राजस्थान के कोने कोने में वह पहुँच सकें। लेकिन राजस्थान के कुछ विज्ञापन हम मद्रास के अखबारों में देते हैं या दिल्ली के अखबारों में देते हैं तो मेरी समझ में सिवाय इसके कुछ नहीं आता है कि हम मद्रास और दिल्ली के अखबार में जिनके कारण से राजस्थान की बुराइयां यदि राजस्थान के बाहर के क्षेत्रों में पहुँच सके या उनके ऊपर बन्धन डालने के लिए हम उनको कुछ दें विज्ञापन के रूप में या प्रकाशन के रूप में या खुशामद के रूप में कुछ पैसा देदें विज्ञापन दिलवाकर या और किसी प्रकार से कि जिससे किसी प्रकार से शायद जो बुराइयां राजस्थान के बाहर होने वाली हैं वे न हो सकें तो यह उचित न होगा।........

यदि इस दृष्टिकोण से मद्रासवाले अखबारों को, और दिल्ली में जितने पत्र सरकुलेट होते हैं उनको विज्ञापन दिये जाते हैं, तो यह सरकार की कमजोरियों को छिपाने के लिये सरकार द्वारा जनता के पैसे को उन लोगों को रिश्वत के रूप में देना है, मैं समझता हूँ इसके सिवाय दूसरी वह चीज नहीं होगी। जितने भी राजस्थान के कोने-कोने में समाचार-पत्रों द्वारा राजस्थान सरकार के काले कारनामे या अच्छे काम समाचार पत्रों द्वारा पहुँचने देने में, राजस्थान के अलग-अलग कोनों में पहुँचा देने के सम्बन्ध में, इस सरकार ने हिन्दी और अँग्रेजी के पत्रों में विज्ञापन देने में पत्रों को सुविधाएँ देने में एक असमानता बना रखी है। राजस्थान के कोने-कोने में पहुंचनेवाले पत्र को अधिकारियों के द्वारा आज्ञायें जारी की गई हैं, सूचनाएँ भेजना है, राजस्थान के अन्दर जितने हिन्दी पत्र हैं जिनका राजस्थान के बाहर सर्कुलेशन ज्यादा नहीं है, उनको अधिक से अधिक

[श्री भैंरूसिंह]

सुविधायें प्रदान करनी चाहिए, इससे मेरा यह मतलब नहीं है कि अंग्रेजी पत्रों को न दी जाय लेकिन जो पत्रकारिता की नीति समान ढंग पर आधारित होनी चाहिए, समान ढंग पर सहूलियतें प्रदान करनी चाहिए और अगर समान ढंग पर सहूलियतें प्रदान राजस्थान सरकार नहीं करती है, इस बात की शंका है, भय है कि राजस्थान में तो इस तरह का देखने को मिल गया कि हम काफी बदनाम हैं, राजस्थान ने डाकू बता दिया, भ्रष्ट बता दिया, राजस्थान के पत्रों ने जितनी आलोचना करनी थी करदी लेकिन उन पत्रों के सरकुलेशन को राजस्थान के बाहर क्यों भेजा जाय। जो बकते हैं उनको बकने दें और जिन पत्रों का सरकुलेशन राजस्थान के बाहर है उनको सुविधाएं देकर, उनको खुश कर सकें तो वे हमारे राजस्थान के बाहर हमारे काले कारनामों को अखबारों में छापेंगे नहीं। लेकिन अंग्रेजी अखबार वालों को धन्यवाद है कि उनको राजस्थान सरकार की इस नीति ने आकर्षित नहीं किया और जो राजस्थान सरकार के काले कारनामे हैं वे अंग्रेजी अखबारों में भी एपीयर होते हैं और राजस्थान की जनता ही नहीं किन्तु बाहरवाले भी राजस्थान सरकार के काले कारनामों को देखते हैं और उनकी चर्चायें कभी-कभी राजस्थान के बाहर भी होती हैं।

(घण्टी)

मैं और बोलना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय !

श्री उपाध्यक्ष—आप काफी बोल चुके हैं। आपका कट मोशन नहीं है।

श्री भैरूँ सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना कट मोशन समय पर तो दे दिया था लेकिन न मालूम क्यों नहीं लिया गया ? मैं पांच मिनट में ही कह दूंगा। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी सूरत में हमें सोचना पड़ेगा कि........

श्री उपाध्यक्ष—दो मिनिट में जल्दी कह दीजिये।

श्री भैरूँ सिंह—तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि वैसी सूरत में हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम किसी भी पत्र को किसी भी प्रकार से संरक्षण दें उस समय एक दृष्टिकोण अपनायें कि उस पत्र को जो संरक्षण प्रदान कर रहे हैं उस संरक्षण के कारण वह पत्र कहीं अनुचित फायदा तो नहीं उठायगा और उस संरक्षण के कारण दूसरे पत्रों में असमानता का व्यवहार तो नहीं होगा। अगर ऐसी नीति रही तो हम पत्रकारिता के साथ न्यायोचित कार्य करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसी तरह का उचित काम करने वाली सरकार कहा जाय तो इसमें शंका होगी। विज्ञापन का ही यह हो ऐसा नहीं है लेकिन जो छोटी-छोटी पुस्तकें छपवायी गई, पीरियोडिकल्स हैं या यों कहूं कि सरकार के राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड या अन्य कार्यवाहियां उनको सारी जनता के सामने लाया जाय उसके लिए छोटी-छोटी पुस्तकें छपाई गई। आज तक ऐसा होता था कि सब प्रकार की छपाई राजस्थान सरकार के गवर्नमेन्ट प्रेस से कराई जाय और अगर गवर्नमेन्ट प्रेस नहीं छाप सके तो बाहर के प्रेसों से सारा का सारा काम छपवाया जाय। लेकिन बदकिस्मती है राजस्थान की इस

[श्री भैरूसिंह]

विषय में भी। आपने देखा होगा उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९५३ में १३ किताबें छपी, ५४ में १६ और सन ५५ में १७ छपी। छपाई में विशेष कोई आफत हो ऐसी बात नहीं। गवर्नमेन्ट प्रेस से छपवाई जाती तो भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन ये पुस्तकें जब गवर्नमेन्ट प्रेस से सन् १९५३ में छपवाई उस समय ६। परसेन्ट दूसरों को दी और जब ५४ में छपवाई तो ४९ परसेन्ट बढ़ गई और १९५५ में वह ७० परसेंट बढ गई। इस तरह बाहरवालों को ५३ में ६। परसेंट, दूसरी बार छपवायी ५४ में तो बाहरवाले प्रेस को ४९ और तीसरी बार फिर ७३ परसेंट तक। क्या गवर्नरमेंट प्रेस बेकार हो गया था ? गवर्नरमेंट प्रेस काम कर सकता है या नहीं कर सकता है उस समय इसकी जानकारी हो सकती है सरकार का कोई भी विभाग किसी प्रकार की छपाई का काम कराये तो गवर्नमेंट प्रेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है तो उससे नोनअवेलेबिलिटी का सर्टिफिकेट ले ले, गवर्नमेंट प्रेस यह सर्टिफिकेट दे दे कि हमें फुरसत नहीं है कि हम छपाई कर सकते हैं और उस सूरत में बाहर के प्रेस से छपाई जाय। लेकिन गवर्नमेंट. प्रेस को कोई पूछता नहीं है, गवर्नमेंट प्रेस से सर्टिफिकेट लेते नहीं हैं। लेकिन होता क्या है कि गवर्नमेंट प्रेस से पूछा जाता है कि क्या दो तीन दिन में यह मेटर छाप कर दे सकते हो और अगर नहीं दे सकते हो तो बाहर से छपवायेगें। जब गवर्नमेंट प्रेस को तो दो तीन दिन का नोटिस दे दिया जाता मैं और अन्दर से दूसरे पेसवालों को कहा जाता है कि किताबें छाप कर तैयार रखो दो तीन दिन का नोटिस समाप्त होते ही हम तुमको बुला लेगें। जब गवर्नमेंट प्रेस इनकार करता है और जिस प्रेस का पत्र लिया जाता है उसको तीन दिन के नोटिस में किताबें छापने के लिए मंजूरी दे दी जाती हैं और किताबें छप जाती हैं। यह युनाइटेड प्रिन्टर्स प्रेस जयपुर का है। उस प्रेस का भी यह हाल है कि यदि आपको दूसरे प्रेस को छपाई देनी है, किसी दूसरेप्रेस से यदि छपाई करानी है तो उस काम के लिए टेण्डर्स इन्वाइट करें और कंपीटीटिव रेट्स मांगे कि अमुक छपाई इस प्रकार की चाहिये, अमुक तरह का कागज चाहिए, इसका मारड ऐसा होना चाहिए, और इस प्रकार के स्पेसिफेक्शन्स देकर टेन्डर्स मांगें और उसके बाद जिस किसी भी प्रेस को यह छपाई दे तो यह उचित हो सकता है लेकिन केवल शार्ट नोटिस के अन्दर ही, बिना स्पेसिफिकेशन्स दिये, शार्ट नोटिस में भी काम पूरा हो या न हो लेकिन फायदा पहुँचाना चाहते हैं। और सिवाय एक प्रेस के दूसरा कोई प्रेस नहीं जिसको कि सबसे ज्यादा फायदा पहुँचाना चाहते हैं वह युनाटेड प्रिन्टर्स। उसने अनाप शनाप पैसा ले लिया, चाहे छपाई कैसी भी हो, इन मन्त्रियों को खुश करना चाहते हैं, इन मन्त्रियों के सहयोग से, इन मन्त्रियों के अखबारों में फोटो छपें उनको बधाई देने के नाते यह किया जाता है, ऐसी सूरत में उपाध्यक्ष महोदय,

(घंटी)

यह जो सरकार की नीति है वह प्रजातान्त्रिक उसूलों पर चलने वाली सरकार की नीति नहीं है, यह जो सरकार की नीति है वह डेमोक्रेसी के आधार पर चलने वाली सरकार की नीति नहीं है। वह तो मैं कहूँ कि जैसे उधर बैठने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हमारी सरकार नाजीवादी है और मैं यह कहूँगा कि यह फासिस्ट मनोवृत्ति को लेकर है और जो फासिस्ट मनोवृत्ति है

[श्री भैरूसिंह]

उससे लोगों की विचार स्वतन्त्रता पर, लोगों को विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता है, पत्रों को विचार करने की स्वतन्त्रता है उन पर कुठाराघात कर रही है, इस प्रकार का कुठाराघात करके लोगों की विचार स्वतन्त्रता का हनन कर रही है। ऐसे पत्र हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं, सही बातें लिखते हैं, वे सरकारके अप्रिय हैं उनको आघात पहुँचाये, उनको खत्म करने की कोशिश करें तो क्या डेमोक्रेसि पर आधारित राज्य के लिए शोभा की बात है? अगर माननीय गृह मन्त्रीजी कह दें कि हमारी सरकार फासिस्ट है और डेमोक्रेसी उसूल पर नहीं है इस मामले में तो मैं आपका कटौती का प्रस्ताव वापिस ले लूंगा और माननीय सदस्य फासिस्ट सरकार के सामने डेमोक्रेटिक स्पीचेज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वापिस ले लेना लेकिन जहां हम डेमोक्रेसी की

(घंटी) (घंटी)

बातें करते हैं, समाजवाद और सोशलिस्टिक पेटर्न की बातें करते हैं वहां अगर इस प्रकार की विचार स्वतन्त्रता पर कुठाराघात होता हो, विचारों का हनन होता हो, इस प्रकार की भेदभाव पूर्ण नीति बरती जाती हो उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए

(घंटी)

हमें सोचना पड़ेगा कि यह प्रजातान्त्रिक राज्य है अथवा फासिस्ट है। यह कह कर मैं माननीय गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इन बातों का जब वे उत्तर दें तो सारी बातों को ध्यान में रखें और विश्वास दिला दें कि उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा कोई अन्याय नहीं होगा और जो भी विज्ञापन होंगे उनका समानता के साथ वितरण होगा और सूचना देते रहेंगे।

(घंटी, घंटी)

मुझे एक मिनिट में एक बात और कहनी है।

अभी कुछ विज्ञापन का जिक्र किया गया था। विज्ञापन पत्रों में.....

श्री उपाध्यक्ष—अगर विज्ञापन की कोई बात

श्री भैरूसिंह—ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—अब औरों को कहने दीजिये।

श्री भैरूसिंह—मैं यह निवेदन कर रहा था कि आयन्दा सब के बारेमें चर्चा हुई है उनके बारे में विशेष ध्यान देकर....

श्री उपाध्यक्ष—Order please !

श्री उपाध्यक्ष—श्री छीतरलाल

श्री वेदपाल त्यागी—इस विषय में मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं।

श्री कस्तूरचन्द जैन—मैं इसके विरोध में कुछ बोलना चाहता हूँ। मुझे एक मिनिट दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा सिर्फ एक मिनिट दिया जाता है।

श्री किस्तूरचन्द जैन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय लायक श्री चन्दनमलजी का कटौती का प्रस्ताव इस पत्र के विज्ञापनों के बारे में रखा गया है उसका मैं समर्थन नहीं विरोध....

श्री चन्दनमल वैद—सही बात होती है वह मुंह से निकल जाती है।

श्री हिम्मत सिंह—समर्थन हो गया।

श्री कस्तूरचन्द जैन—समर्थन नहीं विरोध करना चाहता हूँ। अभी दो चार भाषण सुनने को मिले उनसे यह पता चल गया कि एक मित्र उदयपुर के विरोध में मालुम पड़े। मुझे समझ में नहीं आया कि यह विरोध इस असेंबली में क्यों चल रहा है। जैसा कि अभी साथी ने बताया था कि एक नवजीवन पत्र है वह सरकार का भांड, भगुआ या न मालूम क्या क्या कहा गया। इस तरह की बातें जब उनके मुंह से निकलती है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस तरह का एक पत्र पर लोगों का आचरण क्यों हुआ है। अभी हमारे साथी चन्दनमल जी

श्री हिम्मतसिंह—एक मिनिट हो गया है।

श्री चन्दनमल—मेरे मित्र हैं, कहने दीजिये।

श्री कस्तूरचन्द जैन—अभी मेरे मित्र के द्वारा जो एक्शन हो गया। मेरी अर्ज यह है कि अभी फिर बताया था कि कितना गंदा, अन्धा धुन्ध छपा है, दिखता नहीं है। मैं कहता हूँ कि नवजीवन कितना साफ साफ नजर आता है, कितनी सुन्दर छपाई है। और कितना अच्छा कागज है।

श्री मानसिंह महार—इस पत्र में माननीय सदस्य की फोटू छपी है या नहीं ?

श्री भैरूसिंह—फोटो तो नहीं लेकिन लकड़ियें चुराने का नतीजा छपा है।

श्री कस्तूरचन्द जैन—(जारी) इतना सुन्दर कागज है, सुन्दर और साफ फोटो छपा है फिर भी इसके बारे में बताया जाता है कि नवजीवन काला कलूटा, भद्दा अन्धा धुन्ध छपा

[श्री किस्तूरचन्द जैन]

है राजप्रमुख का फोटो है या जानवर का ऐसी बातें बतला कर लोगों की निगाह पर परदा डालना चाहते हैं। इतनी आलोचना करना मैं समझता हूं गलत बात है। नीति लोगों की शुद्ध और साफ होनी चाहिये। और जो नवजीवन पत्र निकलता है उसमें राजस्थान की शुद्ध और ईमानदारी से खबरें निकलती है उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिये। मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूँ........

श्री चंदनमल वैद—अपने आप को धन्यवाद देते हैं ?

श्री किस्तूरचन्द जैन—उन को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे पत्र को सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिये। आलोचना की दृष्टि से आप कुछ भी कह दें। इस पत्र के मेरिट को देख कर विज्ञापन दिये जाते हैं। कोई टेन्डर वेन्डर की बात नहीं है। यह पत्र सच्ची और ईमानदार बातें देता है। मैं समझता हूं कि किस वजह से आप आलोचना करते हैं सारा हाउस और राजस्थान जानता है।

श्री मानसिंह महार—आपके पास यह अखबार कौनसी तारीख का है।

श्री किस्तूरचन्द जैन—तारीख १-१-५६ का।

श्री कंवरलाल जेलिया—आप का फोटो इसमें कितनी बार छपा है ?

श्री किस्तूरचन्द जैन—मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कितने अंकों में से एक अंक छांट कर लाये हैं। दो तीन हजार में एक दो निकले होंगे।

श्री वेदपाल त्यागी—मुझे भी इस बारे में बोलना है लेकिन आज समय कम हो गया है कल बोलूंगा।

श्री भोलानाथ—मुझे एक मिनिट के लिए ही कुछ कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस एडवर्टाइज़मेंट के बारे में जो बातें कही गई हैं उनसे यह जरूर मालूम होता है कि इस प्रकार के एडवरटाइजमेंट देने से जिस प्रकार की नीति बरती जाती है वह पब्लिक मनी का स्केन्डल है। यह मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, इसकी वजह यह है कि एक अखबार नया शुरू हुआ कलकत्ते में 'विशाल राजस्थान'। इस अखबार के पहले ही अंक में फुल पेज का एडवर्टाइज़मेंट छपा है। यह एडवरटाइजमेंट राजस्थान सरकार की ओर से दिया गया। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जवाब देने के लिये जब गृह मन्त्रीजी खड़े हों तो इस अखबार को

[श्री भोलानाथ]

भी लावें। कलकत्ता जो हिन्दुस्तान की राजधानी रहा है और आज भी सबसे बड़ा शहर है। वहां से अमृतबाजार पत्रिका आदि कई बड़े बड़े अखबार रोज निकलते हैं इसके अलावा अन्य जगहों से उनके कई संस्करण रोजाना निकलते हैं। वैसे अखबारों को एडवर्टाइजमेंट न देकर "विशाल राजस्थान" जैसे अखबार के पहले ही अंक को फुल पेज का एडवर्टाइजमेंट देना कहां तक उचित है? इस अखबार के पहले पेज पर फोटो और लास्ट पेज पर फुल पेज का विज्ञापन छपा है। यह कैसे हुआ? क्या आपको ख्वाब आया था कि यह अखबार निकलने वाला है। राजस्थान के अखबारों के प्रति स्टेप मदरली ट्रीटमेंट की काफी चर्चा हो चुकी है। सुखाड़ियाजी की कलकत्ता विजीट के बाद जब जल बोर्ड के लिए पैसा आता है तो वहां से वापिस आने के बाद एक अखबार निकाला जाता है विशाल राजस्थान के नाम से। कलकत्ता में आपको कौनसा दर्द पैदा हुआ और कौनसा ख्वाब आया कि वहां से यह अखबार निकलेगा ताकि पहले ही अंक में फुल पेज का एडवर्टाइजमेंट दिया गया। इसकी सफाई होनी चाहिये।

श्री चंदनमल वैद—अब तो ६ घंटे हो गये हैं, इसलिये हम सब थक गये हैं।

श्री जसवन्तसिंह—अब तो टाइम हो गया है साहब।

श्री उपाध्यक्ष—आज समय हो गया है इसलिए सदन की बैठक कल दिनांक २१-३-५६ को ११ बजे प्रातः तक के लिये स्थगित की जाती है।

[तत्पश्चात सदन की कार्यवाही ५ बजे सायं, कल दिनांक २१ मार्च, १९५६ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।]

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-२० मार्च, १९५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

(परिशिष्ट १)

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६१ का उत्तर देखिए)

सूची अध्यापकगण किशनगढ़ वृत जिनका फिक्सेशन सम्पूर्णतया नहीं हो सके हैं ।

क्रम संख्या	नाम अध्यापक	नाम स्कूल
१.	श्री अम्बालाल माथुर	मिडिल स्कूल पदमगंज
२.	श्री भंवरलाल शर्मा	मिडिल स्कूल किशनगढ़
३.	श्री लक्ष्मीनारायण	प्रा० स्कूल रामपालों
४.	श्री बिहारीलाल	प्रा० स्कूल व.वर
५.	श्री हरीराम	प्रा० स्कूल वरवर
६.	श्री श्याम सुन्दर	प्रा० स्कूल विहला
७.	श्री बजरंगदास	प्रा० स्कूल सावतसर
८.	श्री कल्याणमल	जे. टी. सी. पावटा, रलावदा
९.	श्री रामस्रूप	प्रा० स्कूल मिलाक्ट
१०.	श्री रामधन	प्रा० स्कूल सितारामजी
११.	श्री रामगोपाल	प्रा० स्कूल सिगारा
१२.	श्री रामनिवास	प्रा० स्कूल बरना
१३.	श्री देवालाल	प्रा० स्कूल बाम्बर सोदरी
१४.	श्री देवकृष्ण	प्रा० स्कूल स्थानान्तर कोटा डिवीजन
१५.	श्री जुगलकिशोर	प्रा० स्कूल टाकड़ा
१६.	श्री कैलाशलाल	प्रा० स्कूल टोकड़ा, जे. टी. सी. पावटा
१७.	श्री निरंजनलाल	प्रा० स्कूल मल्लू
१८.	श्री धनालाल	प्रा० स्कूल सलेमावादे
१९.	श्री चम्पालाल	प्रा० स्कूल छोटा नारायणा
२०.	श्री विजयचन्द	प्रा० स्कूल मल्लू
२१.	श्री लालचन्द	प्रा० स्कूल सावतसर
२२.	श्री भंवरलाल	प्रा० स्कूल मुहारू
२३.	श्री श्रीकिशन	स्थानान्तर दौसा विरत

क्रम संख्या	नाम अध्यापक	नाम स्कूल
२४.	श्री शिवसिंह	प्रा० स्कूल नौसर
२५.	श्री सोहनलाल	प्रा० सीरांज
२६.	श्री रामानन्द	मिदून
२७.	श्री मदनलाल सिंह	पीगलोर
२८.	श्री छीतरमल	मिलावट
२९.	श्री अब्दुलगफ्फार	सांपला
३०.	श्री हीरालाल	धसूल
३१.	श्री जहूर महारम्द	फतहगढ़
३२.	श्री मदनलाल	हिंगोनियां
३३.	श्री रतनलाल	हिंगोनियां
३४.	श्री मोहनलाल	फतहगढ़
३५.	श्री मदनलाल	फतहगढ़
३६.	श्री जमनालाल	फतहगढ़
३७.	श्री श्रीकृष्ण	कुपोल
३८.	श्री अलादीन काश्री	बोरदा
३९.	श्री वली मोहम्मद	मदनगंज
४०.	श्री मूलचन्द	कापला
४१.	श्री रामनिवास	टिकान्ली
४२.	श्री रामस्वरूप	स्थानान्तरण जि० फागी
४३.	श्री उम्रसिंह	ओरिया
४४.	श्री गुलाब मोहम्मद	भगवानपुरा
४५.	श्री देवकीनन्दन	रूपनगढ़
४६.	श्री लक्ष्मीनारायण	रलायता
४७.	श्री दिवाकर	छोटा साम्बा
४८.	श्री हरदेवदास	आंकोलिया
४९.	श्री गोकुलसिंह	नौशाल
५०.	श्री मदनगोपाल	दादिया
५१.	श्री हाथीराम	सरवाड़

Page No 128

क्रम संख्या	नाम अध्यापक	नाम स्कूल
५२.	श्री लादूराम	ममोसरय
५३.	श्री भंवरलाल	जे. टी. सी. पावटा सिरोज
५४.	श्री जमनालाल	देवपुरी
५५.	श्री जगदीश प्रसाद	मोदीत
५६.	श्री नृसिंहलाल	सांपटा
५७.	श्री मोहम्मद कासिम खां	बराइ
५८.	श्री मोहनलाल	करकेडी
५९.	श्री वेदव्रत	”
६०.	श्री बद्रीलाल	”
६१.	श्री ओंकार	”
६२.	श्री घासीलाल शर्मा	”
६३.	श्री बद्रीलाल जोशी	”
६४.	श्री चतुर्भुज	”
६५.	श्री घीसालाल	”
६६.	श्री कल्याण शर्मा	”
६७.	श्री सुगनलाल	”
६८.	श्री गोपीलाल	मि० स्कूल किशनगढ
६९.	श्री सोहनलाल	बराई
७०.	श्री मदनलाल भटनागर	मिडिल स्कूल सरवाड
७१.	श्री रतनलाल गुप्ता	सरवाड
७२.	श्री रामनिवास सोमा	सरवाड
७३.	श्री बंशीलाल शर्मा	सरवाड
७४.	श्री नाथूलाल जोदो	सरवाड
७५.	श्री राजमल पायक	सरवाड
७६.	श्री हरिप्रसाद	सरवाड

Page No 129

क्रम संख्या	नाम अध्यापक	नाम स्कूल
७७.	श्री जमनालाल	सरवाड़
७८.	श्री रामरतन	रूपनगढ़
७९.	श्री कल्याणसिंह	रूपनगढ़
८०.	श्री तेजपाल	रूपनगढ़
८१.	श्री चूनीलाल	रूपनगढ़
८२.	श्री नन्दलाल	रूपनगढ़

परिशिष्ट २

(प्रश्न संख्या १६६ से सम्बन्धित शेष सूची)

Statement showing one school on average population.

S. No.	Name of District,	Primary,	Middle.	High.
1.	Pali.	2368	20651	82607
2.	Nagaur.	2350	29301	69439
3.	Sirohi.	1914	26373	237362
4.	Jalore.	3063	38288	153155
5.	Barmer.	3483	36780	147122
6.	Jaisalmer.	2389	34247	102743
7.	Jaipur.	2059	15924	57106
8.	Kishangarh.			
9.	Sikar.	1987	11487	61616
10.	Jhunjhunu.	1851	15490	39211
11.	Bharatpur.	2105	16498	82490
12.	Alwar.	1890	9472	53874
13.	Sawai Madhopur.	1972	20680	109310
14.	Tonk.	1856	23585	80189
15.	Udaipur.	2411	25345	70072
16.	Bhilwara.	2217	20781	121226
17.	Chittor.	2277	26714	83960
18.	Dungarpur.	1792	17124	77060
19.	Banswara.	1773	22284	118853
20.	Kotah.	2267	14456	69654
21.	Bundi.	1453	16501	56103
22.	Jhalawar.	1771	16252	74762

परिशिष्ट•३

(कृपया प्रश्न संख्या १७८ का उत्तर देखिये)

पिछड़ी जाति कल्याण विभाग राजस्थान द्वारा संचालित राजकीय आदिवासी एवं विमुक्त जाति छात्रालयों की सूचि

क्रमांक	नाम छात्रावास	छात्र सं० निर्धारित	विजिट करने वाले अधिकारी का नाम व दिनांक		निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम व दिनांक	
१.	२.	३.	४.		५.	
१.	राजकीय आदिवासी छात्रालय उदयपुर	५० छात्र	१. श्री एल. एम. श्रीकान्त कमिश्नर ट्र० शि० का० शि० भारत सरकार, नई देहली	७-४-५५	१. श्री जगन्नाथसिंह जी मेहता संचालक पि. जा. क. वि. राजस्थान, जयपुर	७-४-५५
			२. श्री पी० सी० दवे असि. कमिश्नर शि० का० शि० ट्रा०, बड़ोदा	७-४-५५	२. श्री विशवेन्द्रनाथ सहायक अधिकारी, डूंगरपुर	१४-८-५५
			३. श्री एम० पी० कल्ला	२०-८-५५		
			४. श्री एम० पी० कल्ला	२५-११-५५		
			५. उद्योग निरीक्षक, जयपुर	२५-११-५५		
			६. सहायक प्रचार अधिकारी, उदयपुर	२५-११-५५		
			७. कमान्डेन्ट आफिसर नेशनल वालान्टर फोर्स, उदयपुर	२८-११-५५		
			८. श्री रामसिंह जी, संचालक समाज कल्याण विभाग, राजस्थान	२९-१२-५५		

क्रमांक	नाम छात्रावास	छात्र सं० निर्धारित	विजिट करने वाले अधिकारी का नाम व दिनांक		निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम व दिनांक	
१.	२.	३.	४.		५.	
२.	राजकीय आदिवासी छात्रालय, कोटड़ा	४० छात्र	१. श्री एल० एम० श्रीकान्त	८-४-५५	१, श्री एम० पी० कल्ला	१६-५-५५
			२. श्री पी० सी० दवे	८-४-५५	२. श्री जगन्नाथसिंह मेहता, संचालक पि० जा० क० वि० राजस्थान	८-४-५५
					३. श्री एम० पी० कल्ला	८-१२-५५
३.	राजकीय आदिवासी कन्या छात्रालय, खैरवाड़ा	२५ छात्राएं	१. श्री एल० एम० श्रीकान्त	६-४-५५	१. श्री एम० पी० कल्ला	१०-७-५४
			२. श्री पी० सी० दवे	६-४-५५	२. श्री एम० पी० कल्ला	१६-११-५४
			३. श्री तहसीलदार, खैरवाड़ा	२८-४-५५	३. श्री एम० पी० कल्ला	२६-३-५५
			४. श्री क्रिसचिन मिशिनरी	१८-४-५५	४. श्री जगन्नाथसिंह जी मेहता	६-४-५५
			५. पुनर्स्थापन्न निरीक्षक, खैरवाड़ा	५-२-५५	५. श्री एम० पी० कल्ला	६-४-५५
			६. छात्रालय व्यवस्थापक, उदयपुर	४-३-५५	६. श्रीमती चन्दरा भंडारी, लेडी वेलफेयर आफिसर, राजस्थान	६-११-५५
			७. कमान्डेन्ट भील क्रोप, खैरवाड़ा	३-६-५५		
			८. प्रधानाध्यापक, खैरवाड़ा	५-६-५५		
४.	राजकीय आदिवासी छात्रालय, सागवाड़ा	४० छात्र	१. श्री एल० एम० श्री कान्त	११-४-५५	१. श्री एम० पी० कल्ला	११-४-५५
			२. श्री पी० सी० दवे	११-४-५५	२. श्री जगन्नाथसिंह मेहता	११-४-५५
					३.	५-१-५५
					४. श्री एम० पी० कल्ला	५-१-५५
					५. श्री सहायक अधिकारी, डूंगरपुर	७-८-५५

क्रमांक	नाम छात्रावास	छात्र सं० निर्धारित	विजिट करने वाले अधिकारी का नाम व दिनांक		निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम व दिनांक	
१.	२.	३.	४.		५.	
५.	राजकीय आदिवासी छात्रालय, प्रतापगढ़	४० छात्र	१. श्री पी० सी० दवे	१५-४-५५	१. श्री एम० पी० कल्ला	१०-४-५४
					२. श्री एम० पी० कल्ला	१५-४-५५
					३. श्री समाज कल्याण निरिक्षक, उदयपुर	२७-४-५५
६.	राजकीय आदिवासी छात्रालय, बांसवाड़ा	४० छात्र	—	—	१. श्री एम० पी० कल्ला	२६-६-५४
					२. श्री एम० पी० कल्ला	१२-४-५५
					३. श्री समाज कल्याण निरीक्षक, बांसवाड़ा	४-४-५५
७.	राजकीय विमुक्त जाति छात्रालय, चित्तौड़गढ़	२५ छात्र	१. समाज कल्याण निरीक्षक, उदयपुर	१६-२-५५	१. श्री एम० पी० कल्ला	७-४-५५
			२. ,, ,, ,,	२५-४-५५	१. श्री जगन्नाथसिंह जी मेहता	७-४-५५
			३. ,, ,, ,,	१६-५-५५	३. उद्योग निरीक्षक, उदयपुर	६-६-५५
			४. ,, ,, ,,	६-६-५५	३. श्री एम० पी० कल्ला	७-१२-५५
			५. ,, ,, ,,	४-६-५५		
			६. ,, ,, ,,	२६-६-५५		
			७. ,, ,, ,,	२२-६-५५		
			८. ,, ,, ,,	७-१२-५५		
			९. श्री एल० एम श्रीकान्त	७-४-५५		
			१०. श्री पी० सी० दवे	७-४-५५		
८.	जोधपुर	४८ छात्र	—	—	—	—
९.	सिरोही	६ छात्र	—	—	—	नया खुला है
१०.	विमुक्त जाति छात्रावास, पाली	७ छात्र	—	—		—

स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावास सम्बन्धी जानकारी

क्रमांक	नाम छात्रावास	स्वीकृत छात्र सं०	स्वीकृत सहायता प्रति छात्र	निरीक्षक	दिनांक
१.	२.	३.	४.	५.	६.
१.	भील छात्रालय, बिजोलिया	२५	१५ रु० प्रति छात्र	१. श्री जटाशंकर श्रीमाली कूप निरीक्षक, डूंगरपुर	११-३-५५
				२. श्री भंवरलाल दोशी, कूप निरीक्षक, मांडलगढ़	१३-१२-५५
२.	बापा छात्रावास हीरावास फतहनगर।	२६	१५ रु० प्रति छात्र	१. प्रादेशिक अधिकारी, उदयपुर	३-८-५४
				२. सहायक अधिकारी, बांसवाड़ा	२-३-५५
				३. श्री जयसिंह मेहता, कल्याण निरीक्षक, उदयपुर	६-७-५५
				४. ,, ,, ,,	२६-११-५५
३.	बापा भील आश्रम, धूलेव	२५	१५ रु० प्रति छात्र	१. प्रादेशिक अधिकारी, उदयपुर	१७-११-५४ ६-१-५४
				२. श्री चांदमलजी जैन, कूप निरीक्षक, सागवाड़ी	७-३-५५
				३. श्री मदनगोपाल व्यास, पुनर्वास निरीक्षक	१२-५-५५
				४. प्रादेशिक, अधिकारी उदयपुर	१०-४-५५ ३-१२-५५ २०-१२-५५
४.	बागड़ विद्यापीठ, डूंगरपुर	२५	१५ रु० प्रति छात्र	१. श्री प्रभुदयाल गुप्ता कल्याण निरीक्षक. डूंगरपुर	१३-६-५५
५.	आदिवासी छात्रालय, सलुम्बर	२५	१५ रु० प्रति छात्र	१. श्री श्याम सुन्दर व्यास कल्याण निरीक्षक, सलुम्बर	५-३-५५ २८-११-५५
६.	आदिवासी छात्रालय, टीड़ी	२५	१५ रु० प्रति छात्र	१. श्री जयसिंह मेहता, कल्याण निरीक्षक, केन्द्र. सलुम्बर उदयपुर	२-१२-५५

७. श्री जवाहर छात्रावास, खैरवाड़ा	४०	१५ रु० प्रति छात्र	१. प्रादेशिक अधिकारी, उदयपुर	१३-७-५४ १६-११-५४ २६-३-५५ ६-४-५५
			२. श्री मदनगोपाल व्यास पुनर्वास निरीक्षक, डूंगरपुर	२६-११-५५
८. आदिवासी छात्रालय, गलियाकोट	२५	१५ रु० प्रति छात्र	१ श्री प्रभुलाल गुप्त, कल्याण निरीक्षक, डूंगरपुर	१०-३-५५
९. भील छात्रालय, सीमलवाड़ा	२५	१५ रु० प्रति छात्र	१. श्री मदनगोपाल व्यास, पुर्नवास निरीक्षक	१४-३-५५
			२. श्री प्रभुलाल गुप्त, कल्याण निरीक्षक, डूंगरपुर	३१-८-५५
१०. आदिवासी कन्या छात्रालय, सीमलवाड़ा	२८	१५ रु० प्रति छात्र	१. ,, ,,	२-७-५५
			२. प्रादेशिक अधिकारी, उदयपुर	२४-७-५५
११. आदिवासी छात्रालय, कानोड़	२५	१५ रु० प्रति छात्र	१. श्री श्याम सुन्दर व्यास कल्याण निरीक्षक, सलुम्बर	१९-११-५५
१२. आदिवासी छात्रालय, धरियावद	२५	१५ रु० प्रति छात्र	१. ,, ,,	१५-११-५५
१३. नूतन बापा छात्रालय, डूंगरपुर	५०	१५ रु० प्रति छात्र	१. श्री प्रभुलाल गुप्ता	१५-३-५५
१४. महिला आश्रम, भीलवाड़ा के अन्तर्गत आदिवासी कन्या छात्रालय	४०	३० रु० प्रति छात्र	१. श्री प्रभाकर शर्मा, वेलफेयर वर्कर, भीलवाड़ा	२-८-५५
			२. श्री मदनमोहन पालीवाल	३०-११-५५
१५. आदिवासी छात्रालय, बामीडोरा	२५	१५ रु० प्रति छात्र	१. श्री रमणीकलाल त्रिवेदी कूप निरीक्षक, बांसवाड़ा	६-३-६५
			२. कालूलाल मुखवाल, कल्याण निरीक्षक, बांसवाड़ा	१०-१२-५५

१६. आदिवासी छात्रालय, घाटोल			१. कालूलाल हुलवाल, कल्याण निरीक्षक, बांसवाड़ा १३-३-५५
१७. गाडोलिया लुहार छात्रावास, चित्तौड़गढ़	२५	१५ रु० प्रति छात्र	प्रादेशिक अधिकारी, उदयपुर ४-१२-५५
१८. आदिवासी छात्रालय, जोलाना	२५	१५ रु० प्रति छात्र	
१६. आदिवासी छात्रालय, बीछावाड़ा	२५	१५ रु० प्रति छात्र	
२०. आदिवासी छात्रालय, सज्जनगढ़	२५	१५ रु० प्रति छात्र	
२१. गांधी छात्रावास	३०		वेलफेयर वर्कर, झुंझुनूं १४-१०-५५ इन्सपेक्टर, जयपुर ७-१-५३
२२. बापा छात्रावास, झुंझुनूं	६१		१. श्री जगदीश प्रसाद, हा. इन्सपेक्टर १०-२-५५ २. श्री वेलफेयर वर्क, झुंझुनूं (१) १२-७-५५ ,, ,, (२) २२-१०-५५ ३. श्री भवानीसिंह, वेलफेयर इन्सपेक्टर २०-१२-५५ ४. श्री गोपीलाल माली, वेलफेयर इन्सपेक्टर, भरतपुर ४-१०-५५
२३. श्री कृष्ण छात्रावास, सीकर	३०	७५ प्रतिशत	१. श्री जगदीश प्रसाद, हा. इन्सपेक्टर ६-२-५५ २. वेलफेयर इन्सपेक्टर, भरतपुर, १०-६-५५
२४, गांधी छात्रावास, अमरसर	३०		१. श्री शम्भूदत्तजी शर्मा, ए. सहायक समाज कल्याण आफिसर २६-८-५५
२५. राज विद्या मन्दिर छात्रावास, शाहपुरा	२०		२. श्री वेलफेयर इन्सपेक्टर, भरतपुर ७-१०-५५

२६. ग्रामोत्थान विद्यापीठ, सांगरिया	२८	१५ रु० प्रति छात्र	१. श्री शिवकुमार शुक्ल, हाउसिंग इन्सपेक्टर ५-६-५५ २. श्री दवे साहब, रीजनल आफिस २५-६-५५ ३. श्री जगदीश प्रसाद, सीनियर हाउसिंग इन्सपेक्टर २५-६-५५
२७. विद्यार्थी आश्रम, राजगढ़	२२	१५ रु० प्रति छात्र	१. श्री कैलाश बहादुर माथुर १३-६-५५ प्रादेशिक अधिकारी स. २५-६-५५ क. का. बीकानेर ३०-११-५५ २. श्री शिवकुमार, हाउसिंग १३-६-५५ इन्सपेक्टर २५-६-५५ ३०-११-५५ ३. जगदीश प्रसाद, सि. हा. ई. ३०-८-५५

परिशिष्ट ४

(प्रश्न काल में न लिये जा सकने पर सदन की मेज पर रखे गये प्रश्नोत्तर)

१८१. (२५ । सी-आइ. एम.) **श्री तनसिंह, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १४८:**—क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान में किस २ स्थान पर पन चक्कियां लगाने का परीक्षण किया जा रहा है ?

(ख) इस योजना पर कुल कितना रूपया व्यय होगा और परीक्षण के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

उत्तर

१:—राजस्थान सरकार पन चक्कियां लगाने के लिये कोई परीक्षण नहीं कर रही है और न चालू वर्ष में ऐसी कोई योजना है ।

२:—यह प्रश्न ही नहीं उठता।

१८२. (३० । एम. एल. एम.) **श्री छीतरलाल शर्मा, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ३०:** क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या १८–१–५६ को ग्राम पंचायत अलोद तहसील हीन्डोली जिला बूंदी की पंचायत का चुनाव अपूर्ण रहा था ?

(ख) यदि हां, तो अपूर्ण रहने का क्या कारण था ?

(ग) क्या इस पंचायत के सरपन्च और उप-सरपन्च का चुनाव ५–२–५६ को होने के पश्चात चुनाव संपूर्ण हो गया है ?

(घ) यदि हां, तो क्या इस चुनाव के संपूर्ण होने की इत्तिला चीफ पंचायत आफिस में निर्वाचन अधिकारी पेश कर चुके है ?

(ङ) यदि हां, तो किस तारीख को और यदि नहीं, तो क्यों तथा सरकार द्वारा इस समय तक क्या कार्यवाही की गई हैं ?

(च) उपरोक्त चुनाव का नतीजा सरकार कब तक गजट में प्रकाशित करा देगी ?

उत्तर

क. जी हां । केवल सरपंच का चुनाव नहीं होने से ।

ख. सरपंच के चुनाव के समय वातावरण काफी शान्ति भंग करने वाला होगया जिससे चुनाव रोकना पडा ।

ग. जी हां ।

घ. जी हां ।

ङ. १५ फरवरी, १९५६ को । बाकी प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

च. नतीजा गजट में प्रकाशित होने के लिये भेजा जा चुका है ।

१८३. (२६ । भी. आइ. एम.) श्री तनसिंह, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १४८: क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान में अम्बर चर्खों के कितने शिक्षण केन्द्र हैं और वे कहां कहां है तथा प्रत्येक केन्द्र में कितने अम्बर चर्खे हैं ?

(ख) इन चर्खों की उपयोगिता को देखते हुए सरकार इनके उत्पादन के लिये क्या कदम उठा रही है ?

(ग) यदि सरकार स्वयं इनका उत्पादन नहीं कर रही है तो बाहर से कितने ऐसे चर्खे मंगाने की कार्यवाही चल रही है ?

(घ) अब और किन किन स्थानों पर ऐसे शिक्षण केन्द्र खोले जाने का सरकार विचार कर रही है ?

(ङ) क्या अम्बर चर्खे की उपादेयता और शिक्षण के लिये सरकार ने प्रदर्शन भी किये हैं ?

(च) यदि हां; तो कहां कहां ?

(छ) क्या अन्य स्थानों पर भी ऐसा प्रदर्शन करने का सरकार विचार कर रही है ? यदि यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

क. अखिल भारतीय खादी बोर्ड की ओर से राजस्थान में अम्बर प्रशिक्षण केन्द्र सिर्फ एक ही जगह ग्रामोद्योग विद्यालय, शिवदासपुरा में दिनांक १९-११-५५ से शुरु हुआ और ३-१-५६ तक डेढ़ मास रहा । ५ परिश्रमालय बांसा चौम, शाहपुरा, करौली, और उदयपुर में चलाये जा रहे हैं ।

ख. प्रत्येक परिश्रमायालय में ४० अम्बर चर्खे हैं ?

ग. हां। अम्बर चर्खा उत्पादन की दृष्टि से सरकार द्वरा संचालित मिस्त्री खाना राजस्थान खादी बोर्ड को दे दिया गया है। मास अप्रेल से इस कारखाने में अम्बर चर्खे बनाने की ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये २ कारीगर खादी बोर्ड की ओर से बाहर भेजे गये हैं। चौमू और गोविन्दगढ़ में भी अम्बर चरखा बनाने की योजना है।

घ. यह प्रश्न उपरोक्त :ग: भाग के बाद नहीं उठता।

ङ. यह राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के विचाराधीन है।

च. हां ?

छ. उपरोक्त ५ परिश्रमालय में भी इनका प्रदर्शन किया गया है। अभी गत मास हाथ कर्घा सप्ताह जो जयपुर शहर में मनाया गया था उसमें भी अम्बर चर्खे का प्रदर्शन लोगों की आम जानकारी के लिये किया गया था।

१८४. (५७। आर. एम.) श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ५६: क्या राजस्वी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) 'तहसील बसी और चाकसू व सांगानेर जिला जयपुर में इस वर्ष कितने कितने रुपये तकावी के रूप में कितने लोगों में वितरण किया गया ?

(ख) इनमें से कितने हरिजनों को कितनी कितनी तकावी मिली ? तहसीलवार बतलाई जावे।

उत्तर

(क) तहसील बस्सी के ५८ आदमियों को ५३५५० रुपये व तहसील चाकसू के २६ आदमियों को १४५०० रुपये व तहसील सांगानेर के १८ आदमियों को १५१०० रुपये तकावी के वितरित किये गए।

(ख) तहसील बस्सी में ४ हरिजनों को ४४०० रुपये, तहसील चाकसू में २ हरिजनों को १५०० रुपये, तहसील सांगानेर में १ हरिजनों को ५०० रुपये।

१८५. (३५। एम. एल. एम.) श्री भोपालसिंह, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर २०। क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) पंचायतों के वार्ड सन् १९५१ की जन गणना के आधार पर बनाये गये हैं या मौजूदा आबादी के आधार पर ?

(ख) क्या उपरोक्त वार्ड एक स्केल से बनाये हैं ? यदि हां, तो वह तादाद बताने की कृपा करें।

(ग) क्या सरकार डेगाणा व मेड़ता तहसीलों के गांववार वार्ड मय संख्या के सदन की टेबिल पर रखने की कृपा करेंगी ?

उत्तर

(क) पंचायतों के वार्ड सन् १९४१ की मर्दमशुमारी के अंक ध्यान में रखते हुए बनाये गये हैं।

(ख) जी नहीं। गांव की दूरी, आबादी, तथा जनता की सहुलियत, वार्डों को बांटने वाले मुस्तकिल मुकाम आदि को ध्यान में रखते हुये वार्ड बनाये गए हैं।

(ग) इसी के संलग्न है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

१८६. (२७। सी. आइ. एम.) श्री **हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री, एम. एल. ए. डिवीजन नम्बर ५६** क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजस्थान बैकवर्ड क्लासेज वेलफेयर विभाग में कितने वेलफेयर आफीसर्स, इन्सपेक्टर्स व कल्र्क हैं तथा उनमें से कितने हरिजन हैं ?

उत्तर

क. इस विभाग में ९ वैलफेयर आफिसर्स हैं। इनमें हरिजन कोई नहीं है।

ख. इस विभाग में ३२ इन्सपेक्टर्स हैं। इनमें हरिजन कोई नहीं है।

ग. इस विभाग में ६३ क्लर्क हैं जिसमें से दो क्लर्क हरिजन हैं।

घ. सरकार के आदेशानुसार रिक्त स्थानों पर रसद विभाग व कस्टम विभाग के व्यक्तियों

को नियुक्त करना आवश्यक था। जब तक कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति उपलब्ध हो सकता था नई नियुक्ति नहीं की जा सकती थी।

इसके अलावा विभाग में कनिष्ट लिपिकों की आवश्यकता थी जिन पर हरिजन नियुक्त किए जा सकते थे, लेकिन कोई हरिजन टाइप जानने वाला उपलब्ध नहीं हुआ।

ड. भविष्य में सरकार की नीति स्पष्ट है। सरकार ने जो आरक्षण विभिन्न राजकीय सेवाओं में दे रखा है योग्य व्यक्ति मिलने पर उन्हें अवसर दिया जाता है।

परिशिष्ठ ५

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन के पेज पर रखे गये)

१. (३८।आर. एम.) श्री केसरीसिंह, एम. एल. ए. (७५)—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

क. क्या सरकार ने लैन्ड एलोटमेन्ट कमेटियां जिलावार बना रखी है ? यदि हां, तो उनके सदस्य कौन २ हैं ?

ख. अब तक इन कमेटियों ने कितनी मीटिंग की और कितनी जमीन बांटी ?

ग. सबसे अधिक जमीन किसको और कितनी दी गई और सब से कम किसको, कितनी, कब और कहां पर दी गई ?

(उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ)